चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

सत्ता नहीं, भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण

पेज-6

अब तो मां का दूध भी ज़हर हो गया

पेज-7

पाकिस्तान की पोल खोल दी

पेज-11

साई की महिमा

पेज-12

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 16 मई-22 मई 2011 | मूल्य 5 रुपये

एक था ओसामा

चंगेज ख़ान हो या औरंगज़ेब, माओ हो या स्टालिन या फिर सावरकर, इतिहास की किताबों में इनके बारे में जो लिखा गया है और जो हक़ीक़त है, उसमें काफ़ी फ़र्क़ है. यह फ़र्क़ इसलिए है, क्योंकि इतिहास हमेशा विजेताओं का हुआ करता है या शासकों का, पराजित या शासितों का नहीं होता है. इतिहास तो वही लिखवा सकते हैं और लिखवाते हैं, जो विजेता होते हैं और जो सत्ता में होते हैं. ओसामा बिन लादेन का इतिहास अमेरिका लिख रहा है, क्योंकि वही विजेता है. इतिहास की किताबों में ओसामा बिन लादेन का नाम दुनिया के सबसे ख़तरनाक आतंकवादी के रूप में दर्ज होगा. यही इतिहास अमेरिका लिखेगा, यही दुनिया भर में प्रचारित होगा. लेकिन, जो लोग ओसामा को इस्लाम के लिए लड़ने वाला महान योद्धा मानते हैं, वैसा इतिहास कौन लिखेगा?

मनीष कुमार

सीढ़ियों पर अपनी जान बचाते दौड़ते, भागते और हांफते दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सांसद. कोई गिर रहा है, कोई दूसरे को धक्का दे रहा है. सब जान बचाकर भागने में लगे हैं. यह आंखों पर विश्वास करने वाला नजारा नहीं है. 9 सितंबर, 2001 से पहले यह कोई सोच भी नहीं सकता था कि अमेरिका के सांसद अपने ही संसद भवन से जान बचाकर इस तरह भागते हुए नज़र आएंगे. एक बार, दो बार नहीं, 2001 के बाद ऐसा नज़ारा कई बार देखा गया. 31 जनवरी, 2007 को तो हद ही हो गई. अमेरिका के बोस्टन शहर में किसी कंपनी ने प्रचार केलिए कई जगहों पर एलईडी बोर्ड लगा दिए. दूर से देखने में यह बम की तरह दिख रहे थे. ख़बर फैलते ही शहर पर सेना के हेलीकॉप्टर मंडराने लगे. टीवी पर लाइव दिखाया जाने लगा. शहर के लोग घरों में दुबक गए. लगा कि किसी सीरियल ब्लास्ट की योजना है. इस तरह की और भी घटनाएं कई अन्य शहरों में हुईं. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हादसे के बाद अमेरिका वासियों के दिलों में दहशत घर कर गई. अमेरिका का मिथक टूट गया. दुनिया का सबसे ताक़तवर देश, जिसके बारे में यह कहा जाता था कि उसकी भौगोलिक, सामरिक और राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि उस पर कोई हमला नहीं कर सकता, अपनी ही सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया.

यह मिथक तोड़ने का श्रेय ओसामा बिन मोहम्मद बिन अवद बिन लादेन को जाता है, जिसे हम दुनिया के सबसे ख़तरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के नाम से जानते हैं. ओसामा बिन लादेन एक आतंकी तो था, लेकिन उसने ऐसा काम किया, जिसे शक्तिशाली सोवियत रूस नहीं कर सका, जापान नहीं कर सका, हिटलर का जर्मनी नहीं कर सका. द्वितीय विश्वयुद्ध में भी किसी ने न्यूयॉर्क पर हमला करने की हिम्मत नहीं की. जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला ज़रूर किया, लेकिन यह मेन लैंड से दो हज़ार किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर समुद्र में एक टापू है. सामरिक दृष्टि से ओसामा बिन लादेन का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला इतिहास में अमेरिका पर हुआ सबसे बड़ा हमला है. ओसामा बिन लादेन ने पहली बार अमेरिका को यह एहसास दिलाया कि उसके शहर सुरक्षित नहीं हैं. वह एटलांटिक महासागर पार कर उसके शहरों को तबाह कर सकता है. ओसामा बिन लादेन का अमेरिका पर यह पहला हमला नहीं था. इससे पहले भी वह अमेरिकी दूतावासों और समुद्री जहाजों को निशाना बना चुका था, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले ने दुनिया का रंग ही बदल दिया. अंतरराष्ट्रीय राजनीति, आर्थिक व्यवस्था, नाटो की ज़िम्मेदारियां, रूस एवं चीन का विश्व राजनीति में हस्तक्षेप, पश्चिम एशिया के प्रति दुनिया का रवैया, इजरायल एवं फिलिस्तीन की लड़ाई और आतंकवाद के प्रति दुनिया का रवैया जैसी कई महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिनमें असरदार बदलाव आया. इन बदलावों की एक ही वजह थी, ओसामा बिन लादेन का अमेरिका पर हमला. ओसामा के हमले ने न सिर्फ़ अमेरिका को असुरक्षित क़रार दिया, साथ ही विश्व राजनीति भी बदल गई. इसके बाद दुनिया की सारी ताक़तें ओसामा बिन लादेन को ढूंढने निकल पड़ीं, लेकिन वह दस सालों तक अमेरिकी सेना को चकमा देता रहा. बीच-बीच में वह अपने आडियो और वीडियो टेप जारी कर देता, दुनिया को यह बताने के लिए कि वह जिंदा है. 2 मई, 2011 को पाकिस्तान के ऐबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सेना ने मार गिराया. अब सवाल यह है कि क्या ओसामा की मौत के साथ उसका अध्याय ख़त्म हो गया?

ओसामा बिन लादेन की मौत अलक़ायदा के मनोबल पर गहरा झटका है. ओसामा बिन लादेन दुनिया, ख़ासकर ग़ैर मुस्लिम देशों के लिए एक आतंकवादी था, लेकिन इसके साथ ही इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि वह एक करिश्माई नेता था. करोड़ों लोग उसे एक शानदार योद्धा मानते थे. ओसामा बिन लादेन के नाम से कौन वाकिफ नहीं है. दुनिया भर में बच्चे-बच्चे के मुंह पर ओसामा बिन लादेन का नाम है. करोड़ों लोगों के बीच ओसामा की पहचान यह है कि वह एक अरबपति था, जिसने इस्लाम के दुश्मनों से लड़ने के लिए दुनिया के सारे ऐशो-आराम त्याग दिए. ऐसे भी लोग हैं, जो ओसामा द्वारा की गई हत्याओं की निंदा करते हैं, साथ ही उसकी हिम्मत को दाद भी देते हैं कि वह अकेला ऐसा व्यक्ति था, जिसने अमेरिका से लोहा लिया. ओसामा ने जो किया, जिस तरह किया, उस पर मतभेद हो सकता है, लेकिन इस बात को कौन झुठला सकता है कि उसने धीरे-धीरे दुनिया भर में एक ऐसा संगठन तैयार कर दिया, जिससे बड़ी-बड़ी सरकारें सहम गईं.

> **"हमने यह दिखा दिया कि अमेरिका जो ठान लेता है, वह करके दिखाता है. यही हमारा इतिहास रहा है. चाहे अपने लोगों की समृद्धि सुनिश्चित करना हो या सारे नागरिकों को समान दर्जा देना, चाहे अपनी मान्यताओं को देश के बाहर संजोए रखना हो या फिर विश्व को एक बेहतर और सुरक्षित जगह बनाने के लिए क़ुर्बानी देना."**
>
> -बराक ओबामा, *अमेरिकी राष्ट्रपति*

ओसामा बिन लादेन कोई साधारण आतंकवादी नहीं था. वह अमेरिका विरोध का जीता-जागता प्रतीक बन चुका था. फिलिस्तीन का मामला हो या फिर अफ़ग़ानिस्तान और इराक़ का, अमेरिका ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया. तेल के लिए उसने पश्चिम एशिया की सरकारों के साथ मिलकर वहां के निवासियों को विमुख किया. इस्लामिक देशों के लोग अमेरिका के बारे में अच्छी राय नहीं रखते हैं, उसे दुश्मन मानते हैं. ओसामा बिन लादेन ऐसे ही लोगों का महानायक बनकर उभरा. यही वजह है कि दुनिया भर के मुस्लिम देशों में ओसामा के चाहने वाले मौजूद हैं. यही वजह है कि ओसामा की मौत के बाद उन लोगों ने खुलेआम नमाज अदा की. ओसामा बिन लादेन किसी व्यक्ति या आतंकवादी का नाम नहीं रह गया है. ओसामा एक आइडिया है. ओसामा बिन लादेन ने इस्लामिक समाज और ईसाई सभ्यता के बीच एक ऐसी लकीर खींच दी, जिसका असर पूरे विश्व में प्रत्यक्ष रूप से दिखा. क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बातें पहले से हो रही थीं, लेकिन ओसामा बिन लादेन ने इसे हक़ीक़त में बदल दिया. ऐसा विचार, जो यह मानता है कि अमेरिका और यूरोप इस्लामिक सभ्यता को तबाह करना चाहते हैं. उसने पश्चिम एशिया के लोगों को यह समझाया कि अमेरिका अपनी वैचारिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सत्ता को मुसलमानों पर थोपना चाहता है. उसने यह अपील की कि अमेरिका और यूरोप के देश शक्तिशाली हैं और उनसे लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है. मुस्लिम देशों की सरकारें अमेरिका से नहीं लड़ सकती हैं, इसलिए ख़ुद ही लड़ना ज़रूरी है. इनके ख़िलाफ़ जेहाद करना ही सबसे पवित्र कर्तव्य है. यह आइडिया ख़तरनाक और हिंसक है, लेकिन सच्चाई यह है कि ओसामा बिन लादेन के विचारों और संदेशों से कई नौजवान प्रेरित होते हैं. वह अरब देशों के युवाओं का हीरो है. यह बिन लादेन का ही असर है कि अमेरिका विरोध उनके दिलों में ऐसे बैठ जाता है कि वे आत्मघाती हमले करने से भी नहीं हिचकते. ओसामा बिन लादेन द्वारा बनाया गया संगठन अलक़ायदा ऐसे ही प्रेरित और समर्पित लोगों की फौज है. यही वजह है कि यूरोप, उत्तरी अमेरिका, मध्य पूर्व और एशिया के 40 से भी अधिक देशों में ओसामा बिन लादेन का अलक़ायदा सक्रिय है.

ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद अलक़ायदा का नया चेहरा उभरेगा. ओसामा बिन लादेन की हैसियत अब एक दार्शनिक की होगी. यह संगठन लादेन द्वारा बताई गई विचारधारा और रणनीति पर चलेगा. पिछले दस सालों में ओसामा बिन लादेन ने अलक़ायदा को बड़ी सूझबूझ के साथ फ्रेंचाइजी मॉडल में तब्दील कर दिया. मतलब यह कि पहले जहां अलक़ायदा का सिर्फ़ एक संगठन होता था, अब यह अलग-अलग जगहों पर छोटी-छोटी इकाइयों की तरह काम

(शेष पृष्ठ 2 पर)

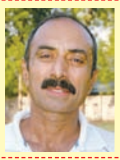

पर्यवेक्षकों के मुताबिक, मुख्यमंत्री की अपने बाबुओं और प्रशासन पर सख्त पकड़ है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लगता कि भट्ट को अलग-थलग किया जा सकता है.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

अगला कैबिनेट सचिव कौन

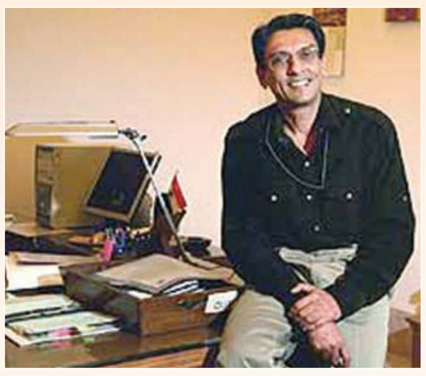

नए कैबिनेट सचिव के नाम की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है और इस वजह से बाबुओं के बीच कयासबाजी का दौर जारी है. यद्यपि पुलोक चटर्जी का नाम इस पद की दौड़ में सबसे आगे है, फिर भी और कई नाम भी इसमें शामिल हैं. इसमें बिहार के मुख्य सचिव अनूप मुखर्जी के नाम की संभावना सबसे ज़्यादा दिख रही है. कुछ पर्यवेक्षकों का मानना है कि उनका नाम पुलोक चटर्जी के विकल्प के तौर पर बेहतर साबित हो सकता है. इस बार एक महिला को कैबिनेट सचिव पद पर लाए जाने की बात पर भी विचार किया जा रहा है. ऐसी स्थिति में वित्त सचिव सुषमा नाथ और कार्मिक सचिव अलका सिरोही का नाम भी सामने आ रहा है. ज़ाहिर है, जल्द ही एक अंतिम नाम सबके सामने आ जाएगा. दिलचस्प रूप से सरकर में ऊंचे ओहदे पर महिला को नियुक्त किए जाने की चर्चा तबसे ज्यादा जोर पकड़ती गई, जब निरूपमा राव विदेश सचिव बनीं. अभी तक भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के पद पर कभी किसी महिला को नियुक्त नहीं किया गया है. सरकार के 150 सचिवों में से महज दस ही महिलाएं हैं और निरूपमा राव, जो जल्द ही रिटायर होने वाली हैं, के बाद यह संख्या और घट जाएगी. सूत्रों का कहना है कि निरूपमा की जगह किसी महिला को ही लाया जाएगा. कई लोग इस पद के लिए रंजन मथाई, एस सभ्भरवाल और आलोक प्रसाद के नाम पर भी कयास लगा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी अंतिम रूप से कहना जल्दबाजी होगा.

बाबू बनाम नेता

वर्ष 2002 के गुजरात दंगे और उस दौरान नेताओं द्वारा पुलिस वालों पर दबाव बनाने के मामले अब एक-एक करके सामने आ रहे हैं. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट ने दंगे के समय नरेंद्र मोदी की भूमिका पर जो सवाल उठाए हैं, उनसे गुजरात पुलिस के आला अफसरों में हलचल मच गई है. सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र देकर संजीव भट्ट ने मोदी को तो घेरे में लिया ही, साथ ही उन्होंने दंगे की जांच करने वाली टीम (एसआईटी) की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं. इस सबसे मोदी पर तो धब्बा लगा ही, साथ ही विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी सकते में आ गए. पर्यवेक्षकों के मुताबिक, मुख्यमंत्री की अपने बाबुओं और प्रशासन पर सख्त पकड़ है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लगता कि भट्ट को अलग-थलग किया जा सकता है. पूर्व पुलिस महानिदेशक के चक्रवर्ती भले ही भट्ट के बयान पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन भट्ट को अपने सहकर्मियों (सिविल सर्विस से जुड़े सहयोगी) की ओर से पर्याप्त समर्थन मिलता दिख रहा है. निलंबित आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा, जो खुद जमीन घोटाले के आरोप का सामना कर रहे हैं, ने एसआईटी के सामने उपस्थित होकर यह खुलासा करने की इच्छा जताई है कि कैसे उन पर यह दबाव डाला गया कि वह अपने एक आईपीएस भाई को अपना कर्तव्य निभाने से रोकें. सबसे खास बात यह है कि एक पूर्व उच्च पुलिस अधिकारी आर बी श्रीकुमार भी भट्ट के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं और गृहमंत्री पी चिदंबरम ने भी भट्ट के शपथपत्र को अपना समर्थन देने का संकेत दिया है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात में शक्तिशाली मोदी से मुकाबला करने के लिए और कौन-कौन लोग सामने आते हैं.

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

वास बनेंगे सचिव

उत्तर प्रदेश कैडर और 1977 बैच के आईएएस अधिकारी एल एम वास अभी आर्थिक मामलों के विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात हैं. उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि बहुत जल्द ही वास को किसी मंत्रालय में सचिव बनाया जाएगा.

संयुक्त सचिव बनेंगी राधा

उत्तर प्रदेश कैडर और 1988 बैच की आईएएस अधिकारी राधा चौहान जल्द ही भारत सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त की जाएंगी. वह एस सी खुनीटा की जगह लेंगी.

सुजाता यूआईएआइ में

बिहार कैडर और 1989 बैच की आईएएस अधिकारी सुजाता चतुर्वेदी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईएआई) की क्षेत्रीय उप निदेशक बनेंगी. वह जीवीके राव की जगह लेंगी. यह पद संयुक्त सचिव के समकक्ष होता है.

कौन होगा डिप्टी सीईओ

फूड एंड सेफ्टी अथॉरिटी में डिप्टी सीईओ का पद सृजित किया गया है. इस पद के लिए दो अधिकारियों का नाम सामने आ रहा है. इनमें 1983 बैच के सीएसएस अधिकारी जी एस बोथयाल और 1988 बैच की सीएसएस अधिकारी रीता चटर्जी शामिल हैं.

ए के मिश्रा होंगे निदेशक

आईएएस अधिकारी अवनीश कुमार मिश्रा को आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय में निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है. इस मंत्रालय में यह नवसृजित पद है.

एक था ओसामा

ओसामा बिन लादेन का सफ़रनामा

1957 : सऊदी अरब के एक बहुत बड़े व्यवसायी मोहम्मद अवाद बिन लादेन के घर ओसामा का जन्म.

1967: हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में मोहम्मद अवाद की मृत्यु, दस वर्ष की उम्र में ओसामा बिन लादेन पिता की दौलत का उत्तराधिकारी बना.

1979 : लादेन अफगानिस्तान गया, जहां वह अफगान लड़ाकों के साथ मुजाहिदीन बन गया और अफ़ग़ानों का वित्तदाता बना.

1989: रूस के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद ओसामा सऊदी अरब वापस आता है और पिता का काम देखता है. अफ़ग़ानों को मदद जारी रहती है.

1990 : कुवैत पर इराक़ के हमले के मद्देनज़र अमेरिकी सैनिक सऊदी अरब आते हैं. लादेन अरब से विमुख हो जाता है और सऊदी अरब के विरोध में लेख लिखने लगता है.

1991 : सऊदी अरब से निष्कासित, सूडान नया घर. घरवाले भी उसे नकार देते हैं.

1993 : वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बम फटा, सोमालिया में अमेरिकी सैनिकों की हत्या.

1995 : रियाद में बम धमाका, कई अमेरिकी मारे गए.

1996 : सूडान से बहिष्कृत, अफगानिस्तान जाकर अमेरिका के ख़िलाफ़ जेहाद की घोषणा.

1998 : नैरोबी, केन्या, तंजानिया और दार-ए-सलाम में अमेरिकी दूतावासों पर बमों से हमला.

2000 : लॉस एंजिलिस हवाई अड्डे पर बम विस्फोट की योजना विफल. पकड़े गए आतंकियों ने बिन लादेन से प्रशिक्षण लिया था.

2001 : 9/11 की घटना, लादेन प्रमुख दोषी माना गया.

2002 : तालिबान सत्ताच्युत, लादेन का अमेरिका के ख़िलाफ़ युद्ध. 2003: अल जजीरा चैनल पर लादेन का वीडियो टेप, जिसमें लादेन सारे मुसलमानों को एक होकर अमेरिका से लड़ने की नसीहत देता है.

2004 : अमेरिका लादेन के सिर पर ईनाम बढ़ाकर 50 मिलियन डॉलर कर देता है.

2011 : लादेन पाकिस्तान के ऐबटाबाद में अमेरिकी हमले में मारा जाता है.

पृष्ठ एक का शेष

करेगा. ओसामा बिन लादेन इस्लाम की पवित्रता में विश्वास करता था. वह डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म, सोशलिज्म या फिर किसी भी ग़ैर इस्लामी सरकारी व्यवस्था के ख़िलाफ़ था. वह इस्लामिक देशों में शरिया के मुताबिक़ क़ानून लागू करने का पक्षधर था. उसका मानना था कि मुल्ला उमर की तालिबानी सरकार वाला अफ़ग़ानिस्तान ही अकेला इस्लामिक देश है. वह ऐसी ही सरकार हर मुस्लिम देश में लागू करना चाहता था. उसका मानना था कि अमेरिका ने पश्चिम एशिया में आकर सभ्यता और इस्लाम को प्रदूषित कर दिया है, इसलिए अमेरिका को पूरे पश्चिम एशिया से बाहर करना जरूरी है. ओसामा फिलिस्तीन का समर्थक था और इजरायल को पश्चिम एशिया से बाहर निकालने का पक्षधर था. इसके लिए उसे हिंसा से भी गुरेज नहीं था. इसमें कोई शक़ नहीं कि उसके विचार और लक्ष्य हासिल करने के तरीक़े उसे आतंकवादी की श्रेणी में शामिल करते हैं.

ओसामा की रणनीति अलग-अलग दुश्मनों के हिसाब से बनी थी. अलक़ायदा के मैन्युअल में इसे अच्छी तरह से समझाया गया है. ओसामा बिन लादेन छोटे देशों से लड़ने के लिए बम धमाके और आत्मघाती हमले जैसी रणनीति पर काम करता था, लेकिन सोवियत संघ और अमेरिका जैसे बड़े देशों के लिए उसकी रणनीति अलग थी. वह इनके साथ सालों तक चलने वाली लंबी लड़ाई करके इन्हें तबाह करना चाहता था. उसका मानना था कि ऐसी लड़ाई के ज़रिए ही विश्व शक्ति को हराया जा सकता है. ऐसी रणनीति की वजह से विश्व शक्ति की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है. सैनिकों के मरने से इन देशों की सरकार पर दबाव बढ़ता है, जिसकी वजह से वे युद्ध के मैदान से भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे. साथ ही इस दौरान धर्मयुद्ध के नाम पर अलग-अलग देशों से जेहादी शामिल होंगे, जो जान दे देंगे, लेकिन समर्पण नहीं करेंगे. इसी रणनीति के ज़रिए ओसामा बिन लादेन ने सोवियत संघ को अफगान युद्ध में पराजित किया था. सोवियत सेना को अपने टैंक छोड़कर भागना पड़ा था. ओसामा बिन लादेन यही उम्मीद कर रहा था कि अफ़ग़ानिस्तान में जो हाल सोवियत संघ का हुआ, वही अमेरिका का होगा. समझने वाली बात यह है कि उसकी रणनीति सफल होती नज़र आ रही है. अमेरिका की आर्थिक स्थिति युद्ध की वजह से ख़राब हो गई है. अमेरिका अब ज़्यादा दिनों तक इराक और अफ़ग़ानिस्तान से युद्ध जारी रखने के पक्ष में नहीं है. इन देशों में युद्ध को लेकर सरकार को जन समर्थन नहीं है. चुनाव के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने यही वादा किया था कि वह युद्ध को ख़त्म करेंगे, इराक़ और अफ़ग़ानिस्तान से सैनिकों को वापस लाएंगे. अमेरिकी सेना के वापस जाने से पहले ही ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया. अमेरिका ने उसे मार गिराया, लेकिन यह कहना पड़ेगा कि वह इतिहास का ऐसा अकेला शख्स है, जिसने दोनों सुपर पावर से लड़ाई लड़ी. एक को उसने हरा दिया और दूसरे के साथ युद्ध में मारा गया. भविष्य में अगर अमेरिकी सेना अफ़ग़ानिस्तान से वापस जाती है और तालिबान वापस अफ़ग़ानिस्तान में सरकार बनाने में कामयाब हो जाता है तो यक़ीनन इसका श्रेय ओसामा बिन लादेन को जाएगा.

अब सवाल यह है कि ओसामा बिन लादेन के बाद अलक़ायदा का क्या होगा. ओसामा बिन लादेन ने एक ऐसा संगठन तैयार किया, जो संख्या के आधार पर ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसके सदस्य समर्पित और प्रशिक्षित लड़ाकू हैं, जो जान पर खेलकर अपना काम करते हैं. समझने वाली बात यह है कि अलक़ायदा किसी दूसरे संगठनों की तरह कोई वर्गीकृत संगठन नहीं है. इसका कोई निर्धारित कंट्रोल एवं कमांड सिस्टम नहीं है. आज अलक़ायदा का नेटवर्क इंडोनेशिया से लेकर अमेरिका तक फैला है. 9/11 के बाद ओसामा ने अलक़ायदा को छोटी-छोटी टुकड़ियों में बांट दिया. ओसामा बिन लादेन ने अलक़ायदा को पूरी दुनिया में फैला दिया. इसकी सारी गतिविधियां दुनिया से छिपी हैं. इसके सदस्य गुप्त रूप से काम करते हैं. लादेन को टेक्नालॉजी की अच्छी समझ थी. वह इस बात से वाक़िफ़ था कि अफ़ग़ान युद्ध के बाद से दुनिया काफ़ी बदल चुकी है. वह इस बात को भी समझता था कि किस तरह इंटरनेट और सैटेलाइट के ज़रिए शक्तिशाली देश उसके संगठन पर निगरानी रख सकते हैं और किस तरह उसे तबाह कर सकते हैं. इसलिए उसने एक ऐसा संगठन तैयार किया, जिसके सदस्यों, समर्थकों एवं योजनाओं की जानकारी और आकलन करना काफ़ी मुश्किल है. यही वजह है कि ओसामा बिन लादेन की मौत से अलक़ायदा के संगठन को ज़्यादा नुक़सान नहीं होने वाला है. ओसामा बिन लादेन ने 9/11 के बाद एक आदमी-एक बम की रणनीति पर काम किया. हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अलक़ायदा के कई ठिकानों पर हमले हुए, उसके कई सदस्य मारे गए, लेकिन अमेरिका और यूरोप के देशों को सबसे ज़्यादा ख़तरा अलक़ायदा की उन टुकड़ियों से है, जो पश्चिम एशिया, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में सक्रिय हैं. इससे भी ज़्यादा ख़तरा उन लोगों से है, जो अलक़ायदा से जुड़े तो नहीं हैं, लेकिन अलक़ायदा के संदेश से प्रभावित होकर जेहादी बनते हैं या कभी भी जेहादी बन सकते हैं. इसलिए ओसामा बिन लादेन मरने के बाद भी उतना ही ख़तरनाक है, जितना वह जीवित रहने पर था. ओसामा बिन लादेन का जिंदा रहना अलक़ायदा के लिए एक जीत की अनुभूति थी कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश ने जिसे पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताक़त लगा दी, फिर भी वह बिन लादेन जिंदा है, अमेरिका की पकड़ से बाहर है. ओसामा बिन लादेन के मारे जाने से अमेरिका को सिर्फ़ मनोवैज्ञानिक फ़ायदा हुआ है, हालांकि उसे अलक़ायदा के सदस्यों एवं समर्थकों से ख़तरा आज और भी अधिक है, क्योंकि अलक़ायदा अब ओसामा की मौत का बदला लेने पर आमादा है.

11 सितंबर 2001 से पहले का नज़ारा

इसमें कोई शक़ नहीं है कि ओसामा की मौत से अमेरिकी सरकार ने राहत की सांस ली. अमेरिका के रणनीतिकार यही सोच रहे होंगे कि भविष्य में अब कोई दूसरा ओसामा बिन लादेन न पैदा हो. एक और बात जो ग़ौर करने वाली है कि ओसामा बिन लादेन ने मानसिक और वैचारिक स्तर पर भी व्यापक असर डाला है. 9/11 की घटना के बाद से इस्लाम, जेहाद और आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई. 2001 के बाद से इस्लामिक समाज को चरमपंथियों और उग्रवाद ने अपने चंगुल में लिया और इसमें उन्हें सफलता भी मिली. वहीं मुसलमानों का एक बड़ा तबका इस्लाम के इस रूप के विरोध में जा खड़ा हुआ. ओसामा बिन लादेन, अलक़ायदा और उससे जुड़े संगठनों की वजह से मुस्लिम समाज में आधुनिकता की हवा चली. जेहाद के नाम पर होने वाली हिंसा की निंदा करने के लिए मुसलमान आगे आने लगे. मुस्लिम समाज की नई पीढ़ी यानी युवा वर्ग ने तो हिंसा और आतंक को सिरे से नकार दिया. इसका असर पश्चिम एशिया में देखने को मिल रहा है, जहां मुसलमान प्रजातंत्र के लिए आंदोलन कर रहे हैं. इन आंदोलनों में महिलाएं भी शामिल हैं. भारत और पाकिस्तान में चरमपंथी तो हैं, लेकिन उन्हें मुस्लिम युवाओं का समर्थन नहीं हासिल है. ओसामा बिन लादेन की गतिविधियों की वजह से यूरोप और अमेरिकी समाज का असली चेहरा भी सामने आया. यूरोप और अमेरिका अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता पर इठलाते रहे हैं. अब तक यही बताया गया कि सहिष्णुता और उदारता पश्चिम सभ्यता की जड़ है. 9/11 के बाद से जिस तरह गैर ईसाइयों के साथ बर्ताव हुआ, जिस तरह ग़ैर ईसाइयों पर हमले हुए, जिस तरह पगड़ी और हिजाब को लेकर सिखों एवं मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया, उससे पश्चिमी सभ्यता की कलई खुल गई.

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 10
दिल्ली, 16 मई-22 मई 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

विशेष संवाददाता
सरोज कुमार सिंह (बिहार)

प्रबंध संपादक (उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)
डॉ. सुनील कौशिक

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-4783999/011-23418962
0120-6450888, 0120-6452888
0120-6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120-4783999
+91 9871194800
फैक्स न. 0120-4783950

पृष्ठ-16+4+4+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

अरुणाचल जैसे दुर्गम क्षेत्र में पवन हंस कंपनी के हेलीकॉप्टरों के बार-बार दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद सरकार सबक क्यों नहीं ले रही है?

गुजरात सबसे आगे है

भारत की अर्थव्यवस्था पिछले दो दशकों से निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है. आज भारत विकासशील देशों की सूची में सिर्फ चीन से पीछे है और अटकलें लगाई जाती हैं कि वह चीन को भी जल्दी ही पीछे छोड़ देगा. भारत के विकास की कहानी में भी विश्व की तरह तीन तरीके के पात्र हैं. पहले वे प्रदेश हैं, जो विकास की सीढ़ी के पहले पायदान पर हैं. उन्हें बीमारू प्रदेश भी कहते हैं. वैसे इनमें भी बदलाव की बयार तेज़ हो चुकी है. दूसरे वे प्रदेश हैं, जो विकासशील कहे जा सकते हैं. भारत के कुछ चुनिंदा प्रदेश, जहां की अर्थव्यवस्था ने भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान दिया है, उनमें गुजरात का नाम प्रमुख है.

51वें वर्ष में प्रवेश के अवसर पर गुजरात सहित विभिन्न देशों में रहने वाले गुजराती लोगों ने स्वर्णिम जयंती महोत्सव का आयोजन किया. विश्व भर में फैले गुजरातियों के लिए गुजरात क्विज का ऑनलाइन ग्लोबल कंपटीशन शुरू करने की भी घोषणा हुई. इस मौक़े पर ग्लोबल गुजरात कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया. स्वर्णिम जयंती समापन वर्ष के शानदार महोत्सव में केन्या के उपराष्ट्रपति डॉ. स्टीफन कॉलोंजो मूस्योका मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे. यह बात दर्शाती है कि गुजरात किस तरह दूसरे देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. यह सब इसलिए हो पाया है, क्योंकि विकास को इस राज्य ने अपना मूल मंत्र बना लिया है.

गुजरात सांप्रदायिक दंगों के लिए बदनाम हुआ, लेकिन अब स्थिति में बदलाव आया है. भले ही गुजरात इस धब्बे को कभी न मिटा पाए, लेकिन आज देश में सभी राज्यों की कानून व्यवस्था के संदर्भ में गुजरात सबसे ऊपर है. देश या विदेश, सभी जगहों से गुजरात में लाखों करोड़ रुपये का निवेश आ रहा है और इसीलिए गुजरात को देश का निवेश राज्य कहा जा सकता है. गुजरात में निवेश चुंबक की तरह खिंचा चला आ रहा है, क्योंकि संभवत: सबसे बड़ी बात है यहां की चाक चौबंद कानून व्यवस्था. अभी कुछ महीने पहले हुए वाइब्रेंट गुजरात निवेश मेले में, जो इस मेले का पांचवा साल था, लगभग 20,83,000 करोड़ रुपये मूल्य के निवेश मिले. इस मेले में लगभग 101 देशों के लोगों ने हिस्सा लिया. मुद्दे की बात यह है कि सिर्फ भारत के बाहर से ही नहीं, गुजरात को देश के सभी बड़े उद्योगपतियों ने दूसरे राज्यों की तुलना में वरीयता दी है. टाटा का नैनो प्रोजेक्ट हो या रिलायंस या रुईआ के निवेश, सभी गुजरात में अपना पैसा लगाना चाहते हैं. इसी कारण जहां पिछली बार वाइब्रेंट गुजरात मेले में 45 देशों के लोग आए थे और 240 बिलियन डॉलर के मसौदे हुए थे, इस बार इतनी बड़ी रकम के मसौदे हुए. ज़ाहिर सी बात है कि कुछ तो ऐसा हो रहा है कि पूंजीपति, जो मुनाफे के लिए काम करते हैं, इतनी बड़ी संख्या में गुजरात के प्रति आकर्षित हो रहे हैं.

गुजरात की विकास गाथा अपने आप में एक मिसाल है. गुजरात देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक है. यहां का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन देश के सामान्य उत्पादन से 3.2 गुना है. अगर गुजरात एक अलग देश होता तो विश्व का 67वां सबसे अमीर देश होता और चीन से भी आगे होता. गुजरात ने देश की विकास यात्रा में कई नए प्रतिमान बनाए हैं. यहां देश की सिर्फ 5 फीसदी जनता रहती है, लेकिन देश का 13 फीसदी औद्योगिक उत्पादन गुजरात करता है. यह राज्य भारत के कुल निर्यात के 22 फीसदी का हिस्सेदार है. भारत का 24 फीसदी सूती कपड़ा उत्पादन गुजरात में होता है. देश भर की 35 फीसदी दवाइयां गुजरात में बनती हैं. पेट्रोलियम पदार्थों का 51 फीसदी हिस्सा गुजरात से आता है. अलंग में भारत का सबसे बड़ा पोत तोड़ने का कारखाना है. गैस द्वारा ऊर्जा उत्पादन में गुजरात देश में अग्रणी है. भारत के शेयर मार्केट की 35 फीसदी पूंजी गुजरातियों के पास है. गुजरात के लोगों ने विदेशों में भी भारत का गौरव बढ़ाया है. उत्तरी अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों में 60 फीसदी संख्या गुजरातियों की है. वहां पर किसी भी गुजराती परिवार की आमदनी किसी अमेरिकी परिवार से कम से कम तीन गुनी है.

अब यदि इन बातों को ध्यान में रखा जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि गुजरात को भारत में विकास के इंजन की उपाधि दी गई है. गुजरात में देश के किसी भी राज्य से अधिक हवाई अड्डे हैं, जिनमें एक अंतरराष्ट्रीय और 6 अंतरराज्यीय हवाई अड्डे शामिल हैं. इसलिए दूर देशों से भी संपर्क बनाए रखने के लिए किसी जद्दोजहद की ज़रूरत नहीं होती. गुजरात में देश की सबसे अच्छी सड़कें और रेल लाइनों का जाल भी समुचित मात्रा में है. गुजरात ने आर्थिक सुधारों को बहुत तेज़ी से लागू किया है. इस कारण राज्य में महंगाई नियंत्रण में है और मूल ढांचे को सुदृढ़ किया गया है. राज्य में आर्थिक निवेश को सरल और सुडौल बनाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं. गुजरात ने इस दिशा में आधुनिक तकनीक का सहारा बड़ी सूझबूझ से लिया है और सिंगल विंडो मॉडल को आगे बढ़ाया है. निवेश करने वालों की सुविधा के लिए मूल ढांचे के बारे में तालुका स्तर तक की सूचनाएं उपलब्ध हैं.

निवेश के लिए समुचित माहौल बनाने के उद्देश्य से गुजरात ने अपने कामगारों की क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिससे निवेश करने वाली कंपनियों को उनके मन मुताबिक़ कामगार मिल सकें. गुजरात में 54 इंजीनियरिंग कालेज हैं और 106 डिप्लोमा संस्थान भी. राज्य में 441 व्यवसायिक संस्थान यानी आईटीआई भी हैं, जिनमें से हर साल लगभग 80,000 युवा काम सीखकर निकलते हैं. गुजरात में हर साल 7 लाख युवा स्नातक की पढ़ाई करके निकलते हैं. अहमदाबाद के आईआईएम का अपना अलग ही स्थान है और राज्य में आईआईटी संस्थान भी है. किसी भी राज्य के विकास का एक पैमाना वहां का बैंकिंग तंत्र भी होता है. इस मामले में भी गुजरात देश के कई बड़े राज्यों से कहीं आगे है. छोटे से लेकर बड़े लोन तक की सुविधा है और को-ऑपरेटिव या सहकारी बैंकों की भी भरमार है. राज्य में सरकारी ही नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों का भी ढांचा बहुत मज़बूत रूप से उभरा है.

गुजरात का समुद्र तट बहुत लंबा है, जिस कारण यहां ऐसे अनेक प्राकृतिक स्थान हैं, जहां पर बंदरगाह बनाए गए हैं या बनाए जा सकते हैं. इस कारण देश में आने और देश के बाहर जाने वाली वस्तुओं का सबसे बड़ा जखीरा गुजरात से ही होकर आता-जाता है. देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी जामनगर में ही स्थित है. इन सारे कारणों से राज्य में बेरोजगारी कम है. स्वरोजगार के लिए छोटी उत्पादन इकाइयों को सरकार ने बढ़ावा दिया है. गुजरात में एसईजेड हैं, जिनमें तीन ऑपरेशनल हैं और उनमें कांडला एवं सूरत मुख्य हैं. ये सारे अलग-अलग क्षेत्रों में महारथ रखते हैं, जैसे ऊर्जा, कपड़ा उत्पादन, नग और जवाहरात आदि. गुजरात में देश में आने वाले कुल निवेश का 15.14 फीसदी हिस्सा आता है, जो बाकी किसी भी राज्य से अधिक है. 41 बंदरगाहों की वजह से देश के कुल समुद्री व्यापार का 25 फीसदी हिस्सा गुजरात के पास है. 2002 से 2007 की समयावधि में गुजरात का सकल घरेलू उत्पाद 10.2 फीसदी की दर से बढ़ा. आगामी 2012 तक के लिए इस लक्ष्य को बढ़ाकर 11.2 फीसदी कर दिया गया है, जो देश में सबसे अधिक है.

लेकिन ऐसा नहीं है कि गुजरात सबसे आगे होने की वजह से पूर्णतया विकसित हो चुका है. अभी भी राज्य में वही सारी समस्याएं हैं, जिन्होंने पूरे देश को परेशान कर रखा है. इस कारण अभी भी गुजरात को आम आदमी के लिए बहुत कुछ करना बाकी है. भले ही गुजरात ने भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया हो, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना शेष है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

खांडू की मौत से उपजे सवाल

एस बिजेन सिंह

बीते 30 अप्रैल को हेलीकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की असामयिक मृत्यु हो गई. इससे भी ज़्यादा दु:ख की बात यह है कि इस तरह की दुर्घटनाएं बार-बार हो रही हैं. इस हादसे से पहले भी कई वीवीआईपी हेलीकॉप्टर दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं, लेकिन यह दुर्घटना एक साथ कई सवाल खड़े कर रही है. मालूम हो कि अरुणाचल की सीमा चीन से लगी हुई है. चीन सीमा से सटे होने के कारण अरुणाचल प्रदेश में ढांचागत सुविधाओं का अभाव है. अपने कड़े रुख के कारण खांडू चीन की आंखों की किरकिरी बने हुए थे. खांडू ने बीते 30 अप्रैल की सुबह पवन हंस हेलीकॉप्टर कंपनी के यूरोकाप्टर बी-8 से उड़ान भरी थी. उड़ान भरने के 20 मिनट बाद ही यह हेलीकॉप्टर लापता हो गया और उसका संपर्क नियंत्रण कक्ष से टूट गया. इसी बीच किसी अज्ञात सेटेलाइट फोन से ख़बर आई कि खांडू को ले जा रहा हेलीकॉप्टर भूटान के सीमावर्ती क्षेत्र में उतर गया है, लेकिन बाद में इसकी पुष्टि नहीं हुई. यह किसका सेटेलाइट फोन था, इस पर भी अभी रहस्य बना हुआ है.

अरुणाचल जैसे दुर्गम क्षेत्र में पवन हंस कंपनी के हेलीकॉप्टरों के बार-बार दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद सरकार सबक क्यों नहीं ले रही है? पिछले दिनों तवांग में पवन हंस का एक और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी. उसके बाद पवन हंस कंपनी की सेवा और लापरवाही को लेकर कई सवाल भी उठे थे. यही नहीं, पूर्वोत्तर की विभिन्न राज्य सरकारें भी कई बार शिकायत कर चुकी थीं. बावजूद इसके इस इलाक़े में पवन हंस कंपनी की हेलीकॉप्टर सेवा जारी रहना कई तरह के संदेह पैदा करता है. तवांग जैसे बीहड़ क्षेत्र में मुख्यमंत्री को ले जाने वाले पवन हंस हेलीकॉप्टर में केवल एक इंजन लगा होना लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण है. सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए कि पवन हंस कंपनी का रिकॉर्ड इतना खराब होने के बावजूद उसके एक इंजन वाले हेलीकॉप्टर की सेवा क्यों ली गई? लगातार पांच दिनों तक सेना, सीमा सड़क संगठन, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, एसएसबी और अरुणाचल पुलिस के क़रीब 3 हज़ार जवान हेलीकॉप्टर खोजने के अभियान में जुटे रहे. यही नहीं, वायुसेना के सुखोई-30 विमानों-हेलीकॉप्टरों और इसरो ने भी इस अभियान में काफ़ी मेहनत की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी. सारे प्रयास धरे के धरे रह गए. बाद में ग्रामीणों ने शवों और हेलीकॉप्टर के मलवे को देखा और उन्होंने ही अरुणाचल नियंत्रण कक्ष को इसकी सूचना दी. उसके बाद सुरक्षाबल वहां पहुंचे और शवों की पहचान हुई. दोरजी का शव क्एला और लोबोथांग के बीच पाया गया. इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों में खांडू के अलावा पायलट जे एस बब्बर, कैप्टन टी एस मामिक, खांडू के सुरक्षा अधिकारी एशी कोडक और तवांग के विधायक त्सेवांग धोंडप की बहन एशी ल्हामू भी शामिल थे.

अरुणाचल की जनता द्वारा पवन हंस कंपनी के कार्यालय में तोड़फोड़ करना स्वाभाविक था. केंद्र सरकार को तत्काल प्रभाव से पवन हंस की सेवा बंद कर देनी चाहिए, साथ ही इस कंपनी को काली सूची में डाल देने की ज़रूरत है. इस बात की जांच होनी चाहिए कि अनुभवहीन पायलटों के कारण तो ऐसी घटना नहीं हुई? केंद्र सरकार को इस दिशा में गंभीरता से क़दम उठाना होगा. खांडू से पहले भी विभिन्न विमान दुर्घटनाओं में अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मौत हो चुकी है. वर्ष 2009 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी भी नल्लामल्ला की पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से मारे गए थे. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधवराव सिंधिया, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जी एम सी बालयोगी, कांग्रेस के युवा नेता संजय गांधी और पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री मोहन कुमार मंगल की मौत भी इसी प्रकार हुई थी.

bijen@chauthiduniya.com

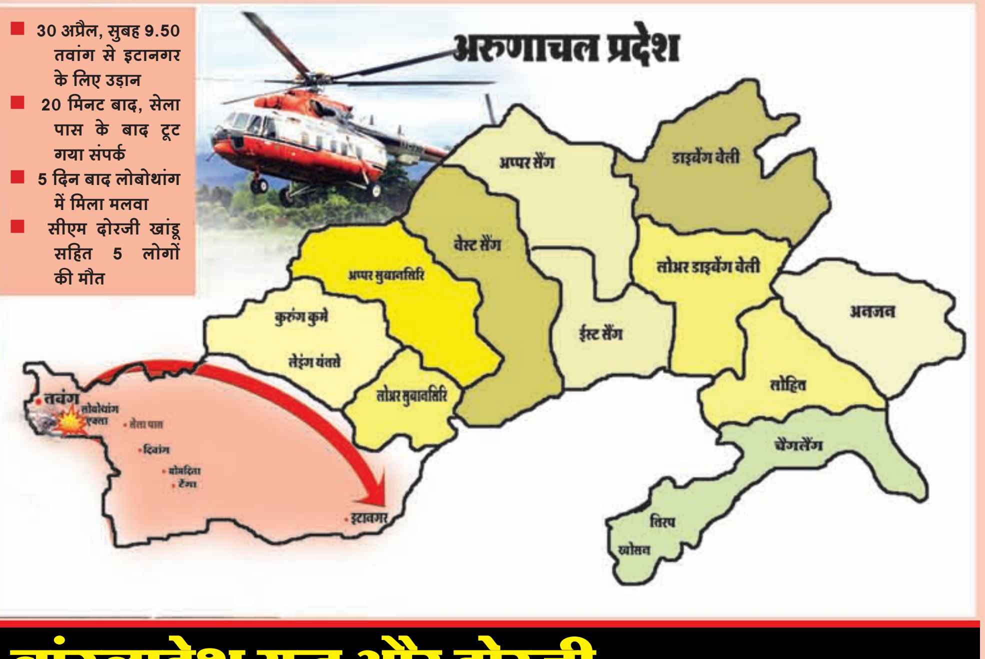

बांग्लादेश युद्ध और दोरजी

56 वर्षीय दोरजी खांडू मोनपा जनजाति के थे. उनके परिवार में चार पत्नियां, चार पुत्र और दो पुत्रियां हैं. दोरजी एक ज़मीनी कार्यकर्ता थे. वह अपनी मेहनत के बल पर राज्य के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे. खांडू ने अपना राजनीतिक सफर राज्य के दूरदराज इलाक़ों में स्कूल खोलने और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने में मदद करने वाले स्थानीय नेता के रूप में शुरू किया था. वह बौद्ध धर्म मानते थे. दो-दो बार मुख्यमंत्री पद संभालने वाले खांडू सात साल तक सेना की ख़ुफ़िया शाखा से जुड़े रहे. 1971 में भारत-पाक युद्ध के दौरान उल्लेखनीय सेवा के लिए उन्हें स्वर्ण पदक से नवाजा गया. तीन मार्च, 1955 को तवांग में जन्मे खांडू 1980 में अंचल समिति के सदस्य बने. इसके बाद उन्होंने दूरदराज के गांवों में सामाजिक कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित किया. उन्होंने अपने गृह ज़िले में पेयजल, बिजली एवं संचार सुविधाएं पहुंचाने और स्कूल स्थापित कराने में अहम भूमिका निभाई. 1983 में वह वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के उपाध्यक्ष बने और 1990 में मुक्तो क्षेत्र से निर्विरोध विधायक चुने गए. 2007 में वह गेगांग अपांग की जगह मुख्यमंत्री बने.

लोहरदगा में पुलिस को सूचना मिली कि सेन्हा थाना अंतर्गत पहाड़ी इलाक़े उड़मुड़ में माओवादियों का दस्ता मौजूद है.

सामूहिक विवाह कार्यक्रम

अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

कहते हैं, जिस दिन घर में बेटी पैदा होती है, उसी दिन से बाप की कमर झुक जाती है. बहुत हद तक यह बात भारतीय समाज के लिए सही भी है, क्योंकि दहेज जैसी प्रथा कब एक विकराल सामाजिक समस्या बन गई, पता ही नहीं चला. बावजूद इसके इसी समाज से कुछ सकारात्मक क़दम भी उठते दिख रहे हैं, जो दहेज जैसी बुराई के ख़ात्मे को लेकर प्रतिबद्ध हैं. कुछ ऐसे लोग हैं, जो सामाजिक सरोकार के मुद्दों से जुड़े हैं और इसी के तहत सामूहिक विवाह के ज़रिए सामाजिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए आगे आ रहे हैं. इनमें एक नाम अमेठी के राजा एवं सुल्तानपुर के सांसद डॉ. संजय सिंह और उनकी पत्नी एवं अमेठी की विधायक डॉ. अमीता सिंह का भी है.

बीती एक मई को राजर्षि रणंजय सिंह जन कल्याण समिति के तत्वावधान में डॉ. संजय सिंह एवं समिति की अध्यक्ष डॉ. अमीता सिंह ने विभिन्न जातियों के ग़रीब–पिछड़े परिवारों की 111 बेटियों का कन्यादान किया. यह समारोह सुल्तानपुर के एमजीएस इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया था. राजर्षि रणंजय सिंह जन कल्याण समिति ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम की शुरुआत 1998 से की थी. इस समिति की सहायता से अब तक सैकड़ों ग़रीब कन्याओं का घर बसाया जा चुका है. एक मई को हुए आयोजन में कोरी–42, वनमानुष–20, रैदास–10, सरोज–5, मौर्य–3, निषाद–3, कुर्मी–3, यादव–2, प्रजापति–2, नाई–2, कश्यप–2, अग्रहरि–2, जायसवाल–1, बहेलिया–1, कनौजिया–1, चौहान–1, ब्राह्मण–2 और क्षत्रिय–4 सहित कुल 108 जोड़ों का पाणिग्रहण संस्कार एवं 3 मुस्लिम जोड़ों का निकाह संपन्न कराया गया. राजर्षि रणंजय सिंह की स्मृति में इस समिति की स्थापना उनके पुत्र डॉ. संजय सिंह ने की थी.

यह संस्था सामूहिक विवाह के माध्यम से उन ग़रीब परिवारों की हरसंभव मदद करती है, जिन्हें अपनी बेटी के विवाह के लिए अपनी ज़मीन एवं अन्य संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है या बेच देनी पड़ती है. इस सामूहिक विवाह में डॉ. संजय सिंह ने इन बेटियों के पिता का फ़र्ज़ निभाते हुए उनका कन्यादान किया. इन नव दंपत्तियों को सम्मानपूर्वक जीवन शुरू करने के लिए स्त्रीधन के रूप में भेंट स्वरूप घरेलू जीवन की सभी आवश्यक वस्तुएं यथा बर्तन, डबल बेड, बिस्तर सेट, साइकिल, कपड़े, सिलाई मशीन, टेबिल फैन, चांदी के आभूषण एवं घड़ी आदि प्रदान किए गए. सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों के साथ–साथ समाज के प्रत्येक वर्ग के बुद्धिजीवियों की भागीदारी इन ग़रीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे उन्हें अपने जीवन में आशा की एक नई किरण दिखाई देती है. उनका आत्मविश्वास मज़बूत होता है, उन्हें समाज में सिर उठाकर जीने और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा मिलती है.

डॉ. सिंह ने राजनेताओं एवं सामाजिक संस्थाओं का आह्वान किया कि वे आगे आकर समाज में व्याप्त दहेज रूपी कुरीति को ख़त्म करें और इस काम को आंदोलन का रूप प्रदान करें. उन्होंने कहा कि हम लोगों के सामूहिक प्रयास से निश्चित रूप से वह दिन आएगा, जब गरीब मां-बाप की लाचारी और उनकी बेटी के सपनों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा.

उपहारों की सूची

कपड़े : दूल्हा, दुल्हन और उनके माता–पिता के लिए.
आभूषण–हार, कंगन, अंगूठी, टीका, पायल, झुमका, नथुनी, बिछुआ.
प्रसाधन सामग्री : तौलिया, तेल, पाउडर, क्रीम, काजल, बिंदी, चूड़ी, लिपिस्टिक, नेल पॉलिश, फीता, शीशा, कंघा, महावर, चप्पल, श्रृंगारदान, साबुनदानी, मोजा, सेफ्टीपिन.
बर्तन : रसोई सेट–थाली, गिलास, कटोरी, लोटा, चम्मच, केतली, जग, पानी की टंकी, परात, फ्राईपेन, छलनी, भगोना, कढ़ाही, तवा, पलटा, कलछुल, चलनी, थर्मस, पीढ़ा, बेलन, चाकू, छिलनी, चिप्स कटर और स्टील ट्रे.
अन्य सामान : डबल बेड, बिस्तर सेट, साइकिल, बड़ा बक्सा, सिलाई मशीन, टेबल पंखा, घड़ी, लालटेन, छाता, चटाई, टॉर्च, दो कुर्सी प्लास्टिक, छोटी मेज और ट्रैवल बैग.

डॉ. सिंह ने राजनेताओं एवं सामाजिक संस्थाओं का आह्वान किया कि वे आगे आकर समाज में व्याप्त दहेज रूपी कुरीति को ख़त्म करें और इस काम को आंदोलन का रूप प्रदान करें. उन्होंने कहा कि हम लोगों के सामूहिक प्रयास से निश्चित रूप से वह दिन आएगा, जब ग़रीब मां–बाप की लाचारी और उनकी बेटी के सपनों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा. समाज के हर वर्ग के लोग इस आयोजन में योगदान करने के लिए आतुर दिखे. वर–वधू को सजाने में दर्जनों महिलाएं लगी रहीं. शिक्षक, डॉक्टर, विद्यार्थी और नवयुवक इस महायज्ञ में बढ़–चढ़कर शामिल हुए. राजनीति को समाजसेवा का माध्यम मानने वाली रानी डॉ. अमीता सिंह ने कहा कि समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन मेरी प्राथमिकता है और उसमें कभी किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

आख़िर कब तक बहेगा ख़ून

प्रशांत कुमार झा

खनिज बहुल प्रदेश झारखंड अपने गठन से ही नक्सली हिंसा का शिकार होता आया है. स्थापना वर्ष 2000 से अब तक सूबे में जितनी सरकारें आईं, सभी ने नक्सलियों पर नकेल कसने की बातें दोहराईं, मगर समस्या विकराल होती गई और नक्सली बलशाली होते गए. वे अब तक असंख्य लोगों की जान ले चुके हैं. बीती 2 और 3 मई को नक्सलियों ने एक बार फिर लोहरदगा, सिल्ली एवं झुमरा में कहर बरपाया. 2 मई की देर रात और 3 मई को राज्य के तीन ज़िलों में नक्सलियों ने हिंसक खेल खेला. लोहरदगा में बारूदी सुरंग विस्फोट और ताबड़तोड़ गोलीबारी में पुलिस बल और सीआरपीएफ के 11 जवान शहीद हो गए, जबकि पचास से अधिक गंभीर रूप से घायल. झुमरा के सीआरपीएफ कमांडेंट और सिल्ली के डीएसपी भी नक्सली हिंसा के शिकार बन गए.

लोहरदगा में पुलिस को सूचना मिली कि सेन्हा थाना अंतर्गत पहाड़ी इलाक़े उड़मुड़ में माओवादियों का दस्ता मौजूद है. इस पर सीआरपीएफ और ज़िला पुलिस के क़रीब 100 जवानों की टीम उड़मुड़ के लिए तुरंत रवाना हो गई. वहां पहुंचने पर जब पता चला कि माओवादी भाग गए तो जवान वापस लौटने लगे. रास्ते में धरधरिया झरने के पास सभी ने पानी पिया. इसके बाद वे पैदल ही आगे बढ़ने लगे. इसी बीच माओवादियों ने लैंड माइंस विस्फोट कर दिया. जवान जब तक संभलते, तब तक नक्सलियों ने गोलियों की बौछार कर दी और छह जवानों ने मौक़े पर ही दम तोड़ दिया. नक्सलियों ने सड़क पर तक़रीबन दो किलोमीटर तक लैंड माइंस लगा रखे थे. माओवादी फायरिंग के साथ–साथ विस्फोट करते गए. बीच–बीच में वे हथियार सौंपने और आत्मसमर्पण करने की चेतावनी भी देते रहे. दूसरी ओर बोकारो ज़िले के झुमरा पहाड़ के निकट सूअरकटवा में नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट जख्मी हो गए. वहीं रांची के सिल्ली के कनकट्टा के पास 2 मई की देर रात नक्सलियों की गोलीबारी से डीएसपी आनंद जोसेफ तिग्गा घायल हो गए. पुलिस को कनकट्टा में नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी. डीएसपी तिग्गा के नेतृत्व में जैसे ही पुलिस टीम वहां पहुंची, माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी और डीएसपी के पेट में गोली लग गई. इसके बाद माओवादी वहां से नौ दो ग्यारह हो गए.

पुलिस पर नक्सली हमला कोई नई बात नहीं है. अब तक चार सौ से ज़्यादा पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं. राज्य गठन के कुछ ही दिनों पहले नक्सलियों ने लोहरदगा के तत्कालीन एसपी अजय कुमार सिंह समेत सात पुलिसकर्मियों को मार डाला था. 2001 में चाईबासा ज़िले के मनोहरपुर थाना अंतर्गत विटकलसोय क्षेत्र में 19 पुलिसकर्मी शहीद हुए. 2002 में हज़ारीबाग के चुरचू थाना अंतर्गत 11 पुलिसकर्मी मारे गए. 2003 में तो चाईबासा के बलिवा इलाके में नक्सलियों ने एक साथ 39 पुलिसकर्मियों को मारकर पूरे राज्य को हिला दिया था. उसी वर्ष लातेहार की अमझरिया घाटी में 11 पुलिसकर्मियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा. 2006 में 14 पुलिसकर्मी नक्सलियों के हाथों मारे गए. 2009 में केकरांग घाटी में पुलिस गश्ती दल पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था, जिसमें दो सीआरपीएफ जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी. 2010 में लातेहार के बरवाडीह में बारूदी सुरंग विस्फोट में सात पुलिसकर्मी मारे गए. 2011 के अभी महज़ चार माह बीते हैं और नक्सली अब तक 46 लोगों को मौत के घाट उतार चुकें हैं, इनमें पुलिस के जवानों के साथ आम नागरिक भी शामिल हैं.

साफ़ ज़ाहिर है कि क्रांति की दुहाई देकर बदलाव की बात करने वाले नक्सली किस कदर रक्तपात करने, हिंसक खेल खेलने और लोगों की जान लेने पर तुले हुए हैं. जवानों को मारने और बस, रेल पटरियों एवं स्कूल भवनों को उड़ाने, ट्रेन का अपहरण करने तथा प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी गिरफ्त में लेने जैसी घटनाओं को अंजाम देकर नक्सली आख़िर किस परिवर्तन की तलाश में हैं, यह समझ के परे है. नक्सली माओवादी विचारधारा के अनुयायी नहीं, बल्कि लेवी के नाम पर अकूत दौलत इकट्ठा करने वाले आतंकी गिरोह बनकर रह गए हैं. राज्य में नक्सलियों का विस्तार यूं ही नहीं हुआ है. भूख, ग़रीबी, बेरोज़गारी, आर्थिक असमानता, उत्पीड़न और विस्थापन आदि समस्याएं इसके मूल में हैं. लोग अहिंसात्मक आंदोलन करते हैं तो उन्हें अनसुना कर दिया जाता है. नतीजतन, हिंसात्मक गतिविधियों के प्रति उनका रुझान बढ़ जाता है.

पृथक राज्य बनते समय झारखंड का कोई भी ज़िला नक्सल प्रभावित नहीं था, लेकिन आज राज्य के सभी 24 ज़िले माओवादी उग्रवाद से त्रस्त हैं. नक्सलियों द्वारा बंद आयोजित करने से संपूर्ण राज्य ठहर सा जाता है. बीते दस वर्षों में बारूदी सुरंग विस्फोटों और कथित जन अदालतों में कथित दोषियों को मौत के घाट उतारने की अनगिनत घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है. माले के जुझारू नेता एवं विधायक महेंद्र सिंह, जदयू के विधायक रमेश सिंह मुंडा, झामुमो के सांसद सुनील महतो, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के पुत्र अनूप मरांडी और पुलिस अधिकारी फ्रांसिस इंदवार को नक्सलियों ने बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया. नक्सलियों की संभावित वार्षिक आमदनी 1500 करोड़ रुपये है. वे केंद्र एवं राज्य सरकार की तमाम परियोजनाओं से भी नियमित रूप से लेवी वसूलते हैं. बर्बादी का यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा, यहां की धरती कब तक ख़ून से सराबोर होती रहेगी, इन यक्ष प्रश्नों का उत्तर दूर–दूर तक दिखाई नहीं पड़ता.

feedback@chauthiduniya.com

अब राष्ट्रवादी कांग्रेस को यह समझ में आ गया है कि यदि उसे कांग्रेस का पिछलग्गू नहीं बने रहना है तो उसे अपने जनाधार को ठोस स्वरूप प्रदान करना होगा.

महाराष्ट्र

राकांपा : चेहरा बदलने की कोशिश

छगन भुजबल

शरद पवार

राज्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के आपसी समीकरण गड़बड़ा रहे हैं. दोनों के बीच राजनीतिक तनातनी चल रही है. राकांपा अपना जनाधार बढ़ाने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाने में जुट गई है. मराठा राजनीति के कारण अब तक राकांपा का अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े और परप्रांतीय मतदाताओं के मध्य कांग्रेस जैसा ठोस जनाधार नहीं बन पाया है. इन वर्गों के मतदाताओं से दूरी ही राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए चिंता की बात है. कांग्रेस से बढ़ती अंदरूनी कलह के चलते अब राकांपा के रणनीतिकारों ने पार्टी को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में

उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व में पार्टी का कायापलट करने का निर्णय आलाकमान ने ले लिया है. राकांपा के वरिष्ठ नेताओं का स्पष्ट मत हैं कि मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड़, नागपुर और नासिक महानगरपालिका में अपने दम पर सफलता हासिल करने के लिए परप्रांतीय एवं अल्पसंख्यक मतदाताओं के समर्थन की सबसे अधिक ज़रूरत है.

मज़बूत करने के लिए अपने जनाधार को ठोस रूप देने पर विचार–विमर्श शुरू कर दिया है. राकांपा पर अब तक अल्पसंख्यक, दलित एवं पिछड़ों के साथ ही परप्रांतीय मतदाताओं की उपेक्षा करने का आरोप लगता रहा है. इसे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने गंभीरता से लिया है. राकांपा के रणनीतिकारों का मानना है कि अल्पसंख्यक, दलित एवं पिछड़े वर्ग के मतदाताओं का समर्थन मिलने से आगामी नगर निकाय और विधानसभा चुनावों में पार्टी की ताक़त में भारी इज़ाफ़ा हो सकता है और कांग्रेस को पीछे ढकेला जा सकता है.

अजीत पवार

उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व में पार्टी का कायापलट करने का निर्णय आलाकमान ने ले लिया है. राकांपा के वरिष्ठ नेताओं का स्पष्ट मत है कि मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी–चिंचवड़, नागपुर और नासिक महानगरपालिका में अपने दम पर सफलता हासिल करने के लिए परप्रांतीय एवं अल्पसंख्यक मतदाताओं के समर्थन की सबसे अधिक ज़रूरत है. राकांपा अब तक अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा वर्ग और परप्रांतीय मतदाताओं का समर्थन हासिल करने में नाकाम रही है. यह भी कहा जा सकता है कि मराठा राजनीति के कारण उसने इनका समर्थन हासिल करने की ज़रूरत नहीं समझी. परप्रांतीय मतदाता विभिन्न चुनावों में कुछ हद तक राकांपा के पक्ष में मतदान करते हैं, पर वह कांग्रेस जैसा ठोस आधार बनाने में अब तक असफल रही है. लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ बराबरी का गठबंधन होने के बाद भी दलित, अल्पसंख्यक एवं परप्रांतीय मतदाताओं में राकांपा उम्मीदवारों के प्रति हिचकिचाहट देखी गई. उनके मन में कई तरह के संशय हैं, जो वाजिब हैं, क्योंकि राकांपा का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना से समय–समय पर लगाव जताना उन्हें खटकता है. इसी वजह से 2007 में संपन्न महानगरपालिका चुनाव में दलित–अल्पसंख्यक वर्ग के 23 प्रतिशत मतदाताओं ने कांग्रेस और 16 प्रतिशत मतदाताओं ने राकांपा के पक्ष में मतदान किया था. इसके अलावा ज़िला परिषदों और पंचायत समितियों में वर्चस्व होने के बाद भी शहरी क्षेत्रों में राकांपा का जनाधार कमज़ोर है. यहां ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि पार्टी में पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल की बढ़ती उपेक्षा से पिछड़े वर्ग के मतदाताओं में संशय और बढ़ गया है. जिस तरह भुजबल को उप मुख्यमंत्री पद से हटाकर अजीत पवार की ताजपोशी की गई, उससे पिछड़े वर्ग के मतदाताओं में खासी नाराजगी है.

अब राष्ट्रवादी कांग्रेस को यह समझ में आ गया है कि यदि उसे कांग्रेस का पिछलग्गू नहीं बने रहना है तो उसे अपने जनाधार को ठोस स्वरूप प्रदान करना होगा. इसके अलावा चुनाव के समय उम्मीदवारों के चयन में भी विशेष सावधानी बरतनी होगी. भ्रष्ट एवं ख़राब छवि वाले नेताओं की जगह दलितों, अल्पसंख्यकों और ग़ैर प्रांत के लोगों से सहानुभूति रखने वाले उम्मीदवारों को टिकट देना होगा. इसके लिए राकांपा ने अब कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में घुसपैठ करने की तैयारी कर ली है. इसकी शुरुआत वह मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी–चिंचवड़, नागपुर और नासिक महानगरपालिका के चुनावों से करना चाहती है. इसके लिए पार्टी नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं को कुछ निर्देश भी दिए हैं, जिन पर अमल भी शुरू हो गया है. पिछली कुछ घटनाओं से साफ ज़ाहिर होता है कि राकांपा अपना जनाधार बढ़ाने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है. विशेषकर तबसे, जबसे अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली है. अजीत पवार स्वयं बेहद सक्रिय हो गए हैं. इसकी झलक उनकी कार्यशैली में भी दिखाई दे रही है. यही वजह है कि बजट सत्र के दौरान पूरे राज्य का दौरा करके उन्होंने सबको अचंभे में डाल दिया. इतना ही नहीं, दौरे के दौरान जिसने जो मांगा, उसे वह देने की घोषणा भी कर दी. अजीत पवार के इस दौरे की कांग्रेसियों में काफी चर्चा है. अजीत का भी यह मानना है कि महानगरपालिका और विधानसभा चुनावों में अगर सफलता पाना है तो दलित, पिछड़े एवं परप्रांतीय मतदाताओं को साधे बिना पार्टी का कल्याण नहीं होने वाला. पार्टी के कल्याण के लिए राकांपा को अपना मराठा राजनीति का चेहरा बदलना होगा और पार्टी के पिछड़े, दलित एवं अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं को आगे लाना होगा. पार्टी ने इसके लिए ऐसे चेहरों को तलाशना शुरू कर दिया है, जिनकी उक्त वर्गों के मतदाताओं में अच्छी पकड़ है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

बिहार

नक़ली सरसों के तेल का काला कारोबार

नीरज कुमार सिंह

अगर आप सरसों के तेल के प्रति सतर्क नहीं है तो आपकी किडनी कभी भी काम करना बंद कर सकती है और लीवर फेल हो सकता है, क्योंकि बाज़ार में विभिन्न ब्रांडों के नाम से मिलावटी और ज़हरीला तेल बेचा जा रहा है. विगत दिनों पुलिस ने सदर थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में उत्तर बिहार की सबसे बड़ी मंडी गुलाब बाग स्थित श्याम एग्रो ऑयल मिल में छापेमारी करके बड़ी मात्रा में विभिन्न ब्रांडों के सरसों के तेल के कनस्तर, टैंकर में भरा क़रीब 50 हज़ार लीटर राइस ऑयल, सरसों के तेल के एसेंस और केमिकल के कार्टून बरामद किए थे. पुलिस ने बताया कि इस कारखाने में हल्दिया एवं इंदौर से राइस ऑयल टैंकरों में मंगाया जाता था, जिसमें एसेंस और केमिकल मिलाकर नकली सरसों का तेल तैयार किया जाता था, जिसे विभिन्न ब्रांडों के नाम से बिहार, बंगाल एवं झारखंड के विभिन्न ज़िलों में बेचा जाता था. तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने कहा था कि आरोपियों के विरुद्ध पुलिस स्पीडी ट्रायल चलाकर सज़ा दिलाने का काम करेगी और ज़ब्त तेल के नमूने को जांच हेतु हैदराबाद भेजेगी. इस मामले में खाद्य निरीक्षक स्वतंत्र कुमार ने सदर थाने में धारा 307, 420, 467, 468 एवं भादवि 34 एवं खाद्य निवारण अधिनियम 1954 की धारा 37 के तहत पांच लोगों के विरुद्ध मुक़दमा भी दर्ज कराया था.

जानकारी के अनुसार, गुलाब बाग में नक़ली सरसों का तेल बनाने वाले तीन कारखाने चल रहे थे, लेकिन एक पर छापा पड़ने के बाद दो अन्य स्वत: बंद कर हो गए. स्थानीय लोगों ने उस समय खाद्य निरीक्षक की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि उक्त कारखाने लंबे समय से चल रहे थे, लेकिन क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक ने कभी कोई जांच नहीं की. इस पर ज़िलाधिकारी डॉ. एन श्रवण कुमार ने इस संदर्भ में खाद्य निरीक्षक से स्पष्टीकरण भी मांगा था. मामले के तूल पकड़ने के बाद राज्य सरकार ने खाद्य निरीक्षकों की एक तीन सदस्यीय टीम पूर्णिया प्रमंडल के ज़िलों में जांच के लिए भेजी, लेकिन नतीजा सिफर रहा. इस संबंध में स्थानीय लोगों का कहना था कि टीम अररिया, कटिहार एवं किशनगंज गई और जांच के नाम पर खानापूर्ति करते हुए बड़े पैमाने पर उगाही करके चलते बनी. लोग बताते हैं कि पूर्णिया के जिस होटल में यह टीम रुकी थी, वहां सुबह–शाम व्यापारियों का जमावड़ा लगा रहता था. जानकारी के अनुसार, इस समय फारबिसगंज एवं किशनगंज में भी नक़ली सरसों का तेल बनाने वाले कारखाने चल रहे हैं.

लगातार प्रशासनिक दबाव के चलते नकली सरसों का तेल बनाने–बेचने वाले कारोबारियों ने निकटवर्ती पश्चिम बंगाल के सोनापुर, रायगंज, दालकोला, कानकी, इस्लामपुर, सिलीगुड़ी और रामगंज को अपना नया ठिकाना बना लिया है. उन्होंने मध्य प्रदेश के मुरैना, उत्तर प्रदेश के कानपुर और हरियाणा के हिसार तक अपना कारोबार फैला लिया है. जानकारी के अनुसार, उत्तरी बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर ज़िले के अंतर्गत सोनापुर में कमल फूल, रामगंज में कल्याणी, कानकी में कमल एवं दालकोला और रायगंज में विभिन्न ब्रांड नामों से नकली सरसों के तेल की पैकिंग होती है. मध्य प्रदेश के मुरैना में यही काम डबल शेर, टाईगर, टेलीफोन, सीपी परमात्मा और कलश आदि ब्रांड नामों से होता है. पश्चिम बंगाल के हल्दिया और मध्य प्रदेश के इंदौर में राइस ऑयल का कारखाना है. बाज़ार में धान की भूसी की क़ीमत बारह सौ से लेकर चौदह सौ रुपये प्रति कुंतल है और विभिन्न ब्रांडों के सरसों के तेल के खाली कनस्तर भी सस्ते दामों पर मिल जाते हैं. इस तरह नक़ली तेल बनाने का गोरखधंधा धड़ल्ले से चल रहा है और जनस्वास्थ्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है.

नियमानुसार डिब्बे/कनस्तर पर तेल में मौजूद तत्वों की मात्रा, बैच नंबर और पैकिंग की तिथि आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि सरसों के तेल की गुणवत्ता छह मास तक ही रहती है. बावजूद इसके बाज़ार में कुछ ऐसे भी ब्रांड मौजूद हैं, जिन पर इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षकों ने चुप्पी साध रखी है. सीमांचल और उससे सटे बंगाल में भी सरसों की अच्छी खेती होती है, इसीलिए स्थानीय लोग अक्सर सवाल करते हैं कि यहां के व्यवसायी देश के दूसरे हिस्सों को छोड़कर केवल मुरैना से ही सरसों का तेल क्यों मंगाते हैं. वहीं व्यापारियों का कहना है कि वे लोगों की क्रय क्षमता को ध्यान में रखते हुए ऐसा करते हैं.

बहरहाल सरसों के तेल में मिलावट इस कदर बढ़ गई है कि बड़ी संख्या में लोग असमय उदर विकार, अल्सर और गैस्टिक आदि से पीड़ित हो रहे हैं. ज़रूरत है, लोगों में जागरूकता पैदा करने और कठोर क़ानून बनाने की, जिससे मिलावटखोरों को सज़ा मिल सके. सदर अनुमंडल पदाधिकारी कुंदन कुमार सिंह ने भरोसा दिलाया है कि ऐसा कोई भी मामला प्रकाश में आने पर दोषियों के विरुद्ध कठोर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

feedback@chauthiduniya.com

बिहार पहला राज्य है, जिसने महिलाओं को पंचायतीराज संस्था में 50 फ़ीसदी आरक्षण दिया, लेकिन इस व्यवस्था का भी जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है.

बिहार पंचायत चुनाव

सत्ता नहीं, भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण

- महिला आरक्षण का फ़ायदा उठाते हैं मुखिया पति
- ग्रामसभा की बैठक पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं होती
- जातीय आरक्षण से ग्रामीण राजनीति में हिंसा का जन्म
- लूट-खसोट में जन प्रतिनिधि और अफसर शामिल

सत्ता का मूल चरित्र ही कुछ ऐसा होता है कि जिसके पास यह होती है, उसे मदहोश और भ्रष्ट बनाती है और जिसके पास नहीं होती, उसे ललचाती है. केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक के होने वाले चुनाव और उस दौरान घटने वाली प्रत्येक घटना से यही साबित होता है. दूसरी ओर जब सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात आती है, तब सत्ता के इस मूल चरित्र का भी विकेंद्रीकरण होता दिखाई देता है. इसका एक बेहतरीन उदाहरण पंचायत चुनाव है. सत्ता के विकेंद्रीकरण के नाम पर पंचायतीराज संस्थाओं का गठन हुआ. सत्ता का सचमुच कितना विकेंद्रीकरण हुआ, इस पर कई शोध किए गए और अब भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही बेईमानी, भ्रष्टाचार और लूट–खसोट का भी विकेंद्रीकरण ज़बरदस्त ढंग से हो गया. यानी कल तक पैसों की जो बंदरबाट सिर्फ केंद्र–राज्य के बीच होती थी, अब उसमें एक और नया हिस्सेदार पैदा हो गया है, जिसका नाम है पंचायतीराज संस्थाएं.

शशि शेखर

बिहार में पंचायत चुनाव अंतिम चरण में पहुंच चुका है. लगभग ढाई लाख से ज़्यादा जनप्रतिनिधियों, जिनमें आठ हज़ार से ज़्यादा मुखिया के पद हैं, के चुनाव के लिए मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. इन्हीं जनप्रतिनिधियों और ख़ासकर मुखियाओं पर ग्राम विकास की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन जिस पंचायतीराज संस्था के ज़रिए गांधी जी ने रामराज का सपना देखा था, वह बिखर चुका है. कम से कम बिहार की पंचायतीराज संस्थाओं की हालत तो ऐसी ही है. चौथी दुनिया ने पंचायत चुनाव शुरू होने से पहले बिहार के कुछ क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों का दौरा किया, लोगों से बातचीत की. इस बातचीत के दौरान लूट–खसोट के कुछ ऐसे हैरतअंगेज तरीक़ों के बारे में जानकारी मिली कि अमूमन उसके बारे में दिल्ली–मुंबई में बैठे लोग सोच भी नहीं सकते. मुखियाओं द्वारा पैसा कमाने के ये अजीबोग़रीब हथकंडे दरअसल पंचायतीराज व्यवस्था का मज़ाक उड़ाते नज़र आते हैं. मसलन, गया ज़िले के टिकारी प्रखंड की एक पंचायत के लोग बताते हैं कि इंदिरा आवास योजना के तहत लाभांवितों के चयन के बाद उनका बैंक में खाता खुलता है, जिसमें उनके हिस्से का पैसा किस्तों में आता है. यहां तक तो सब ठीकठाक चलता है, लेकिन जब एक ग़रीब आदमी अपने हिस्से का पैसा लेने बैंक पहुंचता है तो बैंक अधिकारी यह कहकर उसे पैसा नहीं देते कि जब तक मुखिया जी नहीं आएंगे, तब तक पैसा नहीं मिल सकता. इसके बाद बाकायदा मुखिया जी आते हैं और उनके आदेश के बाद पहली किस्त उस ग़रीब आदमी को मिलती है. बैंक से बाहर निकलने पर मुखिया जी अपने गुर्गों के साथ तैयार मिलते हैं. उस आदमी को मिले पैसों में से एक बड़ा हिस्सा मुखिया जी ले लेते हैं. कई बार प्यार से, कई बार ज़बरदस्ती. इससे भी काम नहीं बना तो रास्ते में ही उस आदमी से पैसा छीन लिया जाता है. ज़ाहिर है, इस तरह की लूट प्रखंड से लेकर ज़िला स्तर तक के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं हो सकती.

बिहार पहला राज्य है, जिसने महिलाओं को पंचायतीराज संस्था में 50 फ़ीसदी आरक्षण दिया, लेकिन इस व्यवस्था का भी जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है. आरक्षण दिए जाने के बाद से बिहार में एक नया शब्द प्रचलित हुआ, एमपी यानी मुखिया पति. इसका अर्थ यह है कि जिस पंचायत में महिला आरक्षण है, वहां की मुखिया तो कोई महिला ही होगी, लेकिन सिर्फ़ दिखावे के लिए. हस्ताक्षर भर करने के लिए. असल में सारा काम उस मुखिया का पति ही करता है. बाकायदा चुनाव प्रचार में मुखिया प्रत्याशी के साथ–साथ मुखियापति का भी फोटो छपता है. जातिगत आधार पर मिले आरक्षण की वजह से भी गांवों में जातीय गोलबंदी उभर कर सामने आई है. पिछले दस सालों में स्थानीय राजनीति में वर्चस्व क़ायम करने के नाम पर काफी ख़ूनखराबा भी हुआ.

ग्रामसभा एक संवैधानिक संस्था, जिसके सहारे गांधी जी के स्वराज का सपना पूरा करने की कोशिश की गई थी. सोच यह थी कि ग्रामसभा जनता यानी लोक को तंत्र से ज़्यादा मज़बूत बनाएगी. पंचायतीराज में जनता जो चाहेगी, वही होगा, पंच का फ़ैसला परमेश्वर का फ़ैसला होगा. नियमत: पंचायत का हर फ़ैसला ग्रामसभा की बैठक में ही लेना होता है, लेकिन शायद ही बिहार की कोई ऐसी पंचायत होगी, जहां नियमित और पारदर्शी ढंग से ग्रामसभा की बैठक होती हो. मुखिया ग्रामसभा की खुली बैठक न कराने के लिए तरह–तरह की कोशिशें करता है. मुज़फ्फरपुर की एक पंचायत में लोगों ने बताया कि एक बार मुखिया ने गांववालों को यह कहकर पंचायत भवन में बुलाया कि स्वास्थ्य से जुड़ी एक योजना के लिए सभी लोगों का फोटो खींचा जाएगा. गांव के लोग वहां पहुंचे. फोटो भी खींचा गया. इसके बाद सभी लोगों से एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने को कहा गया. लोगों ने हस्ताक्षर भी कर दिए. इसी बीच एक बुजुर्ग, जो पूर्व में मुखिया रह चुके थे, अचानक रजिस्टर को ग़ौर से देखने लगे. उस रजिस्टर में ग्रामसभा की कार्यवाही दर्ज की गई थी और गांव के लोगों यानी ग्रामसभा के सदस्यों से सहमति के तौर पर दस्तख़त कराए जा रहे थे. तब जाकर इस गड़बड़झाले का भंडाफोड़ हुआ.

अब सवाल यह है कि ऐसी विकेंद्रीकृत व्यवस्था का लाभ आम आदमी तक कैसे पहुंचेगा? तंत्र कुर्सी पर बैठता है और लोक ज़मीन पर, तंत्र क़ानून बनाता है और लोक उसका पालन करता है! आख़िर क्यों बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ऐसे सवालों और पंचायतीराज संस्था की हक़ीक़त से आंख चुराना चाहते हैं? 50 फ़ीसदी आरक्षण के मसले पर तो ख़ुद वह अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन पंचायतीराज संस्था में घुसे भ्रष्टाचार पर उनका डंडा क्यों नहीं चलता? क्यों ग्रामसभा अपने वास्तविक स्वरूप में बैठकर निर्णय नहीं लेती? सरकार क्यों नहीं ऐसे नियम बनाती, जो पंचायत स्तर पर जन प्रतिनिधि को बाध्य करे कि वह ग्रामसभा के निर्णय के अनुसार चलना शुरू करे? नीतीश कुमार कह चुके हैं कि केंद्र हम पर अपनी योजनाएं न थोपे, लेकिन क्या यही सवाल गांव की ओर से राज्य के लिए नहीं उठते. आज शासन में हिस्सेदारी के नाम पर जनता के पास क्या है, सिवाय 5 साल में एक बार वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनने के. असल में राजनीतिक दल जनता को अधिकार देने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से विधायकों और सांसदों का महत्व ख़त्म हो जाएगा. यही सोच सारी समस्याओं की जड़ है. ऐसे में देश के नीति निर्माताओं को फिर से अपनी ही बनाई योजनाओं और नीतियों पर पुनर्विचार करना होगा. यह सोचना होगा कि क्या सचमुच जिस पंचायतीराज संस्था को उन्होंने खड़ा किया, वह गांधी जी के रामराज, स्वराज या कहें कि जनता का राज स्थापित कर पाएगी.

shashishekhar@chauthiduniya.com

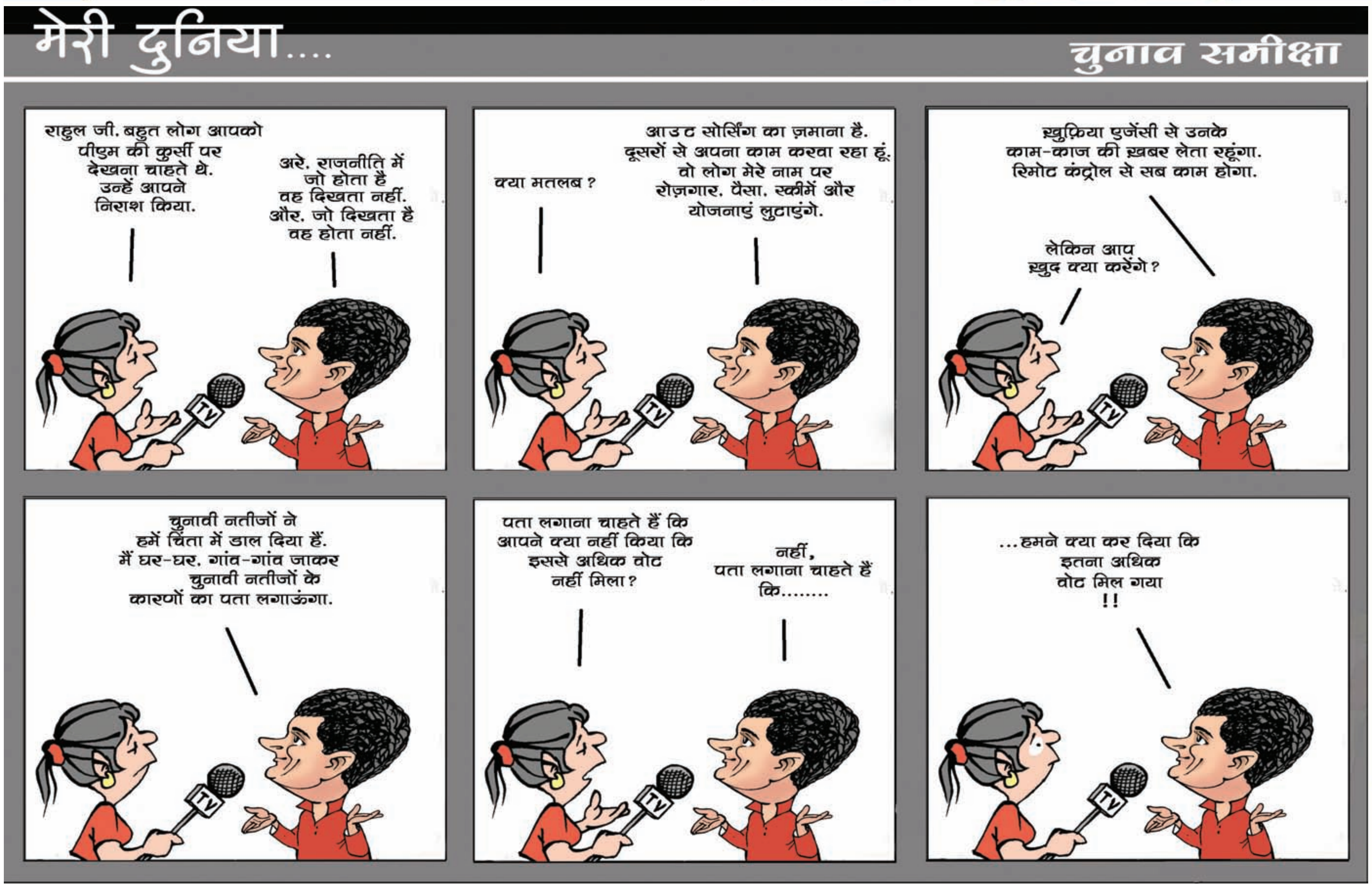

केरल के कासरगोड़ ज़िले में पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसकेइस्तेमाल से कई लोगों की मौत हुई है और बड़ी संख्या में लोग बीमारियों की चपेट में आए हैं.

अब तो मां का दूध भी ज़हर हो गया

फ़िरदौस ख़ान

देश की नदियों की हालत बेहद ख़राब है. इनमें गंगा, यमुना, दामोदर, सोन, कावेरी, नर्मदा एवं साही आदि शामिल हैं. गंगा जैसी पवित्र नदी भी प्रदूषण की शिकार होकर दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में शामिल हो गई है. इसका 23 फ़ीसदी जल प्रदूषित हो चुका है. एक रिपोर्ट के मुताबिक़, यमुना में 7.15 करोड़ गैलन गंदा पानी रोज़ छोड़ा जाता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मानें तो यमुना का पानी नहाने के क़ाबिल भी नहीं रहा है.

देश की सोना उगलने वाली कृषि भूमि और पानी तो प्रदूषित हो ही चुका है, मगर अब मां के अमृत रूपी दूध में भी विषैले तत्व पाए गए हैं. महाराष्ट्र के रत्नागिरी के चिपलुन के डीबीजे कॉलेज के जिओलॉजी विभाग के एक अध्ययन के मुताबिक़, मां के दूध में रसायनों की मात्रा ख़तरनाक स्तर तक पाई गई है. विभाग ने कोटावली सहित इलाक़े के सात गांवों अवाशी, लोटे, गुनाडे, गनुकंड, सोनगांव और पीरलोटे में वर्ष 2003 से 2004 के बीच अध्ययन किया. पशुओं के दूध में सीसे की मात्रा 3.008 पीपीएम पाई गई, जबकि इसकी उचित मात्रा 0.1 है. इसी तरह मां के दूध में भी एल्यूमिनियम की मात्रा 5.802 पीपीएम दर्ज की गई, जबकि इसकी मात्रा 0.3 होनी चाहिए. इसके अलावा दूध में क्रोमियम, निकल और आयरन भी पाया गया. ज़िले के 575 हेक्टेयर इलाक़े में 70 औद्योगिक इकाइयां हैं. इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले औद्योगिक कचरे को पानी में बहा दिया जाता है. इसके कारण इलाक़े के जलस्रोतों का पानी अत्यधिक विषैला हो गया है. हालत यह है कि मछलियां भी दम तोड़ने लगी हैं. पानी के अलावा इलाक़े की भूमि भी ज़हरीली होती जा रही है. दूध में रसायनों का अधिक मात्रा में पाया जाना बेहद चिंता का विषय है. अगर यही हालत रही तो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाने से भी डरने लगेंगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से मां का दूध बच्चे के लिए अमृत समान होता है, जो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, लेकिन प्रदूषण मां के दूध को भी ज़हर में बदल रहा है.

देश की नदियों की हालत बेहद ख़राब है. इनमें गंगा, यमुना, दामोदर, सोन, कावेरी, नर्मदा एवं साही आदि शामिल हैं. गंगा जैसी पवित्र नदी भी प्रदूषण की शिकार होकर दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में शामिल हो गई है. इसका 23 फ़ीसदी जल प्रदूषित हो चुका है. एक रिपोर्ट के मुताबिक़, यमुना में 7.15 करोड़ गैलन गंदा पानी रोज़ छोड़ा जाता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मानें तो यमुना का पानी नहाने के क़ाबिल भी नहीं रहा है. हालांकि बोर्ड नदी की सफ़ाई के नाम पर 1800 करोड़ रुपये ख़र्च कर चुका है. अब वह 15 करोड़ रुपये और ख़र्च करने की योजना बना रहा है. सुप्रीम कोर्ट भी यमुना में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंतित है. वर्ष 1985 में यमुना में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाख़िल की गई थी. इस पर 1989 में अदालत ने सरकार को यमुना को साफ़ करने का निर्देश दिया था. हालांकि अनेक एजेंसियां और संस्थाएं नदी की सफ़ाई की मुहिम में शामिल हुईं, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात ही रहा. कारख़ानों द्वारा दामोदर नदी में भी 40 लाख गैलन विषैला पानी छोड़ा जाता है. चेन्नई की दो करोड़ गैलन गंदगी नदियों को दूषित करती है. इसी तरह धरती के स्वर्ग कश्मीर की राजधानी श्रीनगर का गंदा पानी झेलम नदी को दूषित कर रहा है. वर्ष 1940 में जहां एक लीटर पानी में ऑक्सीजन की मात्रा 2.5 घन सेंटीमीटर थी, वहीं अब यह घटकर महज़ 0.1 घन सेंटीमीटर रह गई है. काग़ज, चर्मशोधन, खनिज एवं कीटनाशक आदि के कारख़ाने नदियों के किनारे हैं. कारख़ानों से निकलने वाले रासायनिक कचरे और शहरों की गंदगी को नदियों में बहा दिया जाता है. देश में अमूमन हर साल 10 लाख लोगों पर पांच लाख टन मल उत्पन्न होता है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा समुद्र और नदियों में छोड़ दिया जाता है. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में एक लाख से ज़्यादा आबादी वाले 142 शहरों में से सिर्फ़ आठ शहर ही ऐसे हैं, जिनमें मल प्रबंधन की पूरी व्यवस्था है, जबकि 62 शहरों में हालत कुछ ठीक है और 72 शहर तो ऐसे हैं, जहां मल प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं है. इसलिए छुटकारा पाने के लिए इसे नदी-नालों के हवाले कर दिया जाता है. नदियों का 70 फ़ीसदी जल प्रदूषित है. इस प्रदूषित जल में बैक्टीरिया, पारा, सीसा, ज़िंक, क्रोमाइट और मैगनीज़ के तत्व भारी मात्रा में पाए जाते हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक़, हर साल पांच लाख बच्चे जल प्रदूषण के शिकार होते हैं. भारत में 30 से 40 फ़ीसदी लोगों की मौत प्रदूषित जल के कारण होती है. प्रदूषित जल की वजह से लोग अनेक भयंकर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं. हालांकि जल प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम बनाया था, मगर इसके बावजूद नदियों की हालत बद से बदतर होती जा रही है.

प्रदूषित जल की वजह से पंजाब के फ़िरोज़पुर ज़िले के तेजा रूहेला, नूरशाह, डोना नांका और खदूका आदि गांवों के बच्चे या तो दृष्टिहीन पैदा हो रहे हैं या जन्म से कुछ वक़्त बाद अपनी आंखों की रोशनी खो रहे हैं. कुछ वक़्त पहले गांव डोना नांका के करीब एक दर्जन बच्चे अंधेपन का शिकार हुए. इसी तरह गांव नूरशाह और तेजा रूहेला के क़रीब 50 लोग अंधेपन की चपेट में आए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं. पंजाब के भूजल में यूरेनियम भी पाया गया है. इसकी वजह से दक्षिणी-पश्चिमी पंजाब के बच्चे सेरेबल पाल्सी से पीड़ित हो रहे हैं. जर्मनी की माइक्रो ट्रेस मिनेरल लैब की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, फ़रीदकोट में मंदबुद्धि बच्चों की संस्था बाबा फ़रीद केंद्र के 150 बच्चों के बालों पर शोध किया गया. इन बच्चों के बालों में 82 से 87 फ़ीसदी तक यूरेनियम पाया गया. पंजाब के भटिंडा, संगरूर, मंसा और मोगा आदि इलाक़ों के पानी में भी यूरेनियम पाया गया है. भटिंडा ज़िले के पानी में यूरेनियम की सांद्रता 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक पाई जा चुकी है, जबकि इसका उचित मानक स्तर 9 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है.

प्रदूषित जल के कारण मिट्टी में भी हानिकारक तत्व पाए जा रहे हैं. इसके अलावा कीटनाशकों ने भी भूमि को ज़हरीला बनाने का काम किया है. ऐसे ही एक कीटनाशक एंडोसल्फान को लेकर पिछले काफ़ी वक़्त से देश में मुहिम चल रही है. एंडोसल्फान बेहद ज़हरीला रसायन है. एंडोसल्फान को 1950 से पहले ही विकसित कर लिया गया था, लेकिन इसे 1950 में पेश किया गया. यह हेक्साक्लोरो साइक्लोपेंटाडीन का व्यापारिक नाम है. हालांकि अब तक इसका पेटेंट नहीं किया गया है. इसके बेहद ज़हरीले होने की वजह से यूरोपीय संघ सहित 81 देशों ने इस पर पाबंदी लगाई है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक़, पूरी दुनिया में 1990 के दशक तक इसका सालाना उत्पादन 12,800 टन को पार कर गया था. भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है, जहां सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइट्स लिमिटेड, एक्सेल क्रॉप केयर और कोरोमंडल फर्टिलाइजर मिलकर क़रीब 8,500 टन एंडोसल्फान बना रही हैं. वैसे अपने देश में 2001 से ही इसके इस्तेमाल पर बहस चल रही है.

हाल में जिनेवा में आयोजित स्टॉकहोम कन्वेंशन में एंडोसल्फान पर विश्वव्यापी प्रतिबंध लगाने पर ज़ोर दिया गया. संबंधित पक्षों ने दुनिया भर में कुछ अपवादों को छोड़कर एंडोसल्फान और उसके अपरूपों का उत्पादन और इस्तेमाल ख़त्म करने का एक प्रस्ताव पारित किया. हालांकि यह फ़ैसला भारत में तभी लागू होगा, जब सरकार इसे मंज़ूरी दे. भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है. समीक्षा समिति कन्वेंशन में शामिल पक्षों और पर्यवेक्षकों के साथ विचार-विमर्श कर एंडोसल्फान के विकल्प सुझाएगी. साथ ही कन्वेंशन विकासशील देशों को एंडोसल्फान का विकल्प अपनाने के लिए वित्तीय मदद भी देगी. प्रस्ताव में कुल 22 फ़सलों के लिए छूट दी गई है, जिनमें गेहूं, धान, चना, सरसों, मूंगफली, कपास, जूट, कॉफ़ी, चाय, तंबाकू, टमाटर, प्याज़, आलू, मिर्च, आम और सेब आदि शामिल हैं. सम्मेलन में 12 कीटनाशकों पर पाबंदी लगाई गई. इसी फ़ेहरिस्त में एंडोसल्फान को भी शामिल करने पर विचार किया जा रहा है.

केरल के कासरगोड़ ज़िले में पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसकेइस्तेमाल से कई लोगों की मौत हुई है और बड़ी संख्या में लोग बीमारियों की चपेट में आए हैं. ज़िले के जिन गांवों में एंडोसल्फान का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां के लोग दिमाग़ी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं. राज्य में एंडोसल्फान को प्रतिबंधित कर दिया गया. कर्नाटक में भी एंडोसल्फान पर पाबंदी लगी हुई है और आंध्र प्रदेश में भी इसे प्रतिबंधित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है. केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा ने एंडोसल्फान पर देशव्यापी पाबंदी लगाने की मांग को लेकर हड़ताल भी की. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदुरप्पा ने भी एंडोसल्फान पर पाबंदी लगाए जाने की वकालत की है. भारतीय जनता पार्टी ने भी एंडोसल्फान पर पाबंदी लगाने की मांग की है. राज्य में कांग्रेस एंडोसल्फान पर प्रतिबंध लगाए जाने का समर्थन कर रही है, लेकिन उसने एलडीएफ की हड़ताल की आलोचना की. हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री वी एस अच्युतानंदन ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर समर्थन मांगा है. इस मामले में ख़ुद अच्युतानंदन एक दिन का अनशन कर चुके हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने एंडोसल्फान पर पाबंदी लगाने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सहित सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की युवा इकाई डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि एंडोसल्फान का मानव विकास पर बुरा असर पड़ता है और कई अध्ययनों में यह बात सामने आ चुकी है. याचिका में केरल के कासरगोड़ ज़िले का भी ज़िक्र किया गया है. यहां के बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास रुक गया है. यहां पिछले दो दशकों से काजू की खेती में इसका छिड़काव किया जा रहा है.

केरल के कृषि मंत्री मुल्लाकरा रत्नकरण के मुताबिक़, एक कीटनाशक के इस्तेमाल से अनाज ख़राब हो गया था और उसे खाने से क़रीब सौ लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 800 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए थे. इसके बाद 1968 में कीटनाशक अधिनियम बनाया गया. केरल विधानसभा में विपक्षी नेता ओमान चांडी और केपीसीसी केअध्यक्ष रमेश चेन्निथला ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाक़ात की थी. इसके बाद पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया कि केरल में एंडोसल्फान का इस्तेमाल प्रतिबंधित है. हालांकि इस पर देशव्यापी पाबंदी लगाने का फ़ैसला वैज्ञानिक अध्ययन और राष्ट्रीय सहमति केआधार पर लिया जाएगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के डायरेक्टर जनरल की अध्यक्षता में एक समिति लोगों की सेहत पर एंडोसल्फान के दुष्प्रभाव की जांच कर रही है.

कृषि मंत्री शरद पवार यह स्वीकार करते हैं कि एंडोसल्फान सेहत के लिए बेहद ख़तरनाक है, लेकिन साथ ही वह यह भी कहते हैं कि इस पर देशव्यापी पाबंदी लगाना व्यवहारिक नहीं है. उन्होंने यहां तक कह दिया कि केरल के हालात के लिए वहां के किसान ही ज़िम्मेदार हैं, जो जानबूझ कर एंडोसल्फान का छिड़काव कर रहे हैं. हालांकि पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने एंडोसल्फान पर पाबंदी लगाने की मांग कर रहे राज्यों को भरोसा दिलाया है कि अगर अध्ययन में इसके हानिकारक होने के सबूत मिलते हैं तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. हैरानी की बात तो यह है कि सरकार को ज़हर को ज़हर साबित करने के लिए भी सबूतों की ज़रूरत पड़ रही है.

अगर यह कहा जाए कि सरकार जनता की जान को जोखिम में डालकर एंडोसल्फान की निर्माता कंपनियों के हित साधने में लगी है तो ग़लत नहीं होगा. ख़ास बात यह भी है कि कुछ वक़्त पहले पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति कह चुकी है कि इसके इस्तेमाल से मानव स्वास्थ्य पर किसी भी तरह का ग़लत असर नहीं पड़ेगा. देश की जनता के साथ इससे बड़ा मज़ाक़ भला क्या हो सकता है. एंडोसल्फान पर पाबंदी को लेकर कई झोल हैं. पहला, सरकार द्वारा कंपनियों को लाभ पहुंचाना और दूसरा, किसानों को इसका विकल्प मुहैया कराना. देश में 70 से ज़्यादा फ़सलों में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है. यह अकेला ऐसा कीटनाशक है, जिसका प्रतिरोध फ़सलों को नुक़सान पहुंचाने वाले कीट अभी तक नहीं कर पाए हैं. इसी वजह से इसकी ख़ूब बिक्री होती है. किसानों की भी यह मजबूरी है कि उनके पास इसका कोई विकल्प मौजूद नहीं है. ऐसे में यह सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह किसानों को इसका विकल्प मुहैया कराए, क्योंकि उसके बिना इस पर पाबंदी का भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा. प्रतिबंध लगने के बावजूद यह चोरी-छुपे महंगे दामों पर बिकने लगेगा, जिससे सबसे ज़्यादा नुक़सान किसानों को ही होगा.

firdaus@chauthiduniya.com

भारत जैसे विशाल देश के कई राज्यों से प्रायः ऐसी ख़बरें मिलती हैं कि लोग भीषण गर्मी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे.

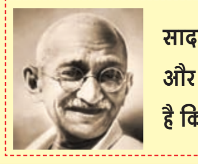
सादा जीवन जीने वाले नेता ही सत्य पर आधारित और अहिंसक आंदोलन चला सकते हैं. यही कारण है कि यह देश दूसरा गांधी पैदा नहीं कर सका.

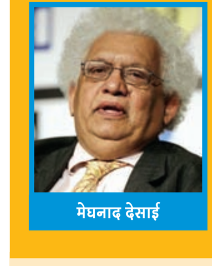
मेघनाद देसाई

गठबंधन के ख़तरे और फ़ायदे

शाही शादी दरअसल गंभीर राजनीतिक क्रियाकलापों से ध्यान हटाने या कहें कि मन बहलाने की एक घटना थी. जब कंजरवेटिव और लिबरल डेमोक्रेट के बीच गठबंधन के लिए समझौता चल रहा था, तब इसका परिणाम एक ऐसी औपचारिक सहमति के रूप में सामने आया, जिसके आधार पर उनकी सारी नीतियां निर्धारित होने वाली थीं. इसमें लिबरल डेमोक्रेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण वह वादा था, जिसमें वोटिंग सिस्टम के संबंध में जनमत संग्रह कराने की बात थी. लिबरल्स वोटिंग सिस्टम को लेकर बहुत पहले से ही आसक्त रहे हैं. इनकी शिकायत रही है कि हर चुनाव में इन्हें मिलने वाले वोट (लगभग 20 फ़ीसदी) के मुताबिक़ सीटें नहीं मिलतीं. इसके लिए वे एफपीटीपी (फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो भारत में भी अपनाया जाता है) को दोष देते हैं. दरअसल इस सिस्टम के तहत सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार जीत जाता है, भले ही उसे कुल पड़े मतों का एक ख़ास यानी तय हिस्सा न मिले. उनका कहना है कि बहुकोणीय मुक़ाबले में जीतने वाले उम्मीदवार प्राय: 51 फ़ीसदी से कम वोट पाकर जीतते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि ज़्यादातर मतदाता जीतने वाले उम्मीदवार के ख़िलाफ़ हैं, फिर भी वह जीत जाता है. इस वजह से बड़ी पार्टियां ज़्यादा सीटें पा जाती हैं. छोटी पार्टियों में यह संदेश जाता है कि मतदाता उन्हें अपना वोट इसलिए नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका वोट बर्बाद चला जाएगा. ज़ाहिर है, इस सबके पीछे वास्तविक वजह है पार्टियों के आकार एवं चुनाव क्षेत्रों का असमान होना और मतदाताओं के बीच बेतरतीब रूप से पार्टियों को मिलता समर्थन. भारत में भी अगर 1977 का उदाहरण छोड़ दें तो सत्ता पर एक ही दल का क़ब्ज़ा रहा. कांग्रेस को 40 फ़ीसदी वोट और इसके बदले 65 फ़ीसदी से भी ज़्यादा सीटें मिलती थीं.

जनमत संग्रह के माध्यम से एफपीटीपी और एवी यानी अलटर्नेटिव वोटिंग में से किसी एक का चुनाव किया जाना है. अलटर्नेटिव वोटिंग का अर्थ है कि आप उम्मीदवारों को एक क्रम में चुनते हैं. यदि सबसे ऊपर के उम्मीदवार को प्रथम वरीयता के तौर पर 51 फ़ीसदी मत नहीं मिलते हैं तो सबसे कम मत पाने वाले उम्मीदवार को हटाकर एक बार फिर यह सारी प्रक्रिया दोहराई जाती है. यानी फिर से उम्मीदवारों को वरीयता के आधार पर चुनने की प्रक्रिया. यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, जब तक किसी उम्मीदवार को 51 फ़ीसदी से ज़्यादा मतदाता प्रथम वरीयता के आधार पर चुन नहीं लेते. जनमत संग्रह का अभियान काफ़ी पेचीदा है. गठबंधन के सहयोगियों ने निर्णय लिया है कि हर कोई अपने तरीक़े से वोट करने के लिए स्वतंत्र होगा. कंज़रवेटिव अलटर्नेटिव वोटिंग को पसंद नहीं करते. लेबर पार्टी में इस मामले पर विभाजन दिख रहा है. उसने चुनाव से पहले जनमत संग्रह का वादा किया था, लेकिन चुनाव हारने के बाद वह आधिकारिक रूप से इस मसले से अलग हो गई. इनमें से कुछ, जो इसका समर्थन नहीं करते. दोनों ओर काफ़ी गर्माहट दिखी. नहीं का विकल्प जीत की स्थिति में होने की वजह से आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी चला. लिबरल डेमोक्रेट नेता और उप प्रधानमंत्री निक क्लेग ने अलटर्नेटिव वोटिंग के विरोधियों पर आरोप लगाया कि वे दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी षड्यंत्र को बचाए रखना चाहते हैं.

लिबरल डेमोक्रेट्स की लोकप्रियता भी घटी है, क्योंकि उनकी छवि प्रगतिशील वामपंथी की थी, लेकिन वह उन्हें कंज़रवेटिव के साथ हाथ मिलाता हुआ देख आश्चर्य में पड़ गए. उन्हें मुफ़्त उच्च शिक्षा जैसा अपना महत्वपूर्ण एजेंडा तक छोड़ना पड़ा. निक क्लेग की लोकप्रियता कम होने के पीछे यह वजह भी थी और इसने अलटर्नेटिव वोटिंग के समर्थन में वोट पड़ने की संभावना को भी कम कर दिया. अलटर्नेटिव वोटिंग के ख़िलाफ़ पड़ने वाले वोटों की संख्या ज़्यादा होने की स्थिति में लिबरल डेमोक्रेट्स को अपनी पार्टी के भीतर आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है. [illegible] संभव है कि वे सरकार से बाहर निकल जाएं और अगले चुनाव [illegible] संभावना है कि कंज़रवेटिव साधारण बहुमत से सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए.

अभी सिर्फ़ टोरीज़ ही ऐसे हैं, जिनके पास चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त धन है. लेबर पार्टी क़र्ज़ में डूबी हुई है (ब्रिटिश राजनीतिक दलों को अपना अकाउंट सार्वजनिक करना पड़ता है, यहां काले धन की कोई गुंजाइश नहीं है).

बहरहाल, यह डेविड कैमरन का मास्टर स्ट्रोक ही कहा जाएगा कि उन्होंने लिबरल डेमोक्रेट्स के साथ गठबंधन किया, जोखिम लिया और इसका फ़ायदा भी उठाया. इस कहानी का संदेश स्पष्ट है. अपने बेटे को पढ़ने के लिए एटन भेजें और वह वहां सीख जाएगा कि देश पर शासन कैसे करते हैं. तो दून स्कूल हमें इस तरह से क्यों आश्वस्त नहीं कर पाता?

feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

रामदेव जी, आपका सत्याग्रह कैसा होगा

देश एक कन्फ्रंटेशन की ओर बढ़ रहा है. कन्फ्रंटेशन देश के हित में है या नहीं है, अभी यह नहीं कह सकते हैं, पर कन्फ्रंटेशन क्यों और किस तरह का होने वाला है, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए. भ्रष्टाचार इन दिनों देश में केंद्रीय विषय बना हुआ है और अन्ना हजारे, जिनकी वजह से देश में एक जागृति आई, देश भर में घूमने की योजना बना रहे हैं. उत्तर प्रदेश में कई जगह उन्हें जाना था, लेकिन वह नहीं जा पाए, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें मना कर दिया. अगर डॉक्टर अनुमति नहीं देते हैं तो कार्यक्रम नहीं देना चाहिए और अगर कार्यक्रम देते हैं तो चाहे कितने भी बीमार हों, वहां पर पहुंचना चाहिए. इस संबंध में अगर कोई उदाहरण देना हो तों वह विश्वनाथ प्रताप सिंह का देना चाहिए. वह एक दिन डायलिसिस कराते थे और अगले दिन इस हालत में नहीं होते थे कि कहीं जाएं. लेकिन अगर उन्होंने कार्यक्रम दे दिया तो वह ज़रूर जाते थे. सुबह जाते थे देश के किसी भी कोने में, जहां से वह हवाई जहाज से शाम को वापस आ जाते थे और अगले दिन फिर डायलिसिस कराते थे. बाबा रामदेव, जिन्होंने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई को अपनी ओर से अपने कंधों पर ले लिया है, सारे देश में घूम-घूमकर लोगों को तैयार कर रहे हैं कि वे भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई में उनका साथ दें. बाबा रामदेव आगामी 4 जून से दिल्ली में एक लाख से दस लाख के बीच लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं और उनके साथ सत्याग्रह पर बैठना चाहते हैं. उनका कहना है कि सारे देश में 10 करोड़ लोग उनके साथ सत्याग्रह करेंगे. सत्याग्रह शब्द गांधी जी का दिया हुआ है. गांधी जी ने सत्याग्रह को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और अंग्रेजों के ख़िलाफ़ इस हथियार से सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी.

गांधी जी का मानना था कि साध्य जैसा हो, वैसा ही साधन भी होना चाहिए. उदाहरण के रूप में उनका मानना था कि अगर आज़ादी पानी है तो उसका साधन भी ऐसा होना चाहिए कि जिससे आज़ादी मिल सके. वह हिंसा या हथियारों के ज़रिए आज़ादी मिलते हुए नहीं देख पा रहे थे. इसलिए उन्होंने अहिंसा का रास्ता चुना. इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह के कई रूप सामने रखे और लोगों को उसमें शामिल किया. जैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, असहयोग सत्याग्रह आदि-आदि. गांधी जी किसी भी सत्याग्रह से पहले उसके नियम-क़ानून लोगों के सामने रखते थे और कहते थे कि जो भी इनका पालन करने की क्षमता रखे, साहस रखे, वही उनके सत्याग्रह में शामिल हो. अगर आज़ादी के आंदोलन की कहानियां दिमाग़ में आ रही हैं तो यह आसानी से समझा या देखा जा सकता है कि किस तरह आज़ादी पाने के सत्याग्रह में अंग्रेज पुलिस का सामना सत्याग्रही ख़ामोश होकर, डंडे खाकर भी करते थे और हमला नहीं करते थे. पुलिस डंडे चलाती थी, सत्याग्रही झंडा हाथ में लिए हुए झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गाते रहते थे. जो लोग ऐसा नहीं करते थे, उनसे गांधी जी कह देते थे कि आप हमारे आंदोलन में न रहें. चौरीचौरा इसका उदाहरण है. शांतिपूर्ण सत्याग्रह था, लेकिन चौरीचौरा में पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई, जिसमें कुछ लोग जलकर मर गए. गांधी जी ने सत्याग्रह वापस ले लिया. गांधी जी ने देश को एक अनुशासित, अहिंसक लड़ाई के लिए तैयार किया था और सालों की मेहनत के बाद तैयार किया था. उस सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल बाबा रामदेव अब कर रहे हैं.

हमारा अनुरोध है कि बाबा रामदेव जितनी जल्दी हो सके, अपने सत्याग्रह का स्वरूप, सत्याग्रह की शर्तें, जो उसमें शामिल होने वाले हैं उनमें क्या-क्या गुण होने चाहिए, क्या-क्या पात्रता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें घोषित कर दें. इसलिए घोषित करें कि अगर लड़ाई भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ है तो कम से कम उनके आंदोलन में वे लोग तो न शामिल हों, जो ज़िला या प्रदेश स्तर पर ऐसे धंधों में शामिल हैं जिनमें काले धन का इस्तेमाल होता है, जो सेल्स टैक्स की चोरी करते हैं. ऐसे लोग न शामिल हों, जो देश में जो व्हाइट मनी से ज़्यादा ब्लैक मनी चलाते हैं. कुछ चीजें बाबा रामदेव को साफ़ कर देनी चाहिए कि उनके सत्यागह में ये लोग शामिल होंगे या नहीं होंगे. यहां से एक नई तरह की जन राजनीति का शुभारंभ हो सकता है. अगर बाबा रामदेव ने यह नहीं किया तो जन राजनीति की जगह उनके आंदोलन में वे लोग शामिल हो जाएंगे, जो लुंपेंस हैं, जो लोग हर आंदोलन को लूट-खसोट में परिवर्तित करने में माहिर होते हैं और जिनमें किसी भी चीज़ को हिंसक बनाने की क्षमता है, सांप्रदायिक बनाने की क्षमता है. हालांकि बाबा रामदेव से एक बड़ी गलती हो रही है. बाबा रामदेव को भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अपने आंदोलन में, अब मैं शब्द इस्तेमाल

> **अगर लड़ाई भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ है तो कम से कम उनके आंदोलन में वे लोग तो न शामिल हों, जो ज़िला या प्रदेश स्तर पर ऐसे धंधों में शामिल हैं जिनमें काले धन का इस्तेमाल होता है, जो सेल्स टैक्स की चोरी करते हैं. ऐसे लोग न शामिल हों, जो देश में जो व्हाइट मनी से ज़्यादा ब्लैक मनी चलाते हैं. कुछ चीजें बाबा रामदेव को साफ़ कर देनी चाहिए कि उनके सत्यागह में ये लोग शामिल होंगे या नहीं होंगे. यहां से एक नई तरह की जन राजनीति का शुभारंभ हो सकता है.**

कर रहा हूं सत्याग्रह का, क्योंकि उन्होंने सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल किया है, सत्याग्रह में समाज के सभी वर्गों के लोगों को अपने साथ लेना चाहिए. पर उन्होंने राजनीति से जुड़े और राजनीति को संचालित करने वाले परोक्ष संगठनों को अपने साथ लेने का संकेत दिया है. लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, गोविंदाचार्य, अशोक सिंघल एवं प्रवीण तोगड़िया के साथ उन्होंने दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस की और अपरोक्ष रूप से बता दिया कि उनकी महत्वाकांक्षा क्या है. मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि यह बात बाबा रामदेव की समझ में न आई हो, हालांकि वह बहुत समझदार हैं. इसलिए उनकी समझदारी पर संदेह नहीं करना चाहिए. उन्होंने बहुत सोच-समझ कर इन लोगों के साथ प्रेस कांफ्रेंस की होगी और उसमें सत्याग्रह की घोषणा की, जिसमें अशोक सिंघल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तौर पर बाबा रामदेव के साथ है.

अगर बाबा रामदेव समाज के सभी वर्गों को, राजनीति के सभी वर्गों को, जो नहीं आता वह नहीं आता, लेकिन उन्हें आमंत्रित करते कि वे उनके सत्याग्रह में शामिल हों, भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाएं, मुहिम के हिस्से बनें, तो शायद ज़्यादा बेहतर होता. बाबा रामदेव को लोग एक योग गुरु के रूप में जानते हैं. बाबा रामदेव का लोग इसलिए आदर करते हैं, क्योंकि उनकी दवाओं से उन्हें फ़ायदा होता है. बाबा रामदेव का लोग इसलिए भी सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार हिंदुस्तान में योगा को योग के रूप में स्थापित किया, पुनर्स्थापित किया. बाबा रामदेव से पहले जितने भी योग गुरु थे, वे विदेशों में जाते थे और वहां योग का प्रचार करते थे. अपने देश में उनकी कोई रुचि नहीं थी अथवा कहें कि योग यहां लोकप्रिय नहीं था. बाबा रामदेव ने योग को देश में लोकप्रिय बनाया और, है शब्द छोटा, लेकिन उसे योगा से योग में परिवर्तित किया. जबसे बाबा रामदेव ने देश के भ्रष्टाचार रोग को योग से ठीक करने की बात कही है, तबसे सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं. बाबा रामदेव अगर सत्याग्रह का स्वरूप घोषित नहीं करते और कौन लोग सत्याग्रह में शामिल हो सकते हैं, यह स्पष्ट नहीं करते हैं तो मानना चाहिए कि यह आंदोलन किसी नतीजे पर शायद न पहुंचे.

बहुत सारे आंदोलन देश में होते हैं, बहुत सारी कोशिशें होती हैं, जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचतीं. क्यों? क्योंकि बाक़ी जो लोग आंदोलन कर रहे होते हैं, उनमें और आंदोलन में एक अंतर्विरोध होता है. वैचारिक अंतर्विरोध. जो भ्रष्ट हैं, वे ही भ्रष्टाचार का विरोध करें! और भ्रष्ट भी वह, जो सचमुच भ्रष्ट की श्रेणी में आता है. ऐसे लोग देश में 25-30 प्रतिशत के आसपास हैं, जिनमें 5 प्रतिशत वे हैं, जिनका धन विदेशों में जमा है, लेकिन बाक़ी पच्चीस प्रतिशत वे हैं, जिनका काला धन इसी देश में घूम रहा है. मुद्दों को बिगाड़ना नहीं चाहिए. भ्रष्टाचार से लड़ने और उसे खत्म करने की बात महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, लोकनायक जयप्रकाश आदि सभी ने की. यह देश भ्रष्टाचार के इतने बड़े जाल में है, शायद दुनिया का कोई दूसरा मुल्क इतने बड़े जाल में नहीं है. इसलिए भ्रष्टाचार से लड़ाई को हल्का नहीं करना चाहिए. कोशिश करनी चाहिए कि देश के मज़दूर, किसान, वंचित, अल्पसंख्यक यानी सभी इस लड़ाई में शामिल हों. और दिख यह रहा है कि इस लड़ाई में वे शामिल हैं, जिनकी पात्रता इस लड़ाई को लड़ने की नहीं है और शायद इसलिए थोड़ा शोरशराबा हो, थोड़ा हल्ला-हंगामा हो, कुछ दंगे भी हो जाएं. लेकिन इस देश की सौ करोड़ जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ चलने वाले इस सत्यागह में कैसे विश्वास करे, वह भी तब, जबकि उसे इस सत्याग्रह की तस्वीर और रूपरेखा के बारे में कुछ मालूम ही न हो. ऐसे में इस सत्याग्रह को सफलता की ओर ले जाने की संभावना पूरी हो पाएगी या नहीं, यह मुझे नहीं पता. इसलिए इस देश के लोगों के साथ, लोगों के विश्वास के साथ अगर ईमानदारी बरतनी है तो लड़ाई के हर कदम को लड़ाई लड़ने से पहले साफ़ करना होगा.

इस मामले में नक्सलवादी ईमानदार हैं. उनकी लड़ाई किसके ख़िलाफ़ है, उनकी लड़ाई कैसे होगी, उनकी लड़ाई में कौन शामिल हो सकता है, उनकी लड़ाई में कौन कितनी दूर तक जा सकता है, वे सब साफ़ कर देते हैं. आज जरूरत इस बात की है कि जितनी ईमानदारी नक्सलवादियों में है, उतनी ईमानदारी बाबा रामदेव को भी दिखानी चाहिए और उन्हें अपने सत्याग्रह के स्वरूप, अपने सत्याग्रह की संभावना, अपने सत्याग्रह में शामिल होने वालों की पात्रता और उसकी शर्तें घोषित करनी चाहिए, ताकि लोग हिम्मत के साथ आगे आएं और बाबा रामदेव को उनकी इस लड़ाई में, जो लड़ाई भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ वह लड़ना चाहते हैं, उनका साथ दे सकें.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

निर्मल रानी

संकट से बचने के लिए जल संरक्षण ज़रूरी

ग्रीष्म ऋतु की दस्तक हो चुकी है. पूरे विश्व में निरंतर बढ़ती जा रही गर्मी को दुनिया तरह-तरह के नाम दे रही है. लोग इसे मौसम का बदलता मिजाज़ बताते हैं, वहीं पर्यावरण विशेषज्ञ हर वर्ष बढ़ती जाने वाली गर्मी को ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा दे रहे हैं. जबकि कुछ इस तेज़ गर्मी के लिए अमेरिका सहित कई विकसित देशों को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं. ऐसी सोच रखने वाले लोगों का मानना है कि करोड़ों टन गोला-बारूद का विस्फोट करके अमेरिका एवं उसके सहयोगी देशों ने ही पृथ्वी पर भीषण गर्मी को न्योता दिया है और इन देशों का ऐसे कृत्य अभी भी जारी है. जबकि तमाम मौसम विज्ञान विशेषज्ञ दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे औद्योगीकरण और प्रतिदिन लाखों वाहनों के सड़कों पर आने के परिणामस्वरूप पैदा होने वाले प्रदूषण को इस प्रचंड गर्मी का ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं. कारण जो भी हों, परंतु सच्चाई तो यही है कि ऐसी भीषण गर्मी से राहत पाने का एकमात्र उपाय केवल जल होता है. गर्मी से प्रभावित लोग इधर-उधर भटकते और किसी भी प्रकार से जल प्राप्त करने के उपाय करते दिखाई देते हैं.

भारत जैसे विशाल देश के कई राज्यों से प्राय: ऐसी ख़बरें मिलती हैं कि लोग भीषण गर्मी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे. वर्ष 2003 में एक हज़ार से अधिक लोग अकेले आंध्र प्रदेश में ही भीषण गर्मी की भेंट चढ़े थे. यहां नालगुंडा ज़िला सबसे अधिक प्रभावित हुआ था, जहां 600 लोगों को भीषण गर्मी ने निगल लिया था. उस समय ऐसी सूचनाएं मिली थीं कि नालगुंडा में मरने वालों की संख्या और भी कम हो सकती थी, परंतु जल के भीषण अकाल के चलते इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा. पानी के अकाल का यह वह समय था, जबकि राजस्थान में भी निजी टैंकर मालिकों ने 5 से 10 रुपये प्रति बाल्टी की दर से ज़रूरतमंदों को जल की बिक्री की थी. मध्य प्रदेश एवं गुजरात में जल के लिए उसी समय ऐसा हाहाकार मचा था कि कई स्थानों से पानी के लिए संघर्ष होने के भी समाचार प्राप्त हुए थे. अब तो हरियाणा एवं पंजाब जैसे राज्य, जिन्हें कृषि के क्षेत्र में अग्रणी होने के साथ-साथ जल संसाधनों के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर समझा जाता था, जल संकट का सामना कर रहे हैं. जल के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञ अब यहां तक कहने लगे हैं कि यदि भीषण गर्मी का प्रकोप यूं ही जारी रहा और धरती के गर्भ से जल का अनावश्यक एवं बेतहाशा दोहन इसी प्रकार होता रहा तो कोई आश्चर्य नहीं कि देश का अधिकांश भाग बंजर भूमि तथा रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाए. जल संकट की समस्या एक विश्वस्तरीय त्रासदी के रूप में सामने आ रही है. यही कारण है कि अब इस प्रकार की चर्चा भी सुनाई दे रही है कि यदि इराक़, ईरान और लीबिया जैसे देशों पर अमेरिका की कुदृष्टि का कारण कच्चे तेल का दोहन किया जाना है तो दुनिया को भविष्य में जल स्रोतों पर वर्चस्व हासिल करने के लिए होने वाले अगले युद्ध की खातिर मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए. भविष्य में होने वाली जंग तेल के लिए नहीं, बल्कि पानी के लिए हो सकती है.

आम तौर पर जल की कमी के लिए जनता सीधे तौर पर सरकार को दोषी ठहरा देती है, परंतु जल की बर्बादी करने और उसका समुचित संरक्षण न कर पाने में जनता का अपना कितना योगदान है, उसे वह नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती. यदि जल की कमी का दोष केवल सरकार पर मढ़ा जाए तो यह हरगिज़ मुनासिब नहीं होगा. आख़िर जनता द्वारा लगभग हर समय जल के दुरुपयोग पर सरकार किस तरह निगरानी रख सकती है. साधन संपन्न लोगों ने अपने घरों में टंकी में पानी चढ़ाने के लिए अवैध रूप से मोटर पंप लगा रखे हैं, इस वजह से जल का दुरुपयोग होता है और जनता में जल का समान वितरण भी प्रभावित होता है. रबड़ के पाइप लगाकर अपनी कारें, फर्श, लॉन एवं बगीचे आदि पर लगातार पानी डालना तो धनाढ्य एवं नव धनाढ्य लोगों की फ़ितरत में शामिल हो चुका है. कटु सत्य तो यह है कि ऐसे तथाकथित संभ्रांत लोग भी हमारे जल भंडारण को प्रभावित करने और देश को समय से पूर्व जल संकट की ओर धकेलने के लिए दोषी हैं. कई स्थानों पर नलों के ऊपर से टोंटी ही नदारद दिखाई देती है. परिणामस्वरूप जलापूर्ति होने पर पानी निर्बाध रूप से व्यर्थ बहता रहता है. मात्र दो दशक पूर्व जिन कुओं में आठ-दस फीट की गहराई पर जल उपलब्ध था, आज वहीं कुएं पूरी तरह सूखे पड़े हैं. तमाम झीलें, तालाब एवं जोहड़ सूखे नज़र आ रहे हैं.

कितने अफ़सोस की बात है कि प्रकृति द्वारा अपने प्राणियों को उपलब्ध कराई गई जल रूपी बेशक़ीमती सौगात का संरक्षण भी हम नहीं कर पाते, जिसके बिना हमारा जीवन ही असंभव है. इसके लिए सरकारों पर दोष मढ़ना या उसके रहमोकरम की आस रखना हरगिज़ उचित नहीं. जनता को स्वयं जल संकट की समस्या के प्रति गंभीर होना होगा. जल के दुरुपयोग को रोके जाने की आवश्यकता है. हमें उन उपायों को अपनाने की ज़रूरत है जो जल संरक्षण के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हों. सर्वप्रथम तो हमें यूकेलिप्टस एवं सफ़ेदा जैसे वृक्षों से परहेज़ करना चाहिए, जो धरती के जलस्तर को कम करने में सहायक सिद्ध होते हैं. आजकल देखा जा रहा है कि शीघ्र करोड़पति बनने की चाह में तमाम लोग ऐसे वृक्ष लगा रहे हैं, जो पांच-छह साल में ही तैयार हो जाते हैं. इस सोच में बदलाव लाने की जरूरत है. सरकार को ऐसे वृक्ष प्रतिबंधित कर देने चाहिए और जनता को इसमें सहयोग देना चाहिए. नवनिर्मित मकानों में लैंड रिचार्जिंग सिस्टम अनिवार्य कर देना चाहिए. इस प्रणाली के तहत मकान की छत पर इकट्ठा होने वाला बारिश का पानी एक विशेष पाइप के माध्यम से सीधा धरती में प्रवेश कर जाता है और उस मकान एवं उसके आसपास के जलस्तर को सामान्य रखने में सहायक होता है. यह प्रणाली नवनिर्मित मकानों में तो अनिवार्य रूप से अपनाई जानी चाहिए, साथ ही पुराने मकानों के स्वामियों को भी अपने यहां ऐसी प्रणाली का प्रबंध कर लेना चाहिए.

बारिश के दिनों में वर्षा का जल ढालदार क्षेत्रों की ओर बहता दिखाई देता है. यह जल निचली जगहों पर अपना स्थान बना लेता है और लंबे समय तक अनावश्यक रूप से रुका रहता है. परिणामस्वरूप जिस ज़मीन पर बरसात का यह पानी रुकता है, वहां की खेती प्रभावित होती है और मच्छर एवं अन्य कीड़े-मकोड़े जन्म लेते हैं. इस प्रकार जल का एक बड़ा भंडार बिना किसी प्रयोग में आए सूख-सूखकर समाप्त हो जाता है. कई स्थानों पर तो यही रुका हुआ जल नदियों और नालों के बढ़े हुए पानी से मिलकर बाढ़ कर रूप धारण कर लेता है तथा विनाश का कारण बन जाता है. ऐसे तमाम क्षेत्रों में बड़े कुएं के रूप में लैंड रिचार्जिंग सिस्टम लगाए जाने चाहिए, जहां बरसात का पानी व्यर्थ रूप से नष्ट होने के बजाय धरती के भीतर समा जाए. यदि हम इस विकट समस्या के प्रति जागरूक नहीं हुए और जल संरक्षण के शीघ्र उपाय नहीं किए गए तो निश्चित रूप से हमारी इन ग़लतियों का परिणाम अगली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा. इन ग़लतियों-लापरवाहियों के लिए हमारी संतानें हमें क्षमा नहीं करेंगी. यदि हम इस वास्तविकता को स्वीकार करते हैं कि जल ही जीवन है तो उस जीवन की रक्षा करने की ज़िम्मेदारी भी हमारी और सिर्फ़ हमारी है.

feedback@chauthiduniya.com

गांधी, हजारे और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जंग

असगर अली इंजीनियर

अन्ना हजारे दूसरे गांधी के रूप में उभर रहे हैं. हर अख़बार उनके स्तुतिगान से लबरेज है. लोकपाल बिल का मसौदा तैयार करने वाली समिति में सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों को शामिल करने की अन्ना की मांग यूपीए सरकार ने मंजूर कर ली. यूपीए सरकार के इतने घोटाले उजागर हो चुके हैं कि उसके सामने यह मांग मंजूर करने के अलावा कोई चारा नहीं था. अन्ना के आमरण अनशन को सभ्य समाज का भारी समर्थन मिला. टूजी और कॉमनवेल्थ खेल घोटालों के आरोपों से घिरी सरकार पहले से दबाव में थी, इसलिए वह आसानी से झुक गई. अगर ऐसा न होता तो अन्ना को इतनी आसानी से जीत हासिल न होती. अन्ना इस समय देश की आंखों का तारा हैं. वह सामाजिक कार्यकर्ताओं और सभ्य समाज के आदर्श बन गए हैं. इन्हें अन्ना पर गर्व है. भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस लड़ाई को दूसरा स्वाधीनता संग्राम बताया जा रहा है. ये प्रतिक्रियाएं त्वरित एवं भावनात्मक हैं. भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दे का हल भावनाओं में बहकर नहीं निकाला जा सकता. क्या यह सचमुच इतनी महान नैतिक विजय है, जितना बताया जा रहा है? क्या इस आंदोलन के दूरगामी प्रभावों पर विचार किया जाना ज़रूरी नहीं है? अन्ना और उनके आंदोलन को गांधीवादी बताया जा रहा है, इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि गांधीवादी मूल्य क्या हैं और गांधीवादी आंदोलन कैसा होना चाहिए. गांधीवादी संघर्ष के तीन मुख्य तत्व हैं, जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता है- सत्य, अहिंसा और अत्यंत सादा जीवन. इन तीनों में से एक तत्व अन्ना के आंदोलन में निश्चित रूप से मौजूद था, वह है अहिंसा. बाक़ी दोनों तत्व मौजूद थे या नहीं, यह बहस का विषय हो सकता है. कोई भी आंदोलन लंबे समय तक अहिंसक तभी रह सकता है, जब वह सत्य और केवल सत्य पर आधारित हो. सादा जीवन जीने वाले नेता ही सत्य पर आधारित और अहिंसक आंदोलन चला सकते हैं. यही कारण है कि यह देश दूसरा गांधी पैदा नहीं कर सका.

अन्ना के आंदोलन को किन तबकों का समर्थन मिला? पहला तबका था मध्यम वर्ग, जिसका सादगी से कोई लेना-देना नहीं है. बड़े उद्योगपतियों की तरह मध्यम वर्ग अपना काम निकालने के लिए रिश्वत देने में कोई संकोच नहीं करता. मध्यम वर्ग के यात्री टीसी की मुट्ठी गरम कर ट्रेन में बर्थ पाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. अवैध निर्माण को नज़रअंदाज़ करने के बदले सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता. इस वर्ग के लोग अपने लड़के-लड़कियों को अच्छे स्कूलों-कॉलेजों में भर्ती कराने के लिए मोटी कैपिटेशन फीस चुकाते हैं. सरकारी कार्यालयों, पुलिस थानों और अदालतों में जो लोग रिश्वत देते-लेते हैं, क्या वे आसमान से उतरे हैं? यही मध्यम वर्ग इस समय अन्ना के आंदोलन का जोर-शोर से समर्थन कर रहा है. इस वर्ग को भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. जिस दूसरे तबके का समर्थन अन्ना को मिला, वह था राजनीतिज्ञों का एक हिस्सा. यद्यपि रणनीतिक कारणों से यह वर्ग खुलकर सामने नहीं आया. इसका उद्देश्य था यूपीए सरकार को कमज़ोर करना. इसके इरादे पवित्र नहीं थे. जो तीसरा वर्ग अन्ना के साथ जुड़ा, वह उनका था जो सिद्धांत और व्यवहार दोनों में भ्रष्टाचार से संघर्ष करना चाहते थे. यह वर्ग गांधीवादी मूल्यों और विचारधारा के सबसे नज़दीक था.

अन्ना समर्थकों में इसके सदस्यों की संख्या सबसे कम थी. अन्ना और गांधी में अंतर को समझना ज़रूरी है. अन्ना गांधी तो कतई नहीं हैं. उन्हें गांधीवादी कहा जा सकता है. उन्हें यह श्रेय दिया जा सकता है कि उन्होंने आंदोलन का गांधीवादी रास्ता चुना. गांधी जी का चिंतन मौलिक था, उनकी समझ बहुत गहरी थी, उनके इरादे एवं लक्ष्य पवित्र थे और वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते थे. अंतरात्मा की आवाज़ वही सुन सकते हैं, जिनका दिलोदिमाग कलुषता से सर्वथा मुक्त हों. अन्ना की न तो मुद्दों पर पकड़ है और न वह गांधी जैसी मेधा-विद्वता के धनी हैं.

अन्ना ने कभी सांप्रदायिक हिंसा की भर्त्सना नहीं की. गुजरात कत्लेआम के दौरान वह चुप्पी साधे रहे. गुजरात कत्लेआम भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है. अगर गांधी जीवित होते तो वह बिना एक क्षण की भी देरी के आमरण अनशन शुरू कर देते. वह इसकी कतई परवाह नहीं करते कि उन्हें सभ्य समाज का समर्थन प्राप्त है या नहीं. गांधी के लिए अहिंसा जीवन दर्शन थी, रणनीति नहीं. अन्ना ने तो नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल की तारीफ़ कर डाली. क्या हम विकास के नाम पर किसी समाज में व्याप्त हिंसा और अन्याय को नज़रअंदाज़ कर सकते हैं? क्या ऐसा विकास प्रशंसनीय हो सकता है, जिससे समाज के वंचित समूहों को कोई लाभ न पहुंचे? गांधी जी की दृष्टि में सच्चा विकास वही है, जिससे समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा आख़िरी आदमी भी लाभांवित हो. मोदी का विकास मॉडल केवल उच्च और उच्च-मध्यम वर्ग को धनी बना रहा है. अन्ना से जब गुजरात कत्लेआम के बारे में पूछा गया तो पहले वह चुप्पी साधे रहे, फिर बाद में केवल इतना बोले कि वह सांप्रदायिक सद्भाव के पक्षधर हैं. अन्ना ने यह काफी बेमन से कहा और वह भी सहयोगियों के दबाव में. अन्ना के आंदोलन के लिए सभ्य समाज का समर्थन जुटाने में आरएसएस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. भाजपा और बाबा रामदेव जैसे दक्षिणपंथी धार्मिक नेताओं ने भी भीड़ जुटाओ अभियान में भागीदारी की. अब बाबा रामदेव दु:खी हैं कि उन्हें लोकपाल बिल की मसौदा समिति में शामिल नहीं किया गया. दक्षिणपंथी राजनीतिक-धार्मिक ताक़तों का गठजोड़ देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के लिए ख़तरा बन सकता है. जय प्रकाश नारायण के आंदोलन का यही नतीजा हुआ था. नरेंद्र मोदी इसी आंदोलन से उभरे थे. यहां यह कह देना प्रासंगिक होगा कि जय प्रकाश नारायण अन्ना से कहीं बेहतर और प्रतिबद्ध नेता थे. जय प्रकाश नारायण और वी पी सिंह द्वारा किए गए आंदोलन असफल रहे. यदि सफल हो गए होते तो आज हमारे देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला न होता. इन दोनों की तुलना में अन्ना कहीं नहीं ठहरते. इसलिए अन्ना की विजय को दूसरे स्वाधीनता संग्राम की सफलता घोषित करना अर्थहीन है. अन्ना के आंदोलन के असर को बढ़ा-चढ़ाकर बताने के पीछे मीडिया के अपने लक्ष्य हैं. अन्ना एंड कंपनी मोदी के विकास मॉडल की समर्थक है और यह मॉडल बड़े औद्योगिक घरानों के हित में है. मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इन घरानों के नियंत्रण में है, इसीलिए वह अन्ना को गांधी बनाने पर तुला हुआ है. गुजरात के जाने-माने गांधीवादी चिंतक चुन्नी भाई वैद्य ने मोदी द्वारा किए गए ग्रामीण विकास की तारीफ़ करने के लिए अन्ना को सार्वजनिक रूप से लताड़ा कि कहां है वह ग्रामीण विकास, जिसकी अन्ना बात कर रहे हैं. अगर गांवों में सचमुच विकास हो रहा होता तो पिछले 10 वर्षों में 10 प्रतिशत ग्रामीण आबादी शहरों में पलायन न कर गई होती. वैद्य की यह टिप्पणी 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है. वह पूछते हैं कि ग्रामीण विकास के मामले में मोदी से सीखने के लिए क्या है? मल्लिका साराभाई ने भी अन्ना की निंदा की है. उनका कहना है कि मोदी के राज में गांवों में ज़रा भी विकास नहीं हुआ, उल्टे गांवों की चरनोई और सिंचित कृषि भूमि मोदी सरकार ने चोरी-छुपे उद्योगपतियों को दे दी और वह भी मिट्टी के मोल. साराभाई के अनुसार, मोदी शासन में ग्रामीणों ने बहुत तकलीफें झेली हैं. साराभाई की मानें तो मोदी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के सारे रिकार्ड ध्वस्त हो गए. 1700 करोड़ रुपये का सुजलाम-सुफलाम जल संरक्षण घोटाला, 600 करोड़ रुपये का मत्स्य पालन घोटाला और 100 करोड़ रुपये का बोरीबंद चेक डेम घोटाला मोदी राज की देन हैं. उद्योगपतियों को उपकृत करने की नीति के कारण राज्य क़र्ज़ के बोझ तले दब गया है.

महात्मा गांधी ग्रामीण विकास पर बहुत जोर देते थे. वहीं दूसरे गांधी यानी अन्ना उस मुख्यमंत्री की तारीफ़ कर रहे हैं, जिसने उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाया. गांधी जी ने जीवन भर छुआछूत और जाति-पांत के विरुद्ध संघर्ष किया और अन्ना उस राज्य की प्रशंसा कर रहे हैं, जहां सरकारी स्कूलों में दलित और सवर्ण बच्चों को मध्यान्ह भोजन के लिए अलग-अलग बैठाया जाता है. जो अध्यापक सभी बच्चों को एक साथ बैठाने की जुर्रत करता है, उसका तबादला कर दिया जाता है. अन्ना शायद इन कटु सच्चाइयों से वाक़िफ़ नहीं हैं. अन्ना की भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई स्वागत योग्य है. वह निश्चय ही प्रशंसा के पात्र हैं. यदि वह इस लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें अपने साथियों-सहयोगियों की छंटनी करनी होगी. भ्रष्टाचार में गले तक डूबे सैनिकों की सेना, चाहे उसका कमांडर कितना ही ईमानदार क्यों न हो, कभी भ्रष्टाचार के दानव को परास्त नहीं कर सकती. गांधी जी कहा करते थे, साधन की पवित्रता उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी साध्य की.

(लेखक मुंबई स्थित सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी एंड सेक्युलरिज्म के संयोजक हैं)

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

देशद्रोही किसे कहें

चौथी दुनिया में कोयला घोटाले के बारे में पढ़ा. सचमुच अब तो सारी सीमाएं पार कर दीं. देशद्रोही किसे कहें, देश के रखवाले को? इससे बुरा और क्या होगा? अब तो गद्दी पर वही बैठे, जो अंग्रेजी क़ानून को ख़त्म करे और नया क़ानून बनाए. भारत स्वाभिमान आंदोलन के मुद्दे और नीति बिल्कुल सही हैं. बस इसे जनता समझ जाए, वरना ऐसे क्रांतिकारी लेखों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा.

-डेविड, *ईमेल से.*

■ कोयला घोटाले के बारे में पढ़ा. भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रही है, यह समझ में नहीं आ रहा है. लगता है, जिन कंपनियों की सूची आपने दी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कंपनियां भी शामिल हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी बिक चुकी है. कांग्रेस पार्टी से पैसे लेकर बैठ गई है. यह शर्म की बात है कि देश के राजनीतिक दलों ने सब कुछ बेच दिया.

-राकेश आर्य, *ईमेल से.*

■ अगर कोयला घोटाले की निष्पक्ष ढंग से जांच होती है तो इसकी लपटों से शायद प्रधानमंत्री का बचना मुश्किल होगा, लेकिन हमारे राजनीतिक दल नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ कोई प्रभावी कार्यवाही हो.

-मदन कुमार तिवारी, *ईमेल से.*

मौलवी ध्यान दें

पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन की बात समझ से दूर है. वहां के कठमुल्लाओं की मानसिकता ही समझ में नहीं आती. शरीयत की ही बात करें तो स्पष्ट है कि ऐ बंदों, सभी ग़ैर मुस्लिम भी मेरे ही बंदे हैं, जबरन इस्लाम कुबूल कराना भी गुनाहे-अज़ीम है. इस्लाम के प्रवर्तक नबी सल अलेहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि ऐ मोमिनों, यदि कोई व्यक्ति अपने देवी-देवता को पूजता है तो उसके देवी-देवता को बुरा-भला मत कहो या गाली मत दो. लेकिन ये तथ्यपरक साक्ष्य शायद पाकिस्तानी मुल्लाओं की समझ में नहीं आएंगे. इसलिए कम से कम भारतीय मुस्लिम इस बात को समझें. खुदा ने नमाज़ से भी पहले इल्म हासिल करने को तवज्जो दी है, ताकि कोई भी मोमिन गुमराह न हो सके. मौलवी यह बात स्पष्ट नहीं करने वाले, वे तो एक ही बात जानते हैं कि औरत को क्या नहीं करना चाहिए!

-हौरैन फ़ैयाज़, *बिजनौर, उत्तर प्रदेश.*

सर्वश्रेष्ठ पत्र

ग़ुलामी ही अच्छी थी

मुख्य आलेख-अब प्यासे मरेंगे अमरावती के किसान (02-08 मई) रोचक, जानकारीपरक था और हमें जमीनी सच्चाई से रूबरू करा गया. लगने लगा है कि यह देश ग़ुलाम रहता तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता. गांधी जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि काले अंग्रेज तो गोरे अंग्रेजों के मुक़ाबले लाख गुना ज़्यादा ज़ुल्म करेंगे. किसानों के हिस्से का पानी पावर प्रोजेक्ट को बेचने वाले इन हिंदुस्तानियों का क्या किया जाए, यह सोचते ही डर लगता है. लड़ें तो आख़िर किससे लड़ें. पूंजीपतियों के ग़ुलाम बन चुके हमारे अपने ही अपनों को मौत के मुंह में धकेलने में सबसे आगे हैं. पिछले अंक में आपने बुंदेलखंड के प्यासे किसानों का हाल बताया. विदर्भ और बुंदेलखंड के किसानों की स्थिति में कोई अंतर नहीं है. राहुल गांधी बुंदेलखंड आते हैं और विदर्भ भी जाते हैं, लेकिन दोनों ही जगह समस्याएं जस की तस हैं.

-पंकज शर्मा, *झांसी, उत्तर प्रदेश.*

सुनहरा अवसर

जन लोकपाल बिल को लोकसभा में पारित कराने के लिए यूपीए सरकार के पास एक सुनहरा अवसर है. इससे कांग्रेस का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा और उसके द्वारा किए गए घोटालों के पाप भी धुल जाएंगे.

-गोपाल कृष्ण ओहरी, *ग्वालियर, मध्य प्रदेश.*

एक सुझाव

चौथी दुनिया ने सूचना अधिकार क़ानून से जुड़ी जानकारियां देकर समाज को जागरूक बनाया है. मैंने इसमें दिए गए आवेदनपत्र के प्रारूप का लाभ स्वयं उठाया है और दूसरे लोगों को भी इससे लाभांवित होते देखा है. मेरा आग्रह है कि अखबार में विविध स्तंभों के माध्यम से पाठकों के छायाचित्र एवं विचार छापे जाएं और विषयों का निर्धारण संपादक मंडल करे.

-कृष्ण कुमार उपाध्याय, *बस्ती, उत्तर प्रदेश.*

राजकमल प्रकाशन समूह
1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110 002 फोन 011-23274463, 23288769, फ़ैक्स 011-23278144
www.rajkamalprakashan.com Email : info@rajkamalprakashan.com
राजकमल प्रकाशन समूह की ओर से लेखन विधा को सम्मान
'चौथी दुनिया' में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को दी जानेवाली 700 रुपये की किताबें

राजकमल प्रकाशन समूह की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें
हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपये की पुस्तकें दी जाएंगी
हेल्पलाइन : 09311196029

पाठक पूरे नाम, पते व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इस पते पर भेजें : संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

वर्ष 2002 में लंदन के वनस्पति उद्यान में भी यह फूल खिला था. अब तक दुनिया में सिर्फ़ 134 बार इस फूल को प्रयासपूर्वक उगाया जा सका है.

दिल्ली, 16 मई–22 मई 2011
चौथी दुनिया

सूचना का अधिकार – चौथी दुनिया की पहल

तीसरा पक्ष क्या है

कई बार जब आप किसी सरकारी विभाग में आरटीआई आवेदन देते हैं तो जवाब में आपको बताया जाता है कि अमुक सूचना तीसरे पक्ष से जुड़ी है, इसलिए आपको नहीं दी जा सकती या मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए सूचना का प्रकटीकरण नहीं किया जा सकता है या फिर अमुक सूचना को सार्वजनिक करना देशहित में नहीं है अथवा सूचना को सार्वजनिक करने से देश की आंतरिक सुरक्षा को ख़तरा हो सकता है. हालांकि कई बार ऐसा लगता है कि लोक सूचना अधिकारी सूचना न देने के लिए बहानेबाज़ी कर रहा है और कई बार सचमुच ऐसा होता भी है. इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास आरटीआई क़ानून की उन धाराओं की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, जो सूचना को सार्वजनिक किए जाने से रोकते हैं. इससे फ़ायदा यह होगा कि हम आसानी से यह तय कर सकेंगे कि लोक सूचना अधिकारी कहीं उन धाराओं का ग़लत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है. इस अंक में हम आपको तीसरे पक्ष के बारे में बता रहे हैं. सूचना अधिकार क़ानून के तहत जो व्यक्ति सूचना मांगता है, वह प्रथम पक्षकार होता है. जिस विभाग या लोक प्राधिकारी से सूचना मांगी जाती है, वह द्वितीय पक्षकार होता है. इस तरह की सूचनाओं में आम तौर पर किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती. लेकिन यदि आवेदक द्वारा मांगी जा रही सूचना आवेदक से सीधे–सीधे संबंधित न होकर किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित हो तो वह अन्य व्यक्ति ही तृतीय पक्ष कहलाता है. तीसरे पक्ष से संबंधित व्यक्ति की सूचना को तृतीय पक्ष की सूचना कहा जाता है. सूचना अधिकार क़ानून में तृतीय पक्ष की गोपनीयता को संरक्षित करने का प्रावधान है. क़ानून की धारा 11 के अनुसार, ऐसी सूचनाएं, जो किसी दूसरे व्यक्ति से संबंधित होती हैं, उन्हें आवेदक को दिए जाने से पूर्व तीसरे पक्षकार की इजाज़त लेनी पड़ती है. ऐसे मामलों में लोक सूचना अधिकारी की ज़िम्मेदारी होती है कि वह आवेदन प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर तीसरे पक्षकार को इस आशय की सूचना देगा और अगले 10 दिनों के भीतर सूचना जारी करने की सहमति या असहमति प्राप्त करेगा. लेकिन क़ानून में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसी सूचना, जिससे सामाजिक हित सधता हो या तीसरे पक्ष की सूचना को जारी करने से होने वाली संभावित क्षति लोकहित से ज़्यादा बड़ी न हो तो उस दशा में मांगी गई सूचना दी जा सकती है. क़ानून में यह एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी लोक सूचना अधिकारी को है कि वह मांगी गई सूचना तृतीय पक्षकार एवं लोकहित को अच्छी तरह समझ–बूझकर जारी करे. कई मामलों में देखने में आया है कि लोक सूचना अधिकारी व्यक्तिगत स्वार्थ या विभागीय दबाव के चलते तृतीय पक्ष से संबंधित सूचनाओं को जारी करने से रोकने के लिए धारा 11 का ग़लत इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे में सूचना आयुक्तों की ज़िम्मेदारी काफी बढ़ जाती है कि वह तृतीय पक्ष से संबंधित सूचनाओं को जारी करने में लोकहित का विशेष ख्याल रखें, जिससे क़ानून की मूल भावना पारदर्शिता और जवाबदेयता बची रहे. यहां हम आपको तीसरे पक्ष से संबंधित कुछ अहम फ़ैसलों के बारे में भी बता रहे हैं. एक करदाता द्वारा दाख़िल किए गए आयकर रिटर्न की सूचना भी तृतीय पक्ष से संबंधित मानी गई है. सूचना आयोग ने एक मामले की सुनवाई के दौरान आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि नहीं दिलाई. आयोग का मानना था कि करदाता द्वारा यह सूचना विभाग को विश्वास आधारित संबंधों के तहत दी जाती है, जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन एक अन्य मामले में आयोग ने आयकर एसेसमेंट की जानकारी सार्वजनिक करने में कोई आपत्ति नहीं जताई. इससे समझा जा सकता है कि सूचना दी जाए या नहीं, इसका सारा दारोमदार सूचना आयुक्त पर है. एक दंपत्ति ने सूचना अधिकार क़ानून के तहत एक डॉक्टर के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपि मांगी, जिसे मेडिकल संस्थान ने देने से मना कर दिया. संस्थान का मानना था कि यह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचना है, जिसे दिए जाने से उसकी निजता का हनन होता है. आयोग में सुनवाई के दौरान दंपत्ति ने यह सूचना लोकहित में जारी करने की दलील दी. उनका कहना था कि शैक्षणिक दस्तावेज़ जिस डॉक्टर के मांगे गए हैं, उसने उनके पुत्र का इलाज किया था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी. उन्हें संदेह था कि डॉक्टर के दस्तावेज़ फर्जी हैं. आयोग ने भी इस दलील पर सहमति जताई और सूचना जनहित में जारी करने के आदेश दिए.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

पाठकों के पत्र

सूचना मांगने पर धमकी मिली

मैंने डाक अधीक्षक से पोस्टल सहायक एवं छंटाई सहायक की नियुक्ति के बारे में आरटीआई के तहत सवाल पूछे थे. मुझे सूचना तो नहीं मिली, लेकिन डाक अधीक्षक ने अपने गुर्गों के माध्यम से मुझे धमकी दिलवाई. मैंने इसकी शिकायत संबंधित विभाग में कर दी है. इसके आगे मुझे क्या करना चाहिए?

–गिरीश प्रसाद गुप्ता, बरौनी, बिहार.

■ *ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि एक अकेले आदमी को डरा–धमका कर चुप करा दिया जाता है. इसलिए अच्छा यह होगा कि आप इसी मसले पर कई लोगों से आरटीआई आवेदन डलवाएं. इसका फायदा यह होगा कि डाक अधीक्षक चाहकर भी उन सबका मुंह बंद नहीं करा पाएगा. वैसे जिन जगहों पर आपने इस घटना की शिकायत की है, वहां एक बार फिर से आरटीआई के तहत आवेदन देकर अपनी शिकायत पर हुई कार्रवाई के बारे में सवाल पूछ सकते हैं.*

न सूचना मिली, न नौकरी

मैंने कमांडेंट रिमाउन्ट प्रशिक्षण एवं डिपो सहारनपुर में मोची पद के लिए आवेदन किया था. मुझे कॉल लेटर नहीं मिला. इस संबंध में मैंने आरटीआई आवेदन देकर सवाल पूछे, लेकिन सूचना नहीं मिली. मैंने केंद्रीय सूचना आयोग में इसकी शिकायत की, वहां से सूचना देने का आदेश भी जारी हुआ, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है. मैंने इस बात की शिकायत भी सूचना आयोग में की है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ.

–सतीश कुमार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश.

■ *आप केंद्रीय सूचना आयोग तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं और वहां से सूचना उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया जा चुका है. सूचना न मिलने की शिकायत भी आप आयोग में कर चुके हैं. ऐसे में आपके पास दो उपाय बचते हैं. एक तो यह कि आप आयोग को इस संबंध में रिमाइंडर भेज सकते हैं या फिर इस मामले को लेकर संबंधित हाईकोर्ट में जा सकते हैं.*

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन –201301, ई–मेल : rti@chauthiduniya.com

बदबूदार मुर्दा फूल

फूल और ख़ुशबू एक–दूसरे के पर्याय माने जाते हैं. आम तौर पर फूल से ख़ुशबू निकलती है, लेकिन उत्तरी स्विट्ज़रलैंड के शहर बासेल में खिले एक फूल से बदबू आती है और वह भी सड़े हुए मांस की. हज़ारों लोग इस विशालकाय और अनोखे फूल को देखने के लिए जा रहे हैं. इसका नाम एमॉर्फ़ॉफ़ैलस टाइटैनम है, लेकिन इसे मुर्दा फूल के नाम से भी जाना जाता है. स्विट्ज़रलैंड में यह 75 सालों में पहली बार खिला है और बासेल में भी इसे खिलने में 17 वर्षों का समय लगा है. बासेल वनस्पति उद्यान को उम्मीद है कि दो मीटर यानी 6.6 फुट ऊंचे इस फूल के मुरझाने से पहले इसे दस हज़ार लोग देख चुके होंगे.

वर्ष 2002 में लंदन के वनस्पति उद्यान में भी यह फूल खिला था. अब तक दुनिया में सिर्फ़ 134 बार इस फूल को प्रयासपूर्वक उगाया जा सका है. स्विसइंफ़ो वेबसाइट के अनुसार, इस फूल की कोंपल पहली बार मार्च में फूटी थी और तबसे यह प्रतिदिन छह सेंटीमीटर बढ़ता रहा है. जिस पौधे से इसे यहां लाया गया है, वह फ्रैंकफ़र्ट पाम गॉर्डन में है और 1992 में खिला था. वैसे यह फूल मूल रूप से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के ऊष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है और इसे आर्द्र मौसम की ज़रूरत होती है. यह जंगलों में भी यदाकदा खिलता है. कहा जाता है कि इस फूल की गंध जली हुई शक्कर या सड़े हुए मांस की तरह होती है. कुछ भी हो, यह फूल है काफी दिलचस्प.

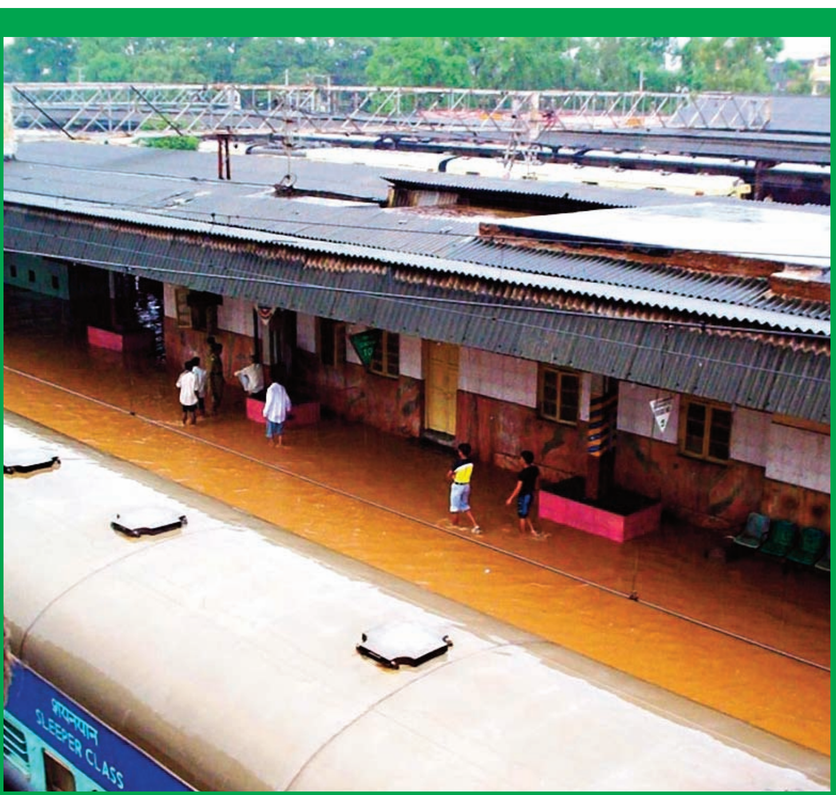

जज़्बे को सलाम

राजधानी दिल्ली के नज़दीक ग्रामीणों ने ख़ुद पैसे एकत्र करके एक रेलवे स्टेशन बनाया है. सीमावर्ती गुड़गांव इलाक़े के गांव ताजनगर और आसपास के लोगों ने दो प्लेटफ़ॉर्म के निर्माण के लिए 20,80,786 रुपये का चंदा इकट्ठा किया. पूरा काम ख़त्म होने में सात महीने लगे. निर्माण कार्य रेलवे के अधिकारियों की देखरेख में किया जा रहा था. इस इलाक़े की सड़कें काफ़ी ख़राब स्थिति में है और आसपास की जगह जाना भी दूभर हुआ करता था. अधिकारियों के अनुसार, इस नए स्टेशन से 25 हज़ार लोगों को फ़ायदा होने की संभावना है. भारतीय रेलवे यूं तो दुनिया की सबसे बड़ी रेल सेवा है, लेकिन कई इलाक़े अब भी रेलवे के नक्शे में नहीं हैं. भारतीय रेलवे नौ हज़ार ट्रेनें चलाती है और डेढ़ करोड़ से ज़्यादा लोग हर दिन इसकी सवारी करते हैं. पूरे भारत में लगभग सात हज़ार स्टेशन हैं. ज़्यादातर स्टेशन रेल विभाग ने बनाए हैं, लेकिन रेल प्रशासन का कहना है कि कुछ स्टेशन पहले भी आम लोगों के सहयोग और चंदे के पैसे से बने हैं.

गौरतलब है कि ताजनगर के लोगों की लंबे समय से यह मांग थी कि उनके गांव में एक स्टेशन बनाया जाए, लेकिन रेल प्रशासन की प्राथमिकता सूची में ताजनगर काफी पीछे था. इसलिए गांववालों ने निश्चय किया कि वे एक विकल्प तैयार करेंगे. उन्होंने अपनी योजना बताई कि वे रेलवे स्टेशन बनाना चाहते हैं. रेल प्रशासन ने उनकी योजना पर ग़ौर किया और उसे लगा कि यह संभव है. इसके बाद काम शुरू हो गया. गुड़गांव–रेवाड़ी लाइन पर पड़ने वाले इस स्टेशन पर इस रूट की सात ट्रेनें रुकेंगी. यह स्टेशन बहुत ही साधारण है और इसे हाल्ट कहना ज़्यादा बेहतर है. गांववाले बहुत ख़ुश हैं कि अब उन्हें आसपास के इलाक़ों में जाने के लिए कहीं और नहीं, बल्कि अपने गांव के स्टेशन तक ही जाना पड़ेगा. एक पुरानी कहावत है कि आप उस बदलाव का पहिया ख़ुद बनें, जिसे आप अपनी दुनिया में देखना चाहते हैं. ताजनगर के निवासियों ने इसे साबित करके दिखा दिया है. इसे कहते हैं जज़्बा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
यह सप्ताह आपके सामाजिक–राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि करेगा. समारोह–कार्यक्रम में भाग लेते समय अपनी भूमिका को अच्छी तरह पूरा करने की कोशिश करें. यदि किसी ग़लत व्यक्ति के संपर्क में हैं तो उससे दूरी बनाए रखना ज़रूरी है, अन्यथा आपकी साख पर धब्बा लग सकता है.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
कला और रचनात्मक शक्ति के बल पर वरिष्ठ अधिकारियों एवं सहयोगियों से प्रशंसा मिल सकती है. पदोन्नति के लिए भी आपका नाम प्रस्तावित हो सकता है. यदि आप तन्मय होकर और भी कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी यह सप्ताह अच्छा है.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
इस सप्ताह कोई चिंता परेशान कर सकती है. यदि आप यात्रा करने वाले हैं या किसी व्यक्ति से मिलने का समय निर्धारित कर रहे हैं तो उसमें व्यवधान आ सकता है. इन्हीं कारणों से स्वास्थ्य में गिरावट आएगी और अनावश्यक ख़र्च बढ़ सकता है.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
जब भी आप घर या बाहर किसी बहसबाजी या वाद–विवाद में उलझ जाते हैं तो आपकी उन्नति रुक जाती है. इस सप्ताह भी कुछ ऐसा ही उलझन भरा दौर सामने आ रहा है. बेहतर होगा कि आप अपने काम से काम रखें और दूसरों को बिन मांगी सलाह देने से बचें.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
काफी समय बाद आप अनुकूल समय आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं. हो सकता है, इस सप्ताह भी आपको धोखा ही मिले. यदि प्रतिकूल समय चल रहा हो तो थोड़ी–बहुत सफलता को भी काफी समझना चाहिए. अंधकार में छोटी सी चिंगारी भी मार्गदर्शक बन जाती है.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
नए और प्रभावशाली दोस्त हमेशा आपके लिए काम निकालने में अच्छे साबित होते हैं. इस सप्ताह भी आपको कुछ जटिल कार्य पूरे करने के लिए किसी प्रभावशाली दोस्त की मदद मिलेगी. आप भी समय पर उनके सहयोग की भरपाई कर देते हैं, लेकिन जल्दबाज़ी में कुछ ऐसा न कर डालें कि दूसरा व्यक्ति आपको स्वार्थी समझ ले.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
आप कुछ ऐसी रणनीति अपनाएंगे, जिससे आपके विरोधियों और शत्रुओं का सिर नीचा हो सकता है. आर्थिक और व्यापारिक मामलों में सुधार के प्रयास सफल होंगे. राजनीतिक हस्तियों से भी फ़ायदा मिलने की उम्मीद रहेगी. समाज में आपके लिए प्रतिष्ठा के नए द्वार खुल सकते हैं.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
कभी–कभी ऐसा भी होता है कि थोड़े से परिश्रम या इच्छाशक्ति के चलते कोई काम अचानक बन जाता है. इस सप्ताह कुछ ऐसी ही घटनाएं आपके साथ होंगी. जिस उपलब्धि के लिए आप कभी सपना देखते थे, वही आपको अचानक मिलने वाली है.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
इस सप्ताह कुछ प्रतिकूल समाचार मिलने से मन अशांत होगा. कोई शुभचिंतक या दोस्त अपने किए गए वायदे से मुकर सकता है. किसी बड़े लेनदेन में उलझ जाने से कोई भारी आर्थिक बोझ भी आप पर पड़ सकता है. जो कुछ भी आप करें, उसके लिए अपने सहयोगियों का विश्वास अवश्य जीत लें.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
इस सप्ताह आपके पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. जो काम या कारोबार काफी समय से मंदा चल रहा है, उसमें एक नई गति आने की संभावना है. अब आपको ज़्यादा समय तक धन की तंगी से नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि परिवार के सदस्य आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
कुछ अच्छा माहौल बनने से इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में उत्साह और ताजगी महसूस होगी. कोई नया व्यक्ति या सहयोगी आपको कामकाज निपटाने में मदद दे सकता है. यदि आप रोमांस या प्रेम प्रकरण में उलझना पसंद करते हैं तो उसके लिए भी तैयार रहें.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
इस सप्ताह आपके उत्साह और पराक्रम में वृद्धि होने से इच्छित प्रयासों में सफलता मिलने की उम्मीद है. कई बार आप अपने संकल्प को तोड़ने की भी सोचते होंगे, लेकिन भाग्य जहां प्रबल होता है, वह काम किसी न किसी तरह पूरा हो जाता है.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

याद रखने की बात है कि पाकिस्तानी जनता भी पिछले कुछ समय से आतंकवाद की शिकार है.

ओसामा की मौत ने पाकिस्तान की पोल खोल दी

सिद्धार्थ राय

फ़र्ज़ कीजिए कि अगर ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के ऐबटाबाद में नहीं, दिल्ली में मारा गया होता तो जनता क्या करती? जवाब यह है कि हमारे हाथ नेताओं के गिरेबानों तक होते और सरकार को इस्तीफ़ा देना पड़ता. लेकिन, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहां लोकतंत्र तो है, पर उसके पास न अधिकार हैं और न देश के लोगों का समर्थन. हुक्मरान अपने आक़ाओं के सामने बेबस हैं, जिनका नाम पाकिस्तानी सेना और आईएसआई है. पाकिस्तान हाशिए पर तो था ही, अब ऐसा न हो कि वह दूसरा अफ़गानिस्तान बन जाए. दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन, जिसने अमेरिका जैसी विश्वशक्ति को नाकों चने चबवा दिए, कहीं और नहीं, बल्कि पाकिस्तान के ही एक ख़ुशनुमा शहर ऐबटाबाद में मारा गया. अमेरिकी सैनिकों ने उसे ऑपरेशन जेरोनिमो के तहत रात के अंधेरे में मार गिराया. सैन्य शब्दों में कहें तो एक गोली माथे पर और एक छाती में. ऐबटाबाद पाकिस्तान का कोई क़बायली सीमांत इलाक़ा नहीं है, बल्कि वह राजधानी इस्लामाबाद से मात्र कुछ कोसों की दूरी पर है. जिस मकान में ओसामा मारा गया, उसमें वह पिछले पांच सालों से रह रहा था. करोड़ों की लागत से बने इस आलीशान मकान के चारों ओर 12–18 मीटर ऊंची दीवार का घेरा था. मकान से कुछ ही दूरी पर स्थित है पाकिस्तान सैनिक प्रशिक्षण अकादमी. मतलब यह कि जिस ओसामा को अमेरिका अफ़गानिस्तान–पाकिस्तान सीमा पर क़बायली इलाक़ों, पथरीली खाइयों और कंदराओं में ढूंढ रहा था, उसे अंत में अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसी सीआईए ने पाकिस्तान के दिल में पाया. अमेरिका विश्वशक्ति है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए उसने पाकिस्तान के घर में घुसकर ओसामा को मार गिराया. मतलब, पाकिस्तान का यह कहना कि वह ख़ुद आतंकवाद का शिकार है और इस वजह से वह अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के ख़िलाफ़ अमेरिकी मुहिम में एक विश्वसनीय साथी है, कोरा झूठ है. पाकिस्तान की क़लई विश्व समुदाय के सामने खुल गई है. उसे मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है. कहते हैं, खिसयानी बिल्ली खंभा नोचे. यही हाल आज पाकिस्तान का है. उसने एक बार फिर भारत विरोध की धुन छेड़ दी है, ताकि जनता और अमेरिका का ध्यान बंटकर भारत–पाकिस्तान संबंधों पर केंद्रित हो जाए. इस घटना ने पाकिस्तान को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है. ऐसे सवाल, जो उसके वजूद पर ही उंगली उठाते हैं. पाकिस्तान में एक शब्द बहुत प्रचलित है–डीप स्टेट यानी सेना और ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई. इन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यहां सतह पर तो प्रजातंत्र नज़र आता है, लेकिन देश का सही मायने में संचालन सेनाध्यक्ष और आईएसआई प्रमुख के हाथों में है. देश की आंतरिक और विदेश नीति बनाने–चलाने का काम भी यही लोग करते हैं. एक बार पूर्व आईएसआई प्रमुख दुर्रानी ने कहा भी था कि आतंकवाद तो पाकिस्तान की नीति है, जिसके सहारे वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है. उनका कहना था कि पाकिस्तान को यह बात स्वीकारने में कोई शर्म भी नहीं आनी चाहिए, न तो भारत के सामने और न अमेरिका के. यह भी अजीब बात है कि एक तरफ़ तो पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में ख़ुद को अमेरिका का दोस्त बताता है और दूसरी ओर आतंकवाद को अपनी मान्यता प्राप्त नीति भी कहता है. वैसे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यह कोई नई बात नहीं है. यथार्थवादी अमेरिकी नीतिकारों ने पाकिस्तान को यह सब जानते हुए भी इसलिए पोस रखा है, क्योंकि पाकिस्तान उनकी अफ़गान योजना का हिस्सा है और जो कि उसके आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध का सबसे बड़ा क्षेत्र है. पाकिस्तान को भी यह पता है, इसलिए उसने एक तरफ़ भारत और अफ़गानिस्तान में आतंकियों को सहारा दे रखा है और दूसरी तरफ़ अमेरिका के साथ खड़ा है. मतलब यह कि आज तक आईएसआई ने अमेरिका को एक तरह से अफ़गान युद्ध की वजह से बंधक बना रखा था, लेकिन अब वस्तुस्थिति बिल्कुल अलग हो गई है. पिछले दस सालों से अफ़गान युद्ध प्रमुखतः अलक़ायदा और ओसामा के विरोध में चल रहा था, लेकिन सीआईए जैसी ख़ुफ़िया एजेंसी भी ओसामा को खोजने में नाकाम रही. इसीलिए जब इस बार ओसामा का पता चला तो अमेरिका ने कोई ग़लती नहीं की और उसके मारे जाने के बाद सीआईए के प्रमुख लीओन पनेटा ने साफ़ कहा कि पाकिस्तान को इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि हर बार की तरह अमेरिका को डर था कि कहीं पाकिस्तानी ख़ुफ़िया अधिकारी इसकी सूचना लादेन को न दे दें. पनेटा के इस बयान से भी अंतरराष्ट्रीय पटल पर पाकिस्तान की बहुत किरकिरी हुई. पाकिस्तान के डीप स्टेट को लगता था कि वह ओसामा को बचाने का घिनौना खेल आगे भी खेलता रहेगा, लेकिन अमेरिका ने उसके मुंह पर कालिख पोत दी है. अब तक सिर्फ़ शक होता था कि पाकिस्तान आतंकियों को शरण देता है, लेकिन ओसामा के मारे जाने और पाकिस्तान को इसकी भनक न लगने की बात ने इसकी पुष्टि भी कर दी है. इस खिचड़ी में कुछ ऐसे पक्ष हैं, जिन पर साफ़ तौर पर कुछ कह पाना मुश्किल है. जैसे, क्या पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अपनी एक बड़ी भूमिका और दायित्व के लिए अमेरिका के हाथों ओसामा को बेच दिया? वजह, हाल में ही अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की बात कही थी और यह सभी जानते हैं कि पाकिस्तान पहले की तरह अफ़गानिस्तान को अपनी गोद में रखना चाहता है. इसीलिए उसने हमेशा भारत द्वारा अफ़गानिस्तान में चलाई जा रही सामाजिक योजनाओं का विरोध किया. वैसे पाकिस्तान अब अपने ही पैदा किए जेहादियों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिए गए झूठे बयानों के बीच फंस गया है. अगर वह अपनी साख बचाने के लिए कहता है कि उसे अमेरिका की योजना के बारे में पता था तो जेहादी इसे इस्लाम के प्रति विश्वासघात समझेंगे और पाकिस्तान के दोस्त ही उसके दुश्मन बन जाएंगे. अगर पाकिस्तान यह कहता है कि उसे कुछ मालूम ही नहीं था तो उसकी बेइज़्ज़ती होती है और अमेरिका से उसके संबंधों में दरार आती है. ऐसे में वह भारत सरीखे देशों के भी निशाने पर आ जाता है, जो हमेशा से कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तानी धरती से ही पूरे विश्व में आतंकवाद की आपूर्ति होती है.

उधर पाकिस्तानी जनता इन अलग–अलग बयानों से आहत और हक्की–बक्की है. पाकिस्तानी मीडिया भी जनता को सही बात बता ही नहीं रहा है. कुछ अख़बार जेहादियों की, कुछ अमेरिका और कुछ पाकिस्तानी सेना एवं आईएसआई की बात कर रहे हैं. सबसे ज़्यादा चोट पहुंची पाकिस्तान के लोकतंत्र को, जो पहले ही सेना और ख़ुफ़िया तंत्र के हाथों की कठपुतली बना हुआ है और कोशिश में है कि गले में पड़े इस फंदे को कसने से किसी तरह रोका जाए. अब जबकि एक बाहरी मुल्क, जो भले ही ख़ुद को दोस्त कहता है, ने बिना पूछे पाकिस्तानी धरती पर हमला कर दिया, ऐसे में जनता के बीच नेताओं की रही–सही साख भी मिट्टी में मिल गई है. जनता आक्रोशित है, क्योंकि उसे लगता है कि यह देश की अस्मिता और अक्षुण्णता पर हमला है. वैसे ओसामा की मौत के ड्रामे में पाकिस्तानी ख़ुफ़िया तंत्र का हाथ होना इसलिए भी लाज़िमी लगता है, क्योंकि उसे पता है कि इसका सबसे बड़ा असर देश के लोकतंत्र और नेताओं पर पड़ेगा, जिन्हें सेना पहले से ही कमज़ोर करने पर आमादा है. पाकिस्तानी जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस पर विश्वास करे और किस पर नहीं. वह आश्चर्यचकित है कि ओसामा जैसा शख़्स उसके बगल में पिछले दस सालों से मौजूद था और उसे भनक तक नहीं लगी. याद रखने की बात है कि पाकिस्तानी जनता भी पिछले कुछ समय से आतंकवाद की शिकार है. अब तो अमेरिकी कांग्रेस पाकिस्तान का ख़ून मांग रही है. उसने साफ़ कर दिया है कि अमेरिका अभी तक हुए विश्वासघात का बदला पाकिस्तान से ज़रूर लेगा. उसने पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बड़े पैमाने पर काटने का मन बना लिया है. मतलब यह कि अब पाकिस्तानी सेना के अफसर अपने ही पैदा किए आतंकियों के बदले अमेरिका से पैसे नहीं ऐंठ पाएंगे. अमेरिकी पैसे के बिना न तो आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा सकता है और न पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चलाई जा सकती है. इस पूरे परिदृश्य में यह ख़ास बात उभर कर सामने आई कि भारत की पाकिस्तान नीति किस तरह विफल रही है. सवाल यह उठता है कि जब पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त बनते हुए भी उसके सबसे बड़े दुश्मन को अपने यहां पाल–पोस सकता है तो फिर भारत तो उसका दुश्मन है. इसलिए यह सोचना अपने आप में बहुत बड़ी भूल है कि पाकिस्तान 26/11 के दोषियों को सज़ा देगा या उन्हें भारत को सौंपेगा. दिल्ली में यथार्थवादियों से लेकर आदर्शवादियों तक को यह बात समझ में आ गई है कि भारत आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान से किसी भी मदद की उम्मीद नहीं कर सकता और मनमोहन सिंह की क्रिकेट कूटनीति नाकाम हो गई है. भारत ने हमेशा अपने पक्ष में बने माहौल को गंवा दिया, लेकिन इस बार ऐसा करना बहुत हानिकारक होगा. यही मौक़ा है भारत के पास, जबकि वह पूरे विश्व में उभरे पाकिस्तान विरोधी स्वरों को अपने हितों के लिए इस्तेमाल करे. पाकिस्तान को उसका आतंकी तंत्र तोड़ने के लिए मजबूर करने का इससे बेहतर मौक़ा हाथ नहीं आएगा. दिल्ली में बैठे नेताओं को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के विदेश सचिव कह चुके हैं कि भारत को 26/11 की बात अब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह मामला अब बासी हो गया है.

पाकिस्तानी जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस पर विश्वास करे और किस पर नहीं. वह आश्चर्यचकित है कि ओसामा जैसा शख़्स उसके बगल में पिछले दस सालों से मौजूद था और उसे भनक तक नहीं लगी. याद रखने की बात है कि पाकिस्तानी जनता भी पिछले कुछ समय से आतंकवाद की शिकार है.

feedback@chauthiduniya.com

नेपाल

हर घर में राजशाही की चर्चा

नेपाल की राजनीति इन दिनों दो ख़ेमों में बंटी हुई है, वामपंथी और लोकतांत्रिक. ज़रूरत इस बात की है कि सभी राजनीतिक दल संविधान निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते, लेकिन फिलहाल वे ऐसा करते नहीं दिखाई दे रहे हैं.

एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के अध्यक्ष पुष्प दहल प्रचंड के साथ एक गोपनीय समझौते के फलस्वरूप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मॉक्सर्वाद–लेनिनवाद (माले) के अध्यक्ष झालानाथ खनाल प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन देश का संविधान बनाने की दिशा में आज तक कोई सार्थक पहल नहीं हो सकी है. खनाल को प्रचंड के अलावा नेकपा (माले), नेकपा (माले समाजवादी), नेकपा (एकीकृत), नेसपा (आनंदी देवी), राष्ट्रीय जनमोर्चा, नेपाल राष्ट्रीय पार्टी और जनता दल का समर्थन हासिल है. नेपाल की राजनीति इन दिनों दो ख़ेमों में बंटी हुई है, वामपंथी और लोकतांत्रिक. ज़रूरत इस बात की है कि सभी राजनीतिक दल संविधान निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते, लेकिन फिलहाल वे ऐसा करते नहीं दिखाई दे रहे हैं. जबकि देश की जनता ने 601 सदस्यों का चुनाव इसीलिए किया था कि वे दो वर्षों के भीतर संविधान निर्माण का काम पूरा कर लेंगे, लेकिन गत वर्ष 28 मई को यह समय सीमा ख़त्म हो गई, फिर भी संविधान नहीं बन सका और सदस्यों ने इस समय सीमा को एक साल के लिए और बढ़ा दिया, जो आगामी 28 मई को एक बार फिर ख़त्म होने वाली है तथा अब भी संविधान का कहीं कोई नामोनिशान तक नहीं है. जनता का राजनीतिक दलों पर भरोसा अब ख़त्म होने लगा है, क्योंकि देश में हर तरफ़ अव्यवस्था का बोलबाला है. महंगाई, भ्रष्टाचार, हत्या, अपहरण और अवैध उगाही के चलते लोगों का जीना दूभर हो गया है. कभी शांति और सुंदरता के लिए विख्यात रहा नेपाल आज एक अशांत देश बन चुका है. जनता को लगता है कि राजशाही ही देश की सारी समस्याओं का निराकरण कर सकती है, इसलिए उसकी निगाहें अब राजशाही की वापसी की ओर टिक गई हैं. लोग चाहते हैं कि पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह एक बार फिर नेपाल की बागडोर संभालें. आज देश के लगभग हर घर में राजशाही की चर्चा सुनने को मिल जाती है. जनता अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को अब नफ़रत की निगाह से देखती है. बीती 20 जनवरी को प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम में जब सुंसरिका इटहरी पहुंचे तो एक किसान ने मंच पर चढ़कर उन्हें थप्पड़ रसीद कर दिया और कहा कि तुम नेता लोग जब सरकार नहीं बना पा रहे हो तो संविधान क्या बनाओगे. इससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि देश की जनता का धैर्य किस कदर जवाब दे रहा है. इधर पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह और पूर्व युवराज पारस एक बार फिर सार्वजनिक सामाजिक–धार्मिक समारोहों में शिरकत करने लगे हैं. वे जहां जाते हैं, जनता जमकर नारेबाज़ी करती है कि हमारा राजा प्राण से प्यारा, राजशाही वापस हो. मालूम हो कि नेपाली जनता अपने राजा को भगवान विष्णु का अवतार मानती है. पूर्व युवराज पारस ने पिछले दिनों राजधानी काठमांडू स्थित पुराने वानेश्वर में खडगी समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में न सिर्फ़ हिस्सा लिया, बल्कि उन्होंने धनगढ़ी स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा–अर्चना करने के साथ–साथ वहां निर्माणाधीन धर्मशाला का कामकाज भी देखा. इसी तरह पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र वीर विक्रम ने भी वस्तुपुर, महादेव मंदिर, विराट नगर और ललितपुर में आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जहां मौजूद लोगों ने उनका बड़े उत्साह के साथ स्वागत–अभिनंदन किया. वहीं दूसरी तरफ़ देश के राजनीतिक दल जनता की समस्याओं के समाधान में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं. भारत ने भी नेपाल की मौजूदा स्थितियों पर चिंता ज़ाहिर की है. पिछले दिनों भारत के विदेश मंत्री एस एम कृष्णा ने नेपाल के शीर्ष नेताओं से बातचीत करके वहां जारी राजनीतिक गतिरोध को अतिशीघ्र दूर करने का आग्रह किया. उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल के स्थायित्व और बहुदलीय लोकतंत्र के लिए भारत हर तरह की सहायता करने को तैयार है.

रवि शंकर प्रसाद साह
feedback@chauthiduniya.com

परमात्मा को पहचान कर खुद को पहचानते हैं, अपने संस्कार परिवर्तन के कार्य में लग जाते हैं, वे परमात्मा के कार्य में लगे हैं, क्योंकि परिवर्तन से ही सृष्टि परिवर्तन और युग परिवर्तन संभव है.

दिल्ली, 16 मई–22 मई 2011
चौथी दुनिया

परमात्मा कौन

सब परमात्मा को खुश करने के लिए किया था तो इंतजार करते हैं कि हमारे सारे काम बनते जाएं, क्योंकि हमने यह भी तो माना है कि अगर परमात्मा खुश है तो हमारे सारे काम बनते जाएंगे.

कनुप्रिया

बचपन से लेकर आज तक हमने परमात्मा को कई बार पुकारा, जगह-जगह तलाशा, कई-कई रूपों में देखने का प्रयत्न किया, लेकिन उसके सही स्वरूप को समझ नहीं पाए और हर बार कन्फ्यूज. कई बार उसकी हस्ती को ही नकार दिया या फिर थक- हारकर अपने-अपने दायरों में परमात्मा को कैद कर लिया. आज ही किसी से बात हुई तो उन्होंने कहा, परमात्मा को याद करना, उसका नाम स्मरण करना ही तो परमात्मा का कार्य है. उसके नाम पर दान-पुण्य करना, मंदिर में जाकर रोज दर्शन करना, उसे प्रसाद चढ़ाना आदि भी तो परमात्मा के कार्य हैं, इससे परमात्मा खुश होंगे, लेकिन ध्यान देने की बात है कि परमात्मा, जो सर्वशक्तिमान, दया का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर है, वह क्यों अपना नाम पुकारे जाने, खुद को याद किए जाने या अपने नाम पर दान-पुण्य होने पर खुश होगा? इसका मतलब कि पहले वह नाराज है. क्या यह संभव है? वह जो प्रेम का सागर है, क्या कभी किसी से नाराज हो सकता है?

समझने की बात यह है कि हम परमात्मा को खुश करने के नाम पर या परमात्मा का कार्य मानकर जो कुछ भी करते हैं, वह असल में स्वयं को खुश करने के लिए, स्वयं को आश्वस्त करने के लिए करते हैं कि हम कुछ सही काम कर रहे हैं और अगर हम यह सब करते रहेंगे तो हमारा रास्ता सही रहेगा. लेकिन चूंकि हमने इन सब को परमात्मा को खुश करने का साधन बना दिया, इसलिए न तो इन्हें करते हुए हमें जो आनंद प्राप्त होना चाहिए, वह होता है, बल्कि हम ज्यादा तनाव में रहते हैं कि हम ये सब चीजें सही तरह से करें, साथ ही अपने पर और बोझ डालते जाते हैं. दूसरी तरफ, क्योंकि ये सब परमात्मा को खुश करने के लिए किया था तो इंतजार करते हैं कि हमारे सारे काम बनते जाएं, क्योंकि हमने यह भी तो माना है कि अगर परमात्मा खुश है तो हमारे सारे काम बनते जाएंगे. अब अगर हमारे काम नहीं बनते तो हम सोचते हैं कि परमात्मा हमसे नाराज है, हमारे खुश करने के सारे तरीके फेल हो रहे हैं. तो हम भी या तो परमात्मा से नाराज हो जाते हैं या फिर भय में आकर कुछ और तरीकों से उसे प्रसन्न करने लगते हैं. दोनों ही सूरत में हम परमात्मा से दूर होते जाते हैं. सही अर्थों में परमात्मा को जनाना है खुद को जानना. मैं इस शरीर का मालिक. मैं शरीर नहीं, चैतन्य शक्ति हूं. पवित्रता, प्रेम, शांति, आनंद, ज्ञान एवं सुख मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं उन्हीं का स्वरूप हूं, मैं मेरा मूल संस्कार है, पर क्योंकि मैं शरीर में रहकर इन्हें व्यवहार में लाता हूं, कर्म बंधन में बंधता हूं, इसीलिए अपने मूल संस्कारों को क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, मोह, लालच, अहंकार एवं लोभ के वंश होकर कार्यों के बंधन में और जकड़ता जाता हूं. परमात्मा जो मेरा पिता है, इस शरीर के बंधन से न्यारा है, मेरी ही तरह चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु है, वह किसी भी कार्य बंधन में नहीं बंधता, क्योंकि वह शरीर के बंधन में नहीं आता, लेकिन वह भी बंधा है समय चक्र के सृष्टि परिवर्तन के अपने कर्तव्य से. दु:ख से भरी जिंदगी से बाहर निकालने के लिए वह हमें हमारा परिचय कराता है. जो परमात्मा को पहचान कर खुद को पहचानते हैं, अपने संस्कार परिवर्तन के कार्य में लग जाते हैं, वे परमात्मा के कार्य में लगे हैं, क्योंकि हमारे सामूहिक संस्कार परिवर्तन से ही सृष्टि परिवर्तन और युग परिवर्तन संभव है. इसलिए परमात्मा को पहचानना, उसके ज्ञान के आधार पर स्वयं में दिव्य गुणों को धारण करने का कार्य परमात्मा का कार्य है.

ओम साई राम.

feedback@chauthiduniya.com

साई की महिमा

श्री साई राम परम सत्य, प्रकाश रूप,
परम पावन शिरडी निवासी, परम ज्ञान आनंद
स्वरूप, प्रज्ञा प्रदाता, सच्चिदानंद स्वरूप,
परम पुरूष योगीराज, दयालु देवाधिदेव हैं,
उनको बार बार नमस्कार.

भक्तों की पुकार

एक साल बाद रागिनी ने साई बाबा की एक मूर्ति स्थापित की. धीरे-धीरे आसपास के लोगों को साई बाबा के चमत्कार का पता चला. लोगों ने साई बाबा की पूजा करनी शुरू कर दी. देखते ही देखते बाबा के दर्शन के लिए मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी.

अगर आप जीवन में किसी भी तरह के संकट से गुजर रहे हों तो साई बाबा को याद करें. उनके पास जाकर ध्यान लगाएं. अगर आपको विश्वास नहीं होता तो हम आपको बताते हैं एक ऐसे साई भक्त की कहानी, जिसकी जिंदगी तबाह होने के कगार पर थी. बाबा की भक्त रागिनी लंबे समय से परेशान चल रही थीं. उनके घर में रोज कोहराम मचता था. रागिनी का कहना है कि ऐसा लगता था कि मानो अपने ही परिवार में लोग एक-दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं. उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें. तभी किसी ने रागिनी को साई बाबा की शरण में जाने को कहा. रागिनी को एक मिनट के लिए लगा कि ऐसी हालत में कोई क्या कर सकता है. पहले तो उन्होंने सलाह मानने से इंकार कर दिया. बाद में रागिनी को लगा कि एक बार साई का दर्शन करने में क्या दिक्कत है.

रागिनी बाबा के दर्शन के लिए शिरडी पहुंच गईं. फिर क्या था, बाबा ने रागिनी को अपनी शरण में ले लिया. शिरडी में बाबा ने रागिनी को साक्षात दर्शन दिए. बाबा ने उन्हें घर लौटने की सलाह दी. रागिनी जब वापस पटना लौटीं तो उन्होंने साई बाबा की फोटो लगाकर पूजा करनी शुरू कर दी. लगभग एक साल बाद रागिनी ने साई बाबा की एक मूर्ति स्थापित की. धीरे-धीरे आसपास के लोगों को साई बाबा के चमत्कार का पता चला. लोगों ने साई बाबा की पूजा करनी शुरू कर दी. देखते ही देखते बाबा के दर्शन के लिए मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी. रागिनी को लगा कि उनकी मेहनत सफल रही. बाबा को उनकी भक्ति रास आ गई. जब लोग इस मंदिर में अपना दु:ख-दर्द लेकर पहुंचने लगे तो उनके साथ भी चमत्कार होने लगा. इसलिए कहते हैं कि बाबा को मन से साधो, उनकी कृपा जरूर होगी. रागिनी की भक्ति से खुश होकर साई बाबा ने मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले हर भक्त पर अपनी कृपा दिखानी शुरू कर दी.

इन्हीं में एक भक्त थीं नेहा. उनकी नौकरी लगने वाली थी. सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, पर जब नेहा घर से निकलने वाली थीं, तभी अचानक उनका ज्वाइनिंग लेटर कहीं गुम हो गया. नेहा ने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन जब तमाम कोशिशों के बाद भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला तो नेहा रोते-रोते पहुंच गईं साई बाबा के मंदिर में. नेहा ने बाबा के सामने अपना सारा दु:ख कह डाला. उदास नेहा घर लौट आईं, लेकिन जैसे ही वह घर में घुसीं कि सामने उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दिख गया. लेटर मेज पर रखा हुआ था. जबकि नेहा ने मेज पर कई बार ढूंढा था. अब नेहा जब भी अपनी तनख्वाह उठाती है तो उसे एक दिन बाबा के चरणों में रखती हैं और फिर उसके बाद खर्च करती हैं. पटना के इस साई मंदिर पर शुरू में लोगों को विश्वास नहीं होता था. लोग देखकर मजाक उड़ाया करते थे, पर आज इस साई मंदिर में भीड़ लगी रहती है. जो भी साई भक्त अपना दु:ख लेकर वहां जाते हैं, दरबार में पहुंचते ही हंसने-मुस्कराने लग जाते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

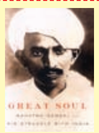

तक़रीबन दो वर्ष बाद विनोदी स्वभाव के गांधी ने अपने दोस्त से समझौते के लिए एक अर्द्ध सहमति पत्र बनाया था, जिसमें वैसे नामों का प्रयोग किया गया था, जिसे हम मज़ाकिया कह सकते हैं.

अनंत विजय

पुराने तथ्य, नई किताब

कुछ दिनों पहले ही हिंदी-अंग्रेजी में एक साथ प्रकाशित वेबसाइट फेस एंड फैक्ट्स के प्रबंध संपादक जयप्रकाश पांडे का बेहद गुस्से में फोन आया. उन्होंने बताया कि न्यूयॉर्क टाइम्स के पूर्व कार्यकारी संपादक जोसेफ लेलीवेल्ड ने महात्मा गांधी का अपमान करते हुए एक किताब लिखी है-ग्रेट सोल: महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया. उसमें गांधी को समलैंगिक क़रार दिया गया है. जब मैंने पूछा कि उन्हें यह बात कहां से पता चली तो उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के अख़बार डेली मेल ने एक लेख छापा है, जिसका शीर्षक है -गांधी लेफ्ट हिज वाइफ टू लिव विद मेल लवर. यह लेख जोसेफ लेलीवेल्ड की नई किताब के हवाले से छापा गया था. उन्होंने तत्काल मुझसे प्रतिक्रिया मांगी, ताकि उसे प्रकाशित किया जा सके. चूंकि मैंने न तो किताब पढ़ी थी और न डेली मेल का लेख पढ़ा था, इसलिए मैंने गांधी से जुड़ी एक कहानी सुना दी. एक बार गांधी ट्रेन से सफर कर रहे थे. किसी स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो उन्होंने देखा कि एक आदमी उनसे मिलने की कोशिश कर रहा है और उनके समर्थक उसे रोक रहे हैं. वह लगातार मिन्नतें कर रहा है, लेकिन लोग उसे उन तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं. गांधी ने लोगों से मामले की जानकारी चाही. उन्हें बताया गया कि जो आदमी उनसे मिलने की जिद कर रहा है, दरअसल वह एक लेखक है और उसने उन्हें केंद्र में रखकर एक किताब-ROGUE OF INDIA लिखी है. वह उस किताब पर उनके दस्तख़त चाहता है. लोगों को लग रहा था कि जिस किताब का शीर्षक ही इतना अपमानित करने वाला है, उसमें भीतर तो और भी विषवमन होगा. इस वजह से उसे गांधी से मिलने से रोका जा रहा था. गांधी को जब पूरी बात पता चली तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया, प्यार से बैठाया और हाल-चाल पूछने के बाद उसकी लिखी किताब पर हस्ताक्षर करके उसे वापस लौटा दिया. उसके जाने के बाद गुस्साए समर्थकों ने बापू से पूछा कि उन्होंने उस व्यक्ति की किताब पर हस्ताक्षर क्यों किए, जो उन्हें ROGUE OF INDIA बता रहा है. गांधी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि सबको अपनी राय बनाने और उसे व्यक्त करने का हक़ है.

यह कहानी सुनाकर मैं उस वक़्त तो निकल गया, लेकिन मेरे मन में गांधी पर लिखी लेलीवेल्ड की किताब पढ़ने की इच्छा बढ़ने लगी. दो-तीन दुकानों पर फोन करने पर पता चला कि यह किताब अभी भारत में उपलब्ध नहीं है. फिर मैंने डेली मेल का लेख पढ़ा. उसे पढ़ने के बाद पूरा तो नहीं, लेकिन माजरा कुछ-कुछ समझ में आने लगा. इस बीच मुंबई के एक अख़बार ने डेली मेल के लेख के हवाले से यह ख़बर छाप दी कि एक जर्मन व्यक्ति गांधी का सीक्रेट लव था. यह लेख छपने के बाद बवाल मचना था, सो मचा. बग़ैर पढ़े-देखे, आनन-फानन में गुजरात विधानसभा ने सूबे में किताब पर पाबंदी लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. महाराष्ट्र में भी ऐसी ही मांग उठी कि लेलीवेल्ड की किताब पर प्रतिबंध लगा दिया जाए. केंद्र सरकार के मंत्री भी इसमें राष्ट्रपिता का अपमान देखने लगे. यह सब कुछ सिर्फ़ एक लेख की बिना पर होने लगा, बग़ैर किताब पढ़े. लेकिन अब यह किताब भारत में उपलब्ध है. मुझे लग रहा था कि गांधी के बारे में इस किताब में कुछ नया ख़ुलासा होगा, लेकिन पढ़ने के बाद निराशा हुई और लगा कि डेली मेल का लेख बेहद सनसनीख़ेज़ और सत्य से परे था.

दरअसल पश्चिमी देशों में किताब को हिट कराने का यह घिसा-पिटा फॉर्मूला है. किताब के बाज़ार में आते ही उसके बारे में उत्सुकता का ऐसा वातावरण तैयार किया गया और प्रकाशक या फिर लेखक के रणनीतिकारों ने बिक्री बढ़ाने के लिए गांधी की इस जीवनी के कुछ चुनिंदा अंश लीक किए, ताकि मीडिया में ख़बर बन सके और वे ऐसा करने में कामयाब भी हो गए. गांधी और हरमन कैलेनबाख के संबंधों के बारे में उनके कुछ पत्रों को इस तरह प्रचारित किया गया कि लेखक लेलीवेल्ड ने कोई महान खोज कर डाली हो. गांधी के बारे में कोई ऐसा सत्य उद्घाटित कर दिया हो, जो पहले से ज्ञात नहीं था. गांधी के जिन पत्रों को आधार बनाकर लेलीवेल्ड ने कुछ बातें की हैं, वे सालों से राष्ट्रीय अभिलेखागार और साबरमती आश्रम में मौजूद हैं. जब गांधी और कैलेनबाख के संबंधों को आधार बनाकर अख़बारों में लेख छपे, समीक्षाएं छपीं तो दुनिया भर में गांधी के प्रशंसकों ने इसका विरोध शुरू कर दिया. यह विरोध जितना तीव्र होता गया, किताब की बिक्री उतनी ही बढ़ती चली गई.

आधुनिक भारत अथवा कहें कि बीसवीं शताब्दी के विश्व इतिहास में महात्मा गांधी एक ऐसे शख्स हैं, जिसके व्यक्तित्व की गुत्थी सुलझाना विद्वानों के लिए एक बड़ी चुनौती है. उनके व्यक्तित्व के इतने आयाम हैं कि एक को पकड़ो तो दूसरा छूट जाता है. गांधी विश्व के इकलौते ऐसे शख्स हैं, जिनकी मृत्यु के साठ साल बाद भी उन पर एवं उनके विचारों-लेखन पर लगातार शोध और लेखन हो रहा है. न्यूयॉर्क टाइम्स के पूर्व कार्यकारी संपादक ने भी गांधी और उनके व्यक्तित्व को अपने तरीक़े से उद्घाटित करने का असफल प्रयास किया है. साठ के दशक में लेलीवेल्ड भारत में न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रतिनिधि थे. चूंकि वह भारत को नज़दीक से देख-समझ चुके थे, इसलिए उनसे गांधी और उनके पत्रों के आधार पर ऐसे सनसनीख़ेज़ निष्कर्षों की उम्मीद नहीं थी. अगर जोसेफ लेलीवेल्ड की किताब के कुछ अंशों पर नज़र डालें तो लेखक की मंशा साफ हो जाती है. गांधी अगर प्रेम में नहीं थे तो भी वह आर्किटेक्ट हरमन कैलेनबाख के प्रति आकर्षित थे. 1909 में लंदन से भेजे एक पत्र में गांधी ने कैलेनबाख को लिखा था, तुम्हारी तस्वीर मेरे शयनकक्ष में मैंटलपीस पर रखी है, जो मेरे बिस्तर के ठीक सामने है. वह आगे लिखते हैं, रुई के फाहे और वैसलीन नियमित तौर पर याद दिलाते हैं. मुद्दा तुम्हें और मुझे यह दिखाने का है कि तुमने कितनी पूर्णता से मेरे शरीर पर क़ब्ज़ा कर लिया है, यह एक प्रतिशोधपूर्ण गुलामी है (पृ-89). अब हम क़ब्ज़ा शब्द का क्या अर्थ निकालें या फिर पेट्रोलियम जेली के इस्तेमाल का, जो आज की तरह उस वक़्त भी मरहम के तौर पर उपयोग में आता था. विश्वसनीय अनुमान तो यह हो सकता है कि लंदन के होटल के कमरे में वैसलीन एनीमा के लिए रही होगी, जो गांधी की नियमित दिनचर्या में शामिल था या फिर यह किसी और उमंग के पहले की छाया रहा हो, जो उत्साह गांधी ने बूढ़े होने पर मालिश के लिए दिखाया था. मालिश के प्रति उनका लगाव सर्वविदित था और देश भर के दौरों के बीच वह महिलाओं से मालिश कराने में रुचि रखते थे. मालिश की उनके जीवनकाल में काफी चर्चा होती थी, जो कभी ख़त्म नहीं हुई.

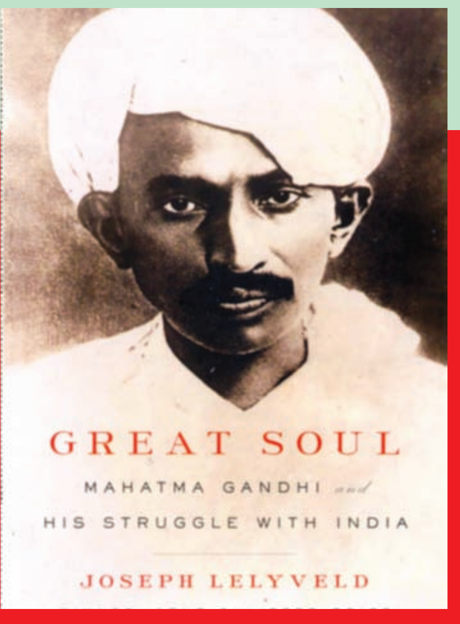

समीक्ष्य कृति-ग्रेट सोल : महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया
लेखक : जोसेफ लेलीवेल्ड
प्रकाशक : हॉर्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया, ए-53, सेक्टर 57, नोएडा
मूल्य : 699 रुपये

तक़रीबन दो वर्ष बाद विनोदी स्वभाव के गांधी ने अपने दोस्त से समझौते के लिए एक अर्द्ध सहमति पत्र बनाया था, जिसमें वैसे नामों का प्रयोग किया गया था, जिसे हम मज़ाकिया कह सकते हैं. वह उम्र में दो वर्ष छोटे कैलेनबाख को लोअर हाउस और ख़ुद को अपर हाउस कहते थे. कैलेनबाख के यूरोप दौरे के पहले 29 जुलाई, 1911 को आपसी सहमति पत्र में अपर हाउस ने लोअर हाउस से यह वादा कराया था कि उनकी ग़ैरहाज़िरी में कोई विवाह नहीं करेगा और न किसी महिला की ओर ललचाई नज़रों से देखेगा. इसके बाद दोनों हाउसों ने आपस में ज़्यादा प्रेम एवं फिर और ज़्यादा प्रेम का वादा किया. यह उस वक़्त की बात है, जब 1908 में गांधी की जेल यात्राओं और 1909 में उनकी लंदन यात्रा की अवधि छोड़कर साथ रहते हुए तक़रीबन तीन वर्ष बीत चुके थे. यहां यह बात स्मरणीय है कि हमारे पास सिर्फ़ गांधी के पत्र हैं, जो हमेशा से डियर लोअर हाउस से शुरू होते हैं. हम अगर उन पत्रों में लिखे गए अन्य संदर्भों और घटनाओं को छोड़ दें तो उनसे ही दोनों के बीच के प्रेम के सूत्र निकलते हैं. पत्रों की व्याख्या हमेशा दो तरह से की जा सकती है. एक तो हम अनुमानों के समंदर में डूब-उतरा सकते हैं और दूसरा तरीक़ा, यह देखें कि दो व्यक्ति अपनी यौन इच्छाओं के दमन के लिए अपने प्रयासों के बारे में क्या कहते-सोचते हैं.

लेलीवेल्ड ने इन्हीं पत्रों को आधार बनाकर गांधी के सेक्स जीवन के बारे में लिखा है, लेकिन लिखते वक़्त वह भूल गए कि गांधी में अपनी कामुकता को लेकर सार्वजनिक रूप से बात करने का अद्वितीय साहस था. 1906 में गांधी ने ब्रह्मचर्य अपना लिया था और उसके बाद वह अपनी कामेच्छाओं के बारे में खुलकर लिखते-बोलते थे और अपनी निजता का त्याग कर चुके थे. मालिश कराने के उनके शौक को लेलीवेल्ड ने कामेच्छा से जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें याद दिलाने की ज़रूरत है कि मालिश कराना और एनीमा लेना गांधी की दिनचर्या में उनकी ज़िंदगी के आख़िर तक बना रहा. सिर्फ़ इन बातों को आधार बनाकर गांधी के सेक्स जीवन की इस गलीज व्याख्या के लिए लेलीवेल्ड को जीवनी लिखने की ज़रूरत नहीं थी. अगर गांधी पर लिखी अन्य जीवनियों से इस किताब की तुलना करें तो यह एक बेहद कमज़ोर कृति है. दरअसल यह कृति गांधी की सही मायने में जीवनी भी नहीं है और न गांधी के बारे में जानने की इच्छा रखने वाले पाठकों के लिए उपयोगी है. किताब पढ़ते वक़्त महसूस होता है कि लेखक यह मानकर चल रहा है कि पाठक को गांधी और उनके क्रियाकलापों के बारे में जानकारी है. अंत में सिर्फ़ इतना कहा जा सकता है कि लेलीवेल्ड ने अपने तरीक़े से गांधी के पुरुष मित्रों के संबंधों को व्याख्यायित किया है और इसका उन्हें हक़ भी है. किताब पर पाबंदी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है. ख़ुद गांधी भी अगर जीवित होते तो इस पर पाबंदी के ख़िलाफ़ होते.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

आम आदमी के दुःख-दर्द की कविता

महेंद्र अवधेश

कोई माने या न माने, लेकिन सच यही है कि कविता की कोई शास्त्रीय परिभाषा नहीं होती. वह हर पंक्ति कविता है, जो तरीक़े से आम आदमी के दु:ख-दर्द की बात करती है, घर-आंगन की बात करती है, समाज के काले पक्ष पर रोशनी डालती है और देश-दुनिया के प्रति अपनी चिंता को ज़ाहिर करती है. मुकुल सरल की कविता भी आम आदमी, घर-परिवार, समाज और देश-दुनिया की बात करती है. एक ज़िम्मेदार इंसान, एक ज़िम्मेदार पिता-पति, एक ज़िम्मेदार सामाजिक प्राणी और एक ज़िम्मेदार नागरिक की हैसियत से मुकुल अपनी कविताओं के ज़रिए कई सवाल उठाते हैं, उसकी वजह बताते हैं और साथ ही समाधान भी प्रस्तुत करते हैं.

हाल में प्रकाशित उनका पहला काव्य संग्रह-उजाले का अंधेरा पचास कविताओं का वह गुलदस्ता है, जिसमें जीवन के कई रंगों से साक्षात्कार होता है. घर से शुरू हुई जद्दोजहद वैश्विक पटल पर जाकर ठहरती है और शायद इसीलिए संग्रह की पहली कविता है-कविता की साइकिल, जिसमें एक ज़िम्मेदार पिता अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के सुनहरे सपने बुनता, बल्कि उन्हें पूरा करने की कोशिश करता भी दिखाई देता है-

बस एक पंक्ति और/कुछ शब्द और ठीक बैठ जाएं
और सखी की साइकिल तैयार/बस पंख लगा रहा हूं हैंडिल में
टायरों में भर रहा हूं सपनों की उड़ान
लगा रहा हूं हौसलों के पैडिल

मुकुल की कविताएं बताती हैं कि एक कवि, एक रचनाकार, एक लेखक यानी एक संवेदनशील व्यक्ति के कर्तव्य क्या हैं, उसे अपने आसपास मौजूद वस्तुओं, स्थितियों और दृश्यों को किस तरह देखना-समझना चाहिए. न सिर्फ़ इतना, बल्कि उसके प्रति जनसामान्य, समाज और देश को सचेत कैसे करना चाहिए. इसलिए वह आज की भौतिकवादी जीवनशैली के ख़तरों और समाजवाद का लबादा ओढ़कर सामने आने वाले पूंजीवादी-सामंती स्वभाव के प्रति आगाह करते हैं-

ये अंधेरा न वो अंधेरा है/कि जिसके बाद तय सवेरा है
जिस उजाले ने हमें घेरा है/उस उजाले का ये अंधेरा है

****

ये अंधेरा बड़ा भयानक है/और कहता है कि वही हक़ है
रोशनी ओढ़कर ये आया है/इसने सूरज को भी भरमाया है

सवा अरब की आबादी वाले इस महान देश की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो हाथ आज तक इसे बनाते, सजाते और संवारते आए हैं, व्यवस्था ने उन्हें बिसार दिया है. यूं तो शाश्वत सत्य है कि नींव की ईंटों की कभी कहीं गिनती नहीं होती, भवन के कंगूरे ही श्रेय के अधिकारी मान लिए जाते हैं. लेकिन मुकुल के अंदर बैठा कवि व्यवस्था की इस मनमर्जी को स्वीकार नहीं करता, वह देश की तरक्की-ख़ुशहाली में मज़दूरों, कामगारों एवं किसानों के योगदान पर रोशनी डालते हुए कहता है-

हमने भी जां गवाई है इस मुल्क की खातिर
हमने भी सौ सितम सहे इस देश के लिए

समीक्ष्य कृति : उजाले का अंधेरा (काव्य संग्रह)
रचनाकार : मुकुल सरल
प्रकाशक : कश्यप प्रकाशन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
मूल्य : 190 रुपये

ये बात अलग हम किसी वर्दी में नहीं थे
कुर्ते में नहीं थे, किसी कुर्सी पे नहीं थे

****

सड़कें बिछाई हमने, ये पुल बनाए हैं
नदियों को खींचकर तेरे आंगन में लाए हैं
खेतों में हमारे ही पसीने की महक है
शहरों में हमारी ही मेहनत की चमक है

कभी-कभी न चाहते हुए भी हम प्रकृति से, ख़ुद से और समाज से कटे-कटे से रहते हैं, जैसे बंद गली का आख़िरी मकान. वह कटा होता नहीं है, सिर्फ़ दिखता है. दूसरों को नहीं, ख़ुद उसे लगता है कि वह सबसे अलग है. यही उसकी पीड़ा भी है. ऐसे में मुकुल उसकी आवाज़ बनने और उसकी व्यथा कहने का प्रयास करते हैं-

जहां सारी उम्मीदें दम तोड़ दें
जहां सपने भी आकर संग छोड़ दें
दिन अकेला हो, सहमी सियाह रात हो
सिर्फ़ सन्नाटा हो, गम की बारात हो
मत बनना, ऐसा बियावान मत बनना
बंद गली का आख़िरी मकान मत बनना

कहते हैं, संघर्ष का ही दूसरा नाम जीवन है. भूख, ग़रीबी और अभाव आगे बढ़ने के क्रम को अक्सर बाधित करते हैं. यही वजह की कई ख्वाइशें रोटी से शुरू होकर रोटी पर ही ख़त्म हो जाती हैं. जीवन की पहली ज़रूरत रोटी विकास के हर सपने का रंग धूमिल कर देती है, लेकिन कवि चाहता है कि उसने जो अनापेक्षित देखा-भोगा, उसे देश की अगली पीढ़ी न देखे-भोगे. यहां मुकुल ने अपनी बेटी सखी को अगली पीढ़ी के प्रतिनिधित्व के तौर पर सामने रखते हुए कामना की है-

चाहता हूं/मेरी बेटी कहे
चांद को चांद
अपनी तो उम्र बीती
चांद को रोटी समझते

मुकुल की यह पहली कृति है. वह मूलत: शायर हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जन्मे, पले-बढ़े हैं, जिसने देश को दुष्यंत कुमार और निश्तर खानकाही जैसे इंकलाबी शायर दिए. शायद इसीलिए शायरी और इंकलाब मुकुल के स्वभाव का हिस्सा बन गए. कवि तो वह बाद में हुए. जैसा कि मैंने पहले कहा, कविता की कोई शास्त्रीय परिभाषा नहीं होती, जीवन का हर रंग ख़ुद में एक कविता है. इस लिहाज़ से, काव्य शिल्प के दायरों से परे हटकर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उजाले का अंधेरा न केवल पठनीय है, बल्कि उसने ख़ुद में वे संदेश छिपा रखे हैं, जिनकी हमें, आपको और सबको बहुत ज़रूरत है.

m_awdhesh@chauthiduniya.com

किताब मिली

पुस्तक का नाम
आगे अंधी गली है

लेखक
प्रभाष जोशी

प्रकाशक
राजकमल प्रकाशन

मूल्य
350 रुपये

इस किताब में स्वर्गीय प्रभाष जोशी जी के अंतिम दो वर्षों में लिखे गए लेख शामिल हैं.

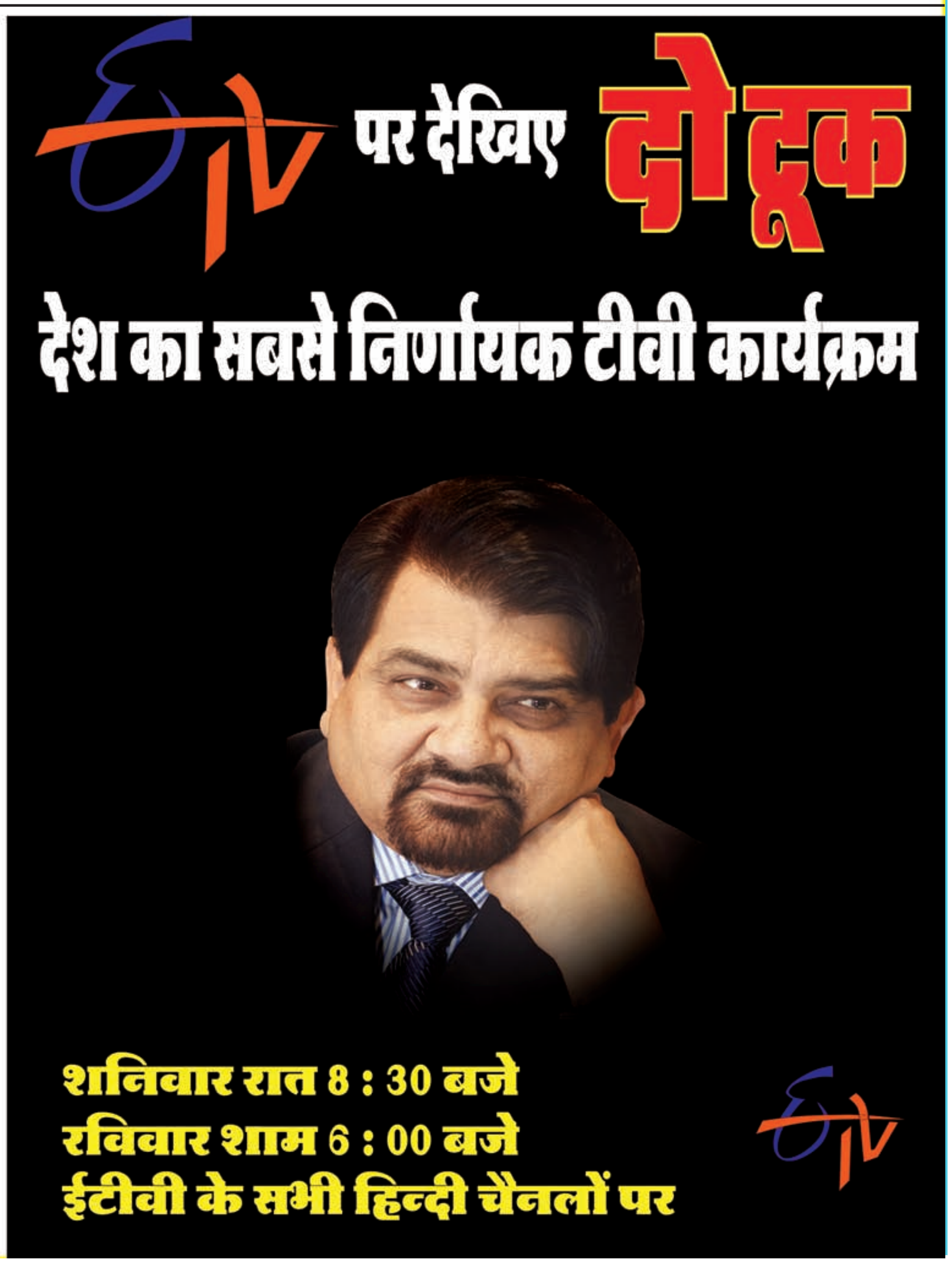

भारत में इन उत्पादों के लांच के साथ ही पर्सनल कंप्यूटर डिस्प्ले मार्केट में फिलिप्स पहले पायदान पर पहुंचने की दिशा में अग्रसर है.

छोटी कार ब्रियो

जापानी कार कंपनी होंडा मोटर्स ने भारत में अपनी छोटी कार ब्रियो का उत्पादन शुरू कर दिया है. कंपनी के ग्रेटर नोएडा स्थित प्लांट में हाल में ही पहली कार का निर्माण हुआ. अब धीरे–धीरे इसका उत्पादन बढ़ाया जा रहा है. जापान में आई भयंकर सुनामी से होंडा को वहां काफी परेशानी उठानी पड़ी और कुछ समय तक उत्पादन भी बंद रहा, लेकिन भारत में उसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि कंपनी ज़्यादातर पुर्जे भारत में ही बनाती है. यह समस्या महंगी कारों के निर्माण में ज़रूर आई, जिनके पार्ट्स बड़े पैमाने पर आयातित होते हैं.

ब्रियो थाईलैंड में लांच हो चुकी है और इसे अब भारत में उतारने की तैयारी है. यह कार सितंबर में भारत में लांच कर दी जाएगी. इस कार की खासियत है कि यह 1200 सीसी की होगी और एक लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर का औसत देगी. कहा जा रहा है कि होंडा चीफ स्वयं इस कार की क़ीमत घोषित करेंगे. फिर भी अंदाज़ा है कि यह चार से पांच लाख रुपये के बीच होगी. यह कार मारुति की स्विफ्ट, हुंडई की आई–20 और टोयोटा की एल्टिस को टक्कर देगी.

रंग-बिरंगे पावर स्ट्रिप

बिजली आपूर्ति में उतार-चढ़ाव से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डाटा को नुक़सान हो सकता है. इसलिए जेब्रोनिक्स ने अपनी अनूठी उन्नत डिज़ाइन का उपयोग इन चिंताओं के निराकरण के लिए किया है.

जेब्रोनिक्स ब्रांड नाम से कंप्यूटर और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद एवं उपस्कर बनाने वाली भारतीय कंपनी टॉप नॉच इंफोट्रॉनिक्स ने प्रीमियम पावर स्ट्रिप–पावर ग्रिप (दि प्लेटिनम सीरीज) की एक नई रेंज पेश की है. जेब्रोनिक्स पावर स्ट्रिप्स को सुंदर ढंग से डिज़ाइन किया गया है और इसमें उपयोग की सुविधा, फंक्शनलिटी और पोर्टेबिलिटी का ख्याल रखा गया है. उच्च तकनीक से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बिजली की मांग बढ़ रही है, कई तरह की समस्याएं भी बढ़ रही हैं. ऐसे में बिजली आपूर्ति में उतार–चढ़ाव से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डाटा को नुक़सान हो सकता है. इसलिए जेब्रोनिक्स ने अपनी अनूठी उन्नत डिज़ाइन का उपयोग इन चिंताओं के निराकरण के लिए किया है. उसने उच्च गुणवत्ता और कंपोनेंट का विशेष ध्यान रखा, ताकि संपूर्ण सुरक्षा मुहैया कराई जा सके और बिजली उपकरण लंबे समय तक चलें, भले ही बिजली अक्सर जाती हो या बहुत कम समय तक रहती हो. इनमें टिन के साथ कॉपर अलॉय का इस्तेमाल किया गया है और फॉस्फोरस की मात्रा अच्छी–खासी है. इससे सॉकेट कांटैक्ट मज़बूत होता है, बिजली से जुड़े ख़तरे बेहद कम हो जाते हैं. इसके कांटैक्ट पर निकिल की परत चढ़ी हुई है और यह क्षरणरोधी है. इससे उपयोगकर्ता को उपयुक्त कनेक्शन और प्लग होल्ड के लिए सॉकेट से छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इतना ही नहीं, सॉकेट को इतने लचीले ढंग से डिज़ाइन किया गया है कि इसका उपयोग दुनिया भर में सुविधाजनक ढंग से किया जा सकता है, क्योंकि यह हर तरह के प्लग की आवश्यकता पूरी करता है. उच्च गुणवत्ता और सुरक्षा के अलावा ये पावर स्ट्रिप स्टाइल वाले हैं. काले सफेद के साथ–साथ सफेद और रंगीन स्ट्रिप के मॉडल चौंकाने वाले हैं. पावर ग्रिप के तीन मॉडल हैं, जिनमें 4, 5 और 6 सॉकेट हैं. ये सभी तीनों मॉडल जेट ब्लैक, पर्ल व्हाइट और सोबर व्हाइट कलर में उपलब्ध हैं. ये पावर स्ट्रिप ऐसे हैं कि इनमें रंगों के एक अच्छे पैटर्न के साथ–साथ उच्च गुणवत्ता वाले डिज़ाइन भी हैं. इससे ये देखने में अच्छे लगते हैं. इसके अलावा सिल्क प्रिंटिंग से पावर स्ट्रिप की फिनिशिंग अनूठी है. जेब–4 पीएस एवं जेब–4 पीएस (प्लस) की क़ीमत 300 और 350 रुपये है, जबकि जेब–5 पीएस सुपर एवं जेब–5 पीएस सुपर (प्लस) की क़ीमत 375 और 425 रुपये है. जेब–6 पीएस एवं जेब–6 पीएस प्लस की क़ीमत 450 और 500 रुपये है.

फिलिप्स के नए मॉनिटर

इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बनाने वाली चीन की कंपनी मल्टीमीडिया डिस्प्ले ने फिलिप्स के साथ मिलकर भारतीय बाज़ार पर क़ब्ज़ा जमाने का मन बना लिया है. कंपनी ने फिलिप्स एलसीडी, एलईडी मॉनिटर और मॉनिटर टीवी भारतीय बाज़ार में उतारा है. इस सीरीज में कंपनी ने चार एलसीडी और पांच एलईडी कंप्यूटर मॉनिटर शामिल किए हैं. इस श्रेणी में कई स्क्रीन साइज़ के कंप्यूटर मॉनिटर हैं, जो 4600 से लेकर 9500 रुपये तक की रेंज में उपलब्ध हैं. कंपनी की सिंगापुर ब्रांच के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि भारत में इन उत्पादों के लांच के साथ ही पर्सनल कंप्यूटर डिस्प्ले मार्केट में फिलिप्स पहले पायदान पर पहुंचने की दिशा में अग्रसर है. उन्होंने कहा कि भारतीय बाज़ार फिलिप्स के रूप में उच्च गुणवत्ता, अच्छी डिज़ाइन और नवीन प्रौद्योगिकी अपनाने के अनुकूल है. चाइना आधारित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरर टीपीवी तकनीक के लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत मल्टीमीडिया डिस्प्ले नामक कंपनी ने फिलिप्स के एलसीडी, एलईडी मॉनिटर और मॉनिटर टीवी एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेचने का समझौता किया है. भारत में कंपनी के डायरेक्टर गौतम घोष के मुताबिक़, फिलिप्स ब्रांड यहां के बाज़ार में काफी लोकप्रिय है. भारत में फिलिप्स के नेटवर्क को केवल मज़बूत करने की ज़रूरत है, जो यहां क्षेत्रीय स्तर पर जाकर काम करने से संभव हो सकता है. कंपनी के उत्पादों का आधुनिकीकरण बाज़ार की मांग पर आधारित है. आने वाले वक़्त में कंपनी आईटी डिस्प्ले स्पेस के क्षेत्र में नए उत्पाद बाज़ार में उतारेगी और अनुमान के तौर पर तब तक भारत में कंपनी के क़रीब 5000 सेल्स आउटलेट्स हो जाने की संभावना है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

स्मार्ट टीवी की पेशकश

एलजी ने भारत में दुनिया की पहली 3 डी टी वी, जो दर्शकों को एक झिलमिलाहट रहित टीवी देखने का मौक़ा देती है. अब एलजी ने 3 डी टीवी के माध्यम से अपने घर में 3 डी पैटर्न में टीवी देखने का अनुभव देगा. स्मार्ट टीवी के दो मॉडल एलडब्ल्यू 6500 और एलडब्ल्यू 5700 के रूप में अपने ग्राहकों को कंपनी ने थ्री डी अनुभव को प्राप्त करने का मौक़ा दिया है. इन ख़ास टेलीविज़न मॉडल की क़ीमत 95,000 और 1,65,000 हैं. हालांकि इन स्मार्ट टीवी के आकार में भिन्नता है, थ्री डी टीवी मॉडल एलडब्ल्यू 6500 बाज़ार में 42 से 47 इंच में और एलडब्ल्यू 5700 42–55 इंच में बाज़ार में उपलब्ध है. एलजी ने इन दोनों स्मार्ट टीवी मॉडलों में अपनी विशेष तकनीक एफपीआर (फिल्म पैटनर्ड रिटाडर्ड) शामिल किया है. यह तकनीक दर्शक को 2 डी तकनीक को थ्री डी तकनीक में परिवर्तित करने की अनुमति देता है. एलजी से उन्नत एफपीआर तकनीक की मदद से दर्शक सिनेमा को बिना किसी विजुअल कमी के थ्री डी तकनीक को एंज्वॉय करने का मौक़ा देता है, जिसके परिणामस्वरूप टीवी दर्शक को आंखों की थकान और चक्कर आने की शिकायत होती है. एलजी को यूरोप आधारित एजेंसियां इंटरटेक और टीयूवी से फ्लिकर फ्री सर्टिफिकेट यानी झिलमिलाहट मुक्त प्रमाणीकरण प्राप्त हो चुका है.

इन मॉडलों की अतिरिक्त सुविधाओं में वेब ब्राउज़र, वाई–फाई तकनीक, विंडोज 7 प्रमाणित, वायरलेस एचडी, चित्र और ध्वनि मोड, एलजी ऐप्लीकेशन स्टोर, यूएसबी, ट्विटर, यूट्यूब, फ्लिकर, और स्टैंड के साथ मिलने वाला टीवी है. एलजी ने हंगामा, एनडीटीवी इंडिया टाइम्स, और दूसरों चैनल्स के साथ टाई अप किया है. अपने प्रारंभिक तौर पर थ्रीडी टीवी अलग अलग क़ीमतों पर सत्रह मॉडल लांच कर रही है, एक ख़ास बात यह भी है कि थ्री डी को बेहतर और सहज तरीक़े से देखने के लिए 3 डी चश्मे में ही शामिल हैं. हालांकि एलजी ने लांच पर 3 डी चश्मे के चार सेट की पेशकश भी कर दी है.

नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में टाईमैक्स की नई घड़ियों की लॉचिंग के अवसर पर अभिनेत्री कंगना राणावत.

नेत्रहीनों के लिए फोन

इंटेक्स टेक्नोलॉजी ने नेशनल एसोसिएशन के साथ मिलकर नेत्रहीन लोगों के लिए एक ख़ास मोबाइल फोन डिज़ाइन किया है. नया इंटेक्स स्मार्ट मोबाइल फोन विजन डुअल सिम वाला है, जिसमें दो जीएसएम सिम लग सकते हैं. इसमें ब्रेल की–पैड लगाए गए हैं, जिससे नेत्रहीन लोगों को की–पैड पहचानने में आसानी हो. इस स्मार्ट फोन में टॉकिंग की–पैड भी है, जो डिजिट्स को अंग्रेजी में बोलता है. ख़ास फीचर यह है कि इसमें चार नंबरों को सेव करने और सिर्फ़ एसओएस बटन पुश करके कॉल की सुविधा दी गई है. एसओएस बटन मोबाइल फोन के पीछे वाले हिस्से में दिया गया है. इसे दबाने से सबसे पहले फीड गए इमर्जेंसी नंबर पर कॉल लग जाएगी. इंटेक्स टेक्नोलॉजी के टेलीकॉम विभाग के डीजीएम शैलेंद्र झा ने कहा कि आसान और किफायती तकनीक के ज़रिए नेत्रहीनों का जीवन स्तर बेहतरीन बनाने का प्रयास किया गया है. उन्होंने कहा कि इंटेक्स विजन मोबाइल वायरलेस एफएम, रेडियो, ऑडियो प्लेयर, ऑटो कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल ट्रैकर एवं फ्लैश लाइट जैसे फीचर्स से लैस है. इस फोन की मेमोरी 2 जीबी तक एक्सपेंडेबल है, जो ऐसे विद्यार्थियों की पढ़ाई आसान बनाती है, जिन्हें एजुकेशनल मैटेरियल की ज़रूरत होती है. फोन में ऑरेंज टोन बियरिंग बैकेट है, जो आंशिक रूप से दृष्टिहीन लोगों को प्रभावित नहीं करता. भारत के नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड और इंटेक्स ने यह फोन विद्यार्थियों के बीच लांच किया. इस ख़ास फोन की क़ीमत लगभग 2900 रुपये है.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

आईपीएल में गर्व और देशभक्ति जैसी कोई बात नहीं जुड़ी है. आप यहां एक शहर की किसी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं.

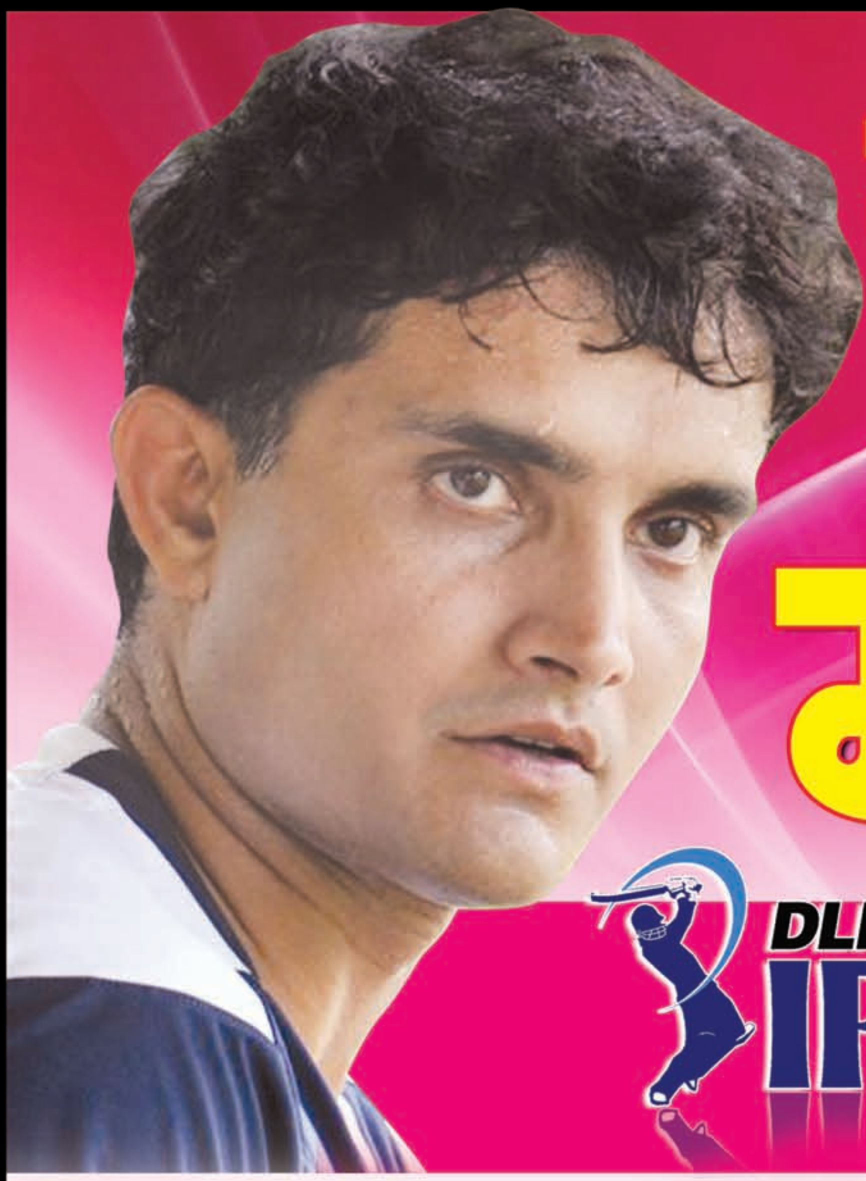

सौरव की वापसी के मायने

DLF IPL

पुणे वारियर्स के टीम निदेशक अभिजीत सरकार ने कहा कि गांगुली को लेना कोई जुआ नहीं है. उन्होंने कहा कि भारत में गांगुली जैसा क्रिकेट का जानकार कोई और नहीं है और वह अपनी उपयोगिता साबित कर देंगे. अजीब बात है, अभिजीत सरकार को उनकी उपयोगिता इतनी जल्दी समझ में आ गई. लगता है, यह बात नेशनल टीम के चयनकर्ताओं को नहीं सूझी.

राजेश एस कुमार

बंगाल टाइगर, दादा, बाबू मोशाय और सौरव गांगुली, ये सारे नाम उस शख्स के हैं, जिसका एक दौर में भारतीय क्रिकेट पर ऐसा दबदबा था कि लोग बोलते थे कि यह भारतीय क्रिकेट टीम का अब तक का सबसे सफल और शानदार कप्तान है. लेकिन यह उगता हुआ सूरज इतनी जल्दी अस्त होगा, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था. अर्श से फ़र्श और फ़र्श से अर्श तक के सफ़र के सही मायने दादा से बेहतर कोई और नहीं समझ सकता है. कप्तानी से हटने के बाद फ़र्श तक पहुंचना और कमेंट्री करने से लेकर आईपीएल 4 के अंतिम दौर में बतौर उपकप्तान वापसी करना, फिर से अर्श तक पहुंचने की जद्दोजहद की अजीब दास्तां है. कल तक युवराज जैसे कई युवा प्रतिभाओं को निखारने वाला यह खिलाड़ी आज उसी की कप्तानी में खेलने को मजबूर है. इसे मजबूरी कहें या सीमित विकल्प, लेकिन दादा ख़ुद को किस किनारे स्थापित करना चाहते हैं, इस पर संशय बरक़रार है. कभी उनके लिए कहा जाता है कि दादा अब क्रिकेट को अलविदा कहने की पोजीशन में हैं तो कभी वह आईपीएल जैसी फ़टाफ़ट श्रंख्ला में वापसी कर अपने अंदर बचे हुए हुनर को सबके सामने लाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं, जैसे वह यह साबित करने की कोशिश कर रहे हों वह अभी तक चुके हुए साबित नहीं हुए हैं. इतने बड़े क्रिकेटर की वापसी क्या ऐसी होनी चाहिए थी. क्या सौरव अब इतने मजबूर हो गए हैं कि उन्हें किसी के रहमो–करम की ज़रूरत है. जब उन्हें शुरुआत में आईपीएल में शामिल करने के लायक़ नहीं समझा गया तो अब उन्हें शामिल नहीं होना चाहिए था.

जब वर्ल्ड कप के दौरान सौरव कमेंट्री कर रहे थे, उस वक़्त सब ठीक नहीं था, क्योंकि उससे पहले ही आईपीएल 4 के संभावित खिलाड़ियों की सूची में उनका नाम नहीं था. पहले और तीसरे सत्र में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान रहे गांगुली को 10 में से किसी फ्रेंचाइजी ने नीलामी में नहीं ख़रीदा था. फिर अचानक से सहारा पुणे वारियर्स उन्हें आईपीएल के अंतिम दौर में शामिल करता है. यहीं पर मामला अटक जाता है. आख़िर उस प्लेयर का क़द इसी बात से मापा जा सकता है कि जिस पर किसी ने भी बोली न लगाई हो, उसे मजबूरी में कहें या फिर ज़रूरत पड़ने पर शामिल किया जाता है. क्या इस क़द में दादा फिट बैठते हैं. हालांकि यहां पर इस बात पर ग़ौर कर सकते हैं कि दादा ने इस चयन पर ख़ुद अपनी स्वीकृति दी है.

अब दादा ने यह फ़ैसला किस तरह लिया है, यह तो वह ही बता सकते हैं, लेकिन प्रशंसकों और उनके आलोचकों के लिए यह चर्चा का विषय ज़रूर हो सकता है कि क्या उन्हें क्रिकेट खेलने की चाह ने इस फ़ैसले पर हांमी भरने को प्रेरित किया, या फिर आईपीएल में मिलने वाली रक़म ने. इतना तो तय है कि यह फ़ैसला उन्होंने देश के लिए खेलने की ख़ातिर तो लिया नहीं है, क्योंकि देश के लिए खेलने की चाहत को आईपीएल में खेलने से जोड़ कर नहीं देखा जा सकता. हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वह एक दिन देश के लिए खेले. देश के लिए खेलने की चाहत में कहीं न कहीं गर्व और देशभक्ति की भावना जुड़ी रहती है और ऐसे में यदि कोई फिट खिलाड़ी 40 की उम्र में भी राष्ट्रीय टीम में शामिल होने के लिए कोशिश करता है तो तब उसकी भावनाओं को समझा जा सकता है. लेकिन यहां आईपीएल में गर्व और देशभक्ति जैसी कोई बात नहीं जुड़ी है. आप यहां एक शहर की किसी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं. और तो और कई खिलाड़ियों के जन्म स्थान और फ्रेंचाइजी टीम में कोई रिश्ता भी नहीं है.

बहरहाल दादा ने युवराज की कप्तानी में उस टीम की ओर से खेलने का फ़ैसला लिया जो पहले से ही प्वाइंट रैंकिंग में फिसड्डी बनी हुई है. पुणे की डूबती नैया को पार लगाने के लिए अब टीम में उन्हें शामिल किया गया है, लेकिन चोटी की टीम को मात देने के लिए टीम को हर दृष्टि से बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, जो वारियर्स के लिए इतना आसान नहीं होगा. इस टीम ने टूर्नामेंट में अब तक शुरुआती दो मैचों को छोड़कर लगभग सभी में हार का मुंह देखा है. हालांकि दादा मुंबई इंडियंस के ख़िलाफ़ हुए मैच में मैदान पर नहीं उतरे. उस मैच में भी पुणे को मुंबई के हाथों पिटना पड़ा. युवराज सिंह की कप्तानी वाली पुणे वारियर्स लगातार छह मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर है. फ्रेंचाइजी को उम्मीद है कि अपार अनुभव रखने वाले गांगुली के आने से उनकी बल्लेबाज़ी मज़बूत होगी. पुणे वारियर्स के टीम निदेशक अभिजीत सरकार ने कहा कि गांगुली को लेना कोई जुआ नहीं है. उन्होंने कहा कि भारत में गांगुली जैसा क्रिकेट का जानकार कोई और नहीं है और वह अपनी उपयोगिता साबित कर देंगे. अजीब बात है, अभिजीत सरकार को उनकी उपयोगिता इतनी जल्दी समझ में आ गई. लगता है, यह बात नेशनल टीम के चयनकर्ताओं को नहीं सूझी. हालांकि यह पहला मौक़ा नहीं है जब दादा को इस तरह से दरकिनार कर टीम से बाहर किया गया हो. इससे पहले भी कप्तान सौरव गांगुली को अच्छे प्रदर्शन के बावजूद एक दिवसीय टीम से बाहर किया गया था. इस बात का दर्द उन्हें अब भी सालता है. एक दिवसीय टीम से बाहर किए जाने के बारे में यदि गांगुली से कोई पत्रकार ज़रा सा भी कुछ पूछता है तो उनके दिल का दर्द जैसे बाहर निकल आता है और वह अपने मन की बात दबा नहीं पाते हैं. गांगुली कहते थे कि मैं नहीं जानता कि वनडे टीम में वापसी के लिए आख़िर क्या करूं. वह यह भी कहते थे कि मुझे यह भी नहीं पता कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अच्छा प्रदर्शन करने पर क्या मुझे भारतीय वनडे टीम में जगह मिल पाएगी. उनका मानना था कि फॉर्म में होने के बावजूद उन्हें ऑस्ट्रेलिया में हुई एक दिवसीय मैचों की कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज के लिए चुनी गई भारतीय टीम से हटा दिया गया था. उन्होंने कहा कि एक साल में क़रीब 1300 रन बनाने के बावजूद मुझे टीम में जगह नहीं दी गई. यह बात तब की है जब दादा को बुरी तरह से घेरकर टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, लेकिन उसके बाद उनके जख्मों पर मलहम लगाते हुए शाहरुख़ ने अपनी कोलकाता नाइट राइडर्स में उन्हें बतौर कप्तान चुना. ऐसा लगा जैसे इस बार दादा ज़ोरदार वापसी करेंगे, लेकिन शुरुआत में सब ठीक चलने के बाद अचानक पता नहीं क्या हुआ कि चौथे सीजन से उनका पत्ता साफ़ हो गया. सबसे गंभीर बात तो यही थी कि किसी भी फ्रेंचाइजी ने उन पर भरोसा नहीं जताया.

सरकार कहते हैं कि वह पैसे के लिए आईपीएल नहीं खेल रहे हैं, बल्कि उन्हें कुछ साबित करना है. वह काफ़ी सम्मान के हक़दार हैं, लेकिन उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया. वह यह भी कहते हैं कि उनकी टीम कई खिलाड़ियों की फिटनेस समस्या से जूझ रही है. लिहाज़ा उन्होंने गांगुली के बारे में सोचा. टूर्नामेंट की शुरुआत में ही एंजेलो मैथ्यूज बाहर हो गए जो सर्वश्रेष्ठ ऑल राउंडर थे. आस्ट्रेलियाई टी 20 के उपकप्तान टिम पेन, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ग्रीम स्मिथ भी चोटिल हैं. आशीष नेहरा भी फिट नहीं है. हम नेहरा की फिटनेस रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे थे. टीम प्रबंधन का मानना है कि गांगुली सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध विकल्प हैं. वह जुझारू हैं और वापसी के बादशाह भी. हमें यक़ीन है कि वह अपनी उपयोगिता साबित करेंगे.

इससे पहले दादा को लेकर आईपीएल में अटकलों का बाज़ार काफ़ी गर्म था. कहा जा रहा था कि वह कोलकाता की टीम में बतौर कोच भी हिस्सेदारी ले सकते हैं, लेकिन इस बात से सभी वाक़िफ़ थे कि कल तक एक–दूसरे को गले लगाकर खेलबो लड़बो, जीतबो एंथम गाने वाले दादा और शाहरुख़ के बीच अब पहले जैसी बात नहीं रही है. दोनों की दोस्ती में दरार तभी पड़ गई थी जब दो बार कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करने के बाद आईपीएल के चौथे संस्करण में शाहरुख़ ने दादा को अपनी टीम में शामिल करने के लायक़ ही नहीं समझा. आपको याद होगा कि इस बात पर बंगाल में दादा के प्रशंसकों ने शाहरुख़ के ख़िलाफ़ जमकर प्रदर्शन भी किया था. इसके अलावा एक ख़ास तबक़े में भी दादा को दोबारा कोलकाता में न शामिल करने के कारण शाहरुख़ को काफ़ी लोगों की आलोचना सहनी पड़ी थी. हालांकि इसके बाद भी शाहरुख़ दुनिया भर में इस बात का ढोल पीटते रहे कि दादा आज भी उनके क़रीब हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, यह सभी जानते हैं. कुछ वरिष्ठ खिलाड़ी सौरव के इस फ़ैसले पर कुछ अलग ही राय रखते हैं. कुछ लोगों का मानना है कि नीलामी में नहीं ख़रीदे जाने के बाद गांगुली ने खिलाड़ी के तौर पर इसे अपने क्रिकेट करियर का अंत मान लिया होगा, लेकिन उसके बाद जब अचानक उन्हें पुणे में शामिल होने का ऑफर मिला तो उन्होंने इसे एक मौक़े के तौर पर लिया होगा यानि उन्हें अब फिर नए सिरे से शुरुआत करनी होगी. उन्हें उस टीम की नैया पार लगाने की ज़िम्मेदारी दी गई है, जो लगभग डूबने की कगार पर है. फ्रेंचाइजी और गांगुली ने सोच समझ कर निर्णय लिया होगा, लेकिन इस फ़ैसले ने मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अपना बेहतरीन क्रिकेट खेल चुकने और क्रिकेट से बहुत दिनों दूर रहने के बाद वापस इससे जुड़ना क्या बद्धिमत्ता वाला निर्णय कहा जा सकता है?

सौरव को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनकी टीम के बल्लेबाज़ी कोच बनने का प्रस्ताव दिया है. बांग्लादेश बोर्ड ने इस ख़बर की पुष्टि भी कर दी है कि वह दादा को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं. जल्द ही वह दादा को एक औपचारिक पत्र भेजेंगे. बांग्लादेश बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद जलाल यूनुस के मुताबिक़ वह दादा की क़ाबिलियत का लाभ उठाना चाहते हैं. इससे पहले क़यास लगाए जा रहे थे कि वह कोच्चि टीम की कप्तानी संभाल सकते हैं. उनका यह सपना सच भी हो जाता अगर श्रीलंका के खिलाड़ी वापस अपने देश लौट जाते. इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ़ एक बात पोजिटिव यह रही कि अब दादा के प्रशंसक एक बार फिर से उन्हें मैदान में देख सकेंगे. आख़िरकार लंबे समय से लग रहे सभी क़यासों पर विराम लगा है. इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि सौरव के टीम में शामिल होने से पुणे टीम में अनुभव की कमी दूर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सहारा को यह फ़ैसला लेने में कुछ ज़्यादा ही वक़्त लग गया. इसके अलावा जिस तरह का रवैया दादा को लेकर अब तक अपनाया जाता रहा है, उसे देखते हुए तो दादा को इतनी जल्दी फ़ैसला नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि पता नहीं कब शाहरुख़ की तरह सहारा भी किसी सीजन में उनसे अपना पल्ला झाड़ ले, तब दादा कहां जाएंगे.

rajeshy@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

अपने बैनर का नाम भीगी बसंती एंटरटेनमेंट रखने के बारे में वह कहती हैं कि प्रोडक्शन हाउस शुरू करने का फ़ैसला अचानक हुआ.

दादा साहब फाल्के अवार्ड
...एक बार फिर भुला दिए गए प्राण

सुषमा गुप्ता

वर्ष 2010 का दादा साहब फाल्के अवार्ड वरिष्ठ फिल्मकार के बालाचंदर को दिया जाएगा. वह पिछले 45 सालों से सिनेमा जगत में सक्रिय हैं. बालाचंदर को इस अवार्ड के लिए चुने जाने का मतलब है कि 91 वर्षीय प्राण को इस बार भी यह अवार्ड नहीं मिला. दादा साहब फाल्के सम्मान सिनेमा जगत में अविस्मरणीय योगदान के लिए दिया जाता है, लेकिन 60 से ज़्यादा साल तक अभिनय करने वाले उस कलाकार के योगदान को ज्यूरी के सदस्य अविस्मरणीय नहीं मानते, जिन्हें फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाओं का सशक्त हस्ताक्षर कहा जाता है. शुरुआत के केवल 20 साल, जबकि वह बड़े हो रहे थे, छोड़ दिए जाएं तो उनका पूरा जीवन फिल्मी इंडस्ट्री को समर्पित रहा. चालीस साल हो गए, प्राण को फिल्मों में खलनायकी छोड़े, पर आज भी भारतीय सिनेमा में जब खलनायक का ज़िक्र आता है तो ज़ेहन में सबसे पहला नाम प्राण का ही आता है. यह उनके अभिनय का जादू नहीं तो और क्या है!

हिंदी फिल्मों में खलनायकी के ज़रिए प्राण ने अभिनय को एक नई ऊंचाई बख्शी. प्राण फिल्मी दुनिया में उस वक़्त से सक्रिय हैं, जब भारतीय सिनेमा अपनी पहचान बना रहा था. वर्ष 1940 में पंजाबी फिल्मों से प्राण का सिनेमाई सफर शुरू हुआ था. यमला जट नामक पंजाबी फिल्म में उन्होंने खलनायक की भूमिका अदा की थी. उस वक़्त वह लाहौर में रहकर काम करते थे. इसके दो साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वह नायक बनकर उतरे, फिल्म थी खानदान. इस फिल्म में उनके अपोज़िट थीं नूरजहां. तब नूरजहां की उम्र महज़ 13-14 साल की थी. फिल्म हिट रही. इसके बाद तो उनके पीछे निर्माताओं की लाइन लग गई. उन्हें फिल्मों में नायक की भूमिकाएं मिलने लगीं, पर नायक की भूमिकाएं उन्हें ज़्यादा रास नहीं आ रही थीं. इसकी वजह थी कि नायक के पास करने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं था, सिर्फ़ हीरोइन के साथ पेड़ के इर्द-गिर्द चक्कर लगाने और नाच-गाने के अलावा. लिहाज़ा उन्होंने फिर से खलनायकी शुरू की. उनका करियर तेजी से आगे बढ़ ही रहा था कि देश को विभाजन की त्रासदी झेलनी पड़ी और वह लाहौर से मुंबई आ गए. छह महीने तक मुफलिसी और संघर्ष के दौर के बाद प्राण को काम मिला देवानंद और कामिनी कौशल की फिल्म ज़िद्दी में. उनका शानदार अभिनय देखकर हिंदी फिल्मों के निर्देशक दंग रह गए. इसके बाद एक बार फिर उनके पीछे निर्माता-निर्देशकों की लाइन लग गई.

पचास और साठ के दशक के आते-आते प्राण हिंदी फिल्मों में खलनायकी के पर्याय बन चुके थे. उनका निभाया हर किरदार लोगों के दिलों में ख़ौफ़ बनकर बैठ जाता था. किरदार की जीवंतता ऐसी कि असल ज़िंदगी में भी लोग प्राण से डरते थे. वह जहां भी जाते, लोग उनसे कन्नी काट लेते थे. एक बार वह दिल्ली में अपने किसी दोस्त के घर चाय के लिए बुलाए गए. जब वह उस दोस्त के घर पहुंचे तो उसकी बहन उन्हें देखते ही वहां से खिसक ली. बाद में उनके मित्र ने फोन पर उन्हें बताया कि उसकी बहन उससे लड़ रही थी कि वह इतने बुरे आदमी को घर में क्यों लेकर आए. पचास के दशक के बाद आलम यह था कि लोगों ने अपने बच्चे का नाम प्राण रखना बंद कर दिया.

उस दौर में देवानंद की शोहरत का मुक़ाबला सिर्फ़ प्राण ही कर सकते थे. फ़र्क़ सिर्फ़ इतना कि यह शोहरत देवानंद को प्यार के रूप में मिली और प्राण को नफ़रत के रूप में. कहा जाता है कि देवानंद जहां भी जाते थे, लड़कियां उन्हें घेर लेती थीं और उनकी एक झलक पाने के लिए छत से भी कूदने को तैयार रहती थीं. ठीक उसी तरह प्राण जहां जाते थे, लोग रास्ता बदल लेते थे या दाएं-बाएं होकर खिसक लेते थे. ग़ौरतलब बात है कि देवानंद को यह लोकप्रियता सिर्फ़ अभिनय के बूते नहीं, बल्कि अपनी ख़ूबसूरती और ख़ास अंदाज़ की बदौलत भी मिली. जबकि प्राण ने यह लोकप्रियता सिर्फ़ अपने अभिनय के दम पर हासिल की. प्राण की यह नकारात्मक लोकप्रियता विश्व सिनेमा के इतिहास में अद्वितीय है. यह भारत ही नहीं, विश्व सिनेमा के इतिहास में बदनामी से मिली शोहरत की ऐसी मिसाल थी, जिसे कोई भी कलाकार नहीं दोहरा पाया. किरदार चाहे जैसा भी हो, उनके अभिनय के ख़ास अंदाज़ को कौन भूल सकता है. संवाद अदायगी के अपने ख़ास अंदाज़, होंठों पर तैरती कुटिल मुस्कान और अलग-अलग गेटअप के साथ प्राण ने नकारात्मक किरदारों को कुछ इस तरह पेश किया कि हर किरदार जीवंत और यादगार हो गया.

प्राण की इस कामयाबी के पीछे था अभिनय के प्रति उनका ज़बरदस्त समर्पण और लगाव. समर्पण इतना गहरा था कि पंजाबी फिल्मों में नायक के तौर पर स्थापित होने के बाद भी चैलेंजिंग रोल की खातिर उन्होंने खलनायकी की ओर रुख़ किया. हिंदी फिल्मों में ऐसा करने का साहस नायकों में उनके साठ साल बाद आया (21वीं सदी में ही हिंदी फिल्मों के नायकों ने खलनायक बनने का जोखिम उठाया). प्राण उन कलाकारों में शुमार किए जाते हैं, जो अपने किरदार पर कैमरे के सामने आने से पहले मेहनत करने में यक़ीन करते थे. पात्र के मुताबिक़ संवाद, वेशभूषा, गेटअप और उसे नया रंग देने के लिए वह बाकायदा कई-कई दिनों तक सिर्फ़ अध्ययन करते थे. चरित्र के हिसाब से ख़ुद को ढालना प्राण की पहचान रही. ख़ास गेटअप के लिए वह अख़बारों से तस्वीरें काटकर रख लिया करते थे. बाद में कोई वैसा पात्र उन्हें निभाना होता था तो वह उसके मुताबिक़ फोटो देखकर हेयर स्टाइल, मूंछें या वेशभूषा अपनाते थे. हर फिल्म में उनका अलग मैनरिज़्म होता था, अलग संवाद अदायगी होती थी. उनके द्वारा अपनाए गए स्टाइल खासे लोकप्रिय होते थे. उनके अभिनय का ही जादू था कि खलनायक होने के बावजूद उनका हेयर स्टाइल, सिगरेट पीने का अंदाज़ और चलने-बोलने का तरीक़ा ख़ूब लोकप्रिय हुआ. प्राण शायद पहले खलनायक थे, जिनकी क्रूरता और घटियापन में भी एक किस्म का आकर्षण रहता था.

खलनायक के तौर पर अपने झंडे गाड़ने के बाद उन्होंने एक बार अपनी रची खलनायक की छवि तोड़ दी. उन्होंने यह काम मनोज कुमार की फिल्म उपकार के ज़रिए किया. एक फिल्म से ही हिंदी फिल्मों का सबसे बड़ा खलनायक मलंग चाचा बन गया. इसके बाद उन्होंने कई यादगार चरित्र भूमिकाएं निभाईं. सत्तर के दशक के बाद प्राण की अमिताभ के साथ जोड़ी काफी हिट रही थी. वह कभी अमिताभ के दोस्त बनते तो कभी पिता. स्क्रीन पर जब भी इन दो महान हस्तियों का आमना-सामना हुआ, वह सीन यादगार बन गया. चाहे वह ज़ंजीर हो या फिर शराबी. इस दौर में वह फिल्मों में चरित्र भूमिकाओं के लिए ऐसी ज़रूरत बन गए कि निर्माता-निर्देशक उन्हें मन मुताबिक़ पैसे देते थे. फिल्म डॉन के लिए निर्माता ने जितने पैसे अमिताभ को डबल रोल के लिए दिए थे, उससे ज़्यादा पैसे उसे प्राण को देने पड़े थे. अगर अभिनय सिनेमा के विकास में योगदान देता है तो उनका अभिनय हिंदी सिनेमा के लिए एक बड़ा योगदान था. हैरानी की बात है कि यह महान कलाकार भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए मिलने वाले सबसे बड़े सम्मान यानी दादा साहब फाल्के अवार्ड से आज तक वंचित है.

लगता है, इस सम्मान हेतु निर्धारित मापदंड सिर्फ़ कहने के लिए हैं. सरकार को जो पसंद आता है, पुरस्कार उसे ही दिया जाता है. प्राण को अब तक यह सम्मान न मिलना इस बात का प्रमाण है. क्या इसकी वजह खलनायकी को लेकर देश के लोगों का दुराग्रह है? क्या चयन समिति और केंद्र सरकार भी इसी दुराग्रह से ग्रसित है? इस सम्मान के लिए नाम का चयन करने वाली समिति में सिनेमा जगत के दिग्गज लोग शामिल होते हैं, जिनसे उच्च कोटि की सिनेमाई समझ की अपेक्षा की जाती है. कम से कम इतनी तो ज़रूर कि कलाकार कलाकार होता है, चाहे वह नायक हो या खलनायक. प्राण ने साढ़े तीन सौ से ज़्यादा फिल्मों में यादगार अभिनय किया. भारतीय सिनेमा के हर उतार-चढ़ाव के वह भागीदार रहे. आज हम कहते हैं कि महात्मा गांधी को नोबल पुरस्कार न मिलना महात्मा गांधी की नहीं, नोबल पुरस्कार की बदक़िस्मती है. कहीं ऐसा न हो कि आने वाले दिनों में हमें यही बात प्राण और दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए कहनी पड़े.

feedback@chauthiduniya.com

लारा की भीगी बसंती

हालिया रिलीज फिल्म चलो दिल्ली से प्रोड्यूसर बनीं लारा दत्ता अपने इस क़दम को करियर का एक्सटेंशन बताती हैं. हालांकि फिल्में बनाने का फ़ैसला वह बहुत पहले कर चुकी थीं और अगर किसी स्क्रिप्ट ने उन्हें अपील किया तो वह निर्देशन के क्षेत्र में भी उतरने के मूड में हैं. यह पूछने पर कि प्रोड्यूसर बनने का फ़ैसला आपने शादी से पहले किया या बाद में, वह कहती हैं कि आप इसे किसी भी तरह ले सकते हैं. वैसे मैंने शादी से काफी पहले ही फिल्म बनाने का फ़ैसला किया था, लेकिन तब ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी, जो मुझे छू जाए. इसे इत्तेफ़ाक कहें कि शादी के तुरंत बाद मुझे अच्छी कहानी मिल गई और मैंने फिल्म बनाने का फ़ैसला कर लिया.

अपने बैनर का नाम भीगी बसंती एंटरटेनमेंट रखने के बारे में वह कहती हैं कि प्रोडक्शन हाउस शुरू करने का फ़ैसला अचानक हुआ. जब इसका नाम रखने की बारी आई तो किसी ने मुझे अपने नाम से कंपनी का नाम रखने की सलाह दी, किसी ने अंग्रेजी टाइप नाम सुझाया. इन्हीं बातों के बीच भीगी बसंती का ज़िक्र आया और झट से नाम फाइनल हो गया. मुझे लगता है कि कंपनी का यह नाम प्यारा और कैची है. लारा कहती हैं कि मॉडलिंग के बाद जब वह इंडस्ट्री में आईं तो सभी ने उन्हें पूरा सहयोग दिया. हर अच्छे-बुरे दौर में लोग उनके साथ खड़े हुए. यह सब देखकर उन्होंने तय किया कि वह इंडस्ट्री के साथ स्थायी रिश्ते बनाएंगी. यहां हीरोइन का करियर लिमिटेड होता है, इसलिए उन्होंने प्रोडक्शन से जुड़ने की सोची, लेकिन डायरेक्शन का फ़ैसला कभी नहीं किया. वह कहती हैं, अगर किसी स्क्रिप्ट ने अपील की और मुझे लगा कि मैं इसे सही तरह हैंडल कर सकती हूं तो डायरेक्शन ज़रूर करूंगी.

मॉडलिंग के बाद जब वह इंडस्ट्री में आईं तो सभी ने उन्हें पूरा सहयोग दिया. हर अच्छे-बुरे दौर में लोग उनके साथ खड़े हुए. यह सब देखकर उन्होंने तय किया कि वह इंडस्ट्री के साथ स्थायी रिश्ते बनाएंगी. यहां हीरोइन का करियर लिमिटेड होता है, इसलिए उन्होंने प्रोडक्शन से जुड़ने की सोची, लेकिन डायरेक्शन का फ़ैसला कभी नहीं किया.

महेश भूपति इंडस्ट्री से नहीं हैं, फिर वह इस फील्ड में कैसे आ गए? इस सवाल पर लारा कहती हैं कि किसने कहा कि महेश का फिल्मों से कुछ लेना-देना नहीं है. यकीन मानिए, अपने खेल के बाद महेश का सबसे ज़्यादा लगाव फिल्मों से है. मुझे जब महेश ने बताया कि उन्होंने कई हिट फिल्मों के फर्स्ट डे-फर्स्ट शो देखे हैं तो मैं हैरान रह गई. हां, उनका प्रोडक्शन वग़ैरह से कोई लेना-देना नहीं है, इसलिए हमने कंपनी का काम बांट रखा है. महेश बिजनेस एंगल और मैं क्रिएटिव एंगल देख रही हूं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

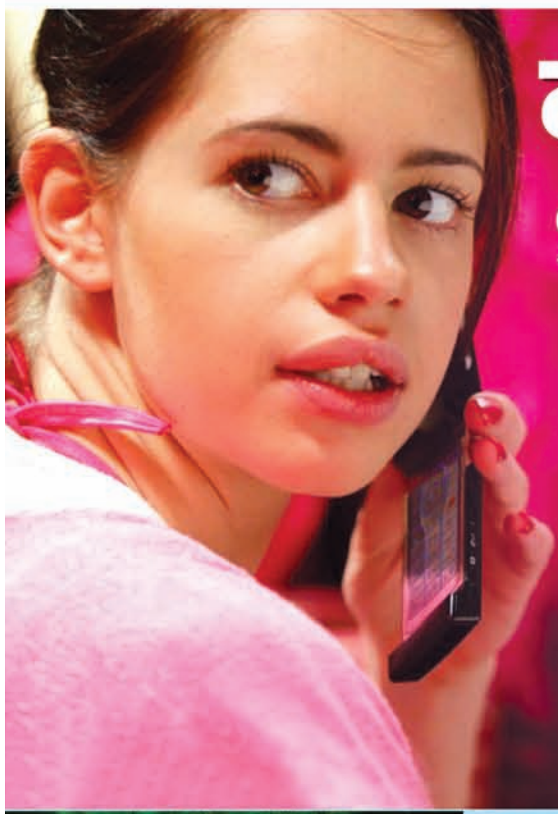

कल्कि की शादी

कल्कि ने अब अपना हमसफर पा लिया है. फिल्म प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप की लांग टाइम गर्लफ्रेंड रहीं कल्कि कोचलीन ने शादी रचा ली है. दोनों ने ऊटी में क़रीब सौ साल पुराने एक आम के पेड़ के नीचे दक्षिण भारतीय रीति-रिवाजों से एक-दूसरे का हाथ थामा. अनुराग कश्यप की यह दूसरी शादी है. इससे पहले वह आरती बजाज को भी अपना हमसफर बना चुके हैं. अनुराग की एक 10 साल की बेटी भी है. ऊटी स्थित एक छोटे से कस्बे कलहट्टी में दोनों की शादी सुबह साढ़े दस बजे शुरू हुई. दो घंटे तक चले इस विवाह कार्यक्रम में क़रीब 40 लोग मौजूद थे. शादी में अनुराग के भाई एवं सुपरहिट फिल्म दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप भी मौजूद रहे.

इस मौक़े पर कल्कि सफेद-लाल रंग की जरीदार साड़ी में थीं तो अनुराग सफेद लुंगी में नजर आए. धार्मिक श्लोकों के बीच अनुराग ने कल्कि को मंगलसूत्र पहनाया. मेहमानों को केले के पत्तों पर शाकाहारी खाना खिलाया गया. कल्कि और अनुराग अपनी आने वाली फिल्म शैतान के प्रमोशन में जुटे हुए हैं, इसलिए अभी इस जोड़े ने हनीमून पर जाने का कोई कार्यक्रम नहीं बनाया है. अनुराग की इस फिल्म में कल्कि कोचलीन मुख्य भूमिका में नज़र आएंगी.

फिल्म प्रीव्यू

भिंडी बाज़ार इंक

गौरी के कजिन रुस्तम तिवारी की शादी में शाहरुख़ के आगमन ने रुस्तम की पत्नी श्वेता वर्मा को स्पॉट लाइट में ला दिया. बहुत कम लोगों को शाहरुख़ से उनकी रिश्तेदारी के बारे में पता है. कई एड फिल्मों में काम कर चुकी श्वेता चकाचौंध से दूर रहती हैं और सिर्फ़ काम में ही रुचि दिखाती हैं. अब वह फिल्म भिंडी बाज़ार इंक में केके मेनन, प्रशांत नारायणन, दीप्ति नवल, शिल्पा शुक्ला और जेनिफ़र लोपेज़ की बहन कैटरीना लोपेज़ के साथ नज़र आएंगी. फिल्म के प्रोड्यूसर करण अरोरा हैं. श्वेता इस फिल्म में सिमरन का किरदार निभा रही हैं. वह पहले अमीरात एयरलाइंस में एयर होस्टेस थीं, उन्होंने एक्टिंग के लिए यह करियर छोड़ दिया. भिंडी बाज़ार के डायरेक्टर अंकुश भट्ट भी श्वेता के काम की प्रशंसा करते नहीं थकते. फिल्म का म्यूज़िक संदीप-सूर्या ने दिया है और गाने लिखे हैं नवीन त्यागी ने. भिंडी बाज़ार इंक एक ड्रामा थ्रिलर जॉनर की फिल्म है. फिल्म की कहानी गालिब असद भोपाली ने लिखी है और कोरियोग्राफी की है सागर दास ने. मुंबई के भिंडी बाज़ार की स्थितियों पर बनी यह फिल्म काफी अलग प्रकार की है. यह बाज़ार स्थानीय माफ़िया के इशारों पर चलता है. बाज़ार का मुख्य व्यापार पॉकेटमारी है. फिल्म की कहानी अद्वितीय है और किरदार भी रोचक हैं. यह फिल्म आगामी 20 मई को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

दिल्ली, 16 मई–22 मई 2011

www.chauthiduniya.com

थाने पर गुंडों की हुकूमत

> चेयरमैन और उनकी लॉबी के लोग थाने के सामने से होकर गुज़रने से भी डरते थे, लेकिन विधायक का संरक्षण मिलते ही वे थाने पर हुकूमत करते नज़र आने लगे. पुलिस अपने आपको बेबस और लाचार महसूस करती हुई दबी ज़ुबान में कहने लगी कि इस सरकार के बाद अन्य कोई सरकार आ गई तो इन लोगों से गिन-गिन कर बदला लिया जाएगा.

देवेंद्र कौशिक

मथुरा जनपद से अपरिचित किसी भी आई.पी.एस, अधिकारी की पोस्टिंग जब यहां होती है तो पहले तो वह अधिकारी आने से कतराता है, लेकिन जब वह चार्ज ग्रहण कर जनपद की वस्तुस्थिति से रूबरू हो जाता है तो वह यहां से जाने को तैयार नहीं होता, ऐसा क्या है मथुरा जनपद में जो अधिकारी यहां से जाने को तैयार नहीं होते! यह जानने के लिए हम मथुरा जनपद और जनपद की कमान संभाले एस.एस.पी भानु भास्कर और उनके अधीनस्थों की कारगुज़ारियों पर नज़र डालते हैं.

चार्ज संभालते ही अधिकारी की नज़र जनपद के रिफाइनरी थाना क्षेत्र निवासी ब्लैक गोल्ड के नामचीन व्यापारी मनोज तेलिया पर पड़ी. मनोज तेलिया की पार्टियों में बड़े–बड़े दिग्गज आई.पी.एस. जाने में अपनी शान समझते थे, मनोज तेलिया पर कप्तान की टेढ़ी नज़र ने उसकी पूरी अवैध सत्ता को तहस–नहस कर दिया. इस समय मनोज तेलिया जेल में बंद है. उस पर एक दर्जन से अधिक आपराधिक मुक़दमे न्यायालयों में विचाराधीन हैं. सन् 2000 में गांव बेरी में तेल के ज़ख़ीरे में लगी भीषण आग के कारण 55 लोगों की मौत हो गई थी, इसमें भी बताते हैं मनोज तेलिया का ही हाथ था. मनोज तेलिया के राजनीतिक आक़ाओं ने अनेक कोशिशें कीं कि कप्तान की वक्र दृष्टि सीधी हो जाए, पर उन्हें सफलता नहीं मिली. उन्होंने देखा कि कप्तान किसी को भाव नहीं दे रहा. कप्तान ईमानदार है और बहुत जल्द ही प्रमोशन लेकर डी.आई.जी बनने वाला है और जाने से पहले मथुरा जनपद में अपराध और ग़ैरक़ानूनी धंधों को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर देना चाहता है. इसलिए कप्तान को नुक़सान पहुंचाने के लिए इन राजनीतिज्ञों ने अपना जाल बुनना शुरू किया. इसकी भनक जब कप्तान को लगी तो उन्होंने भविष्य की परेशानियों के मद्देनज़र ज़्यादा पंगा लेना उचित नहीं समझा. फिर तो कप्तान की ईमानदारी के नाम पर अवैध कारोबारियों के भाव और भी बढ़ गए. गोकुल से पिछले विधान सभा चुनावों में जीत बसपा प्रत्याशी की हुई थी. मायावती ने मथुरा जनपद को बसपा के मज़बूत क़िले में बदलने के लिए वहां विकास कार्यों की झड़ी लगा दी. विधायक को भी बढ़ावा दिया, पर विधायक गुंडों को संरक्षण देने लग गए. आज स्थिति यह है कि विधायक क्षेत्र की जनता का विश्वास पूर्णतया खो चुके हैं. आज़ादी के बाद से पहली बार गोवर्धन विधानसभा सीट सामान्य होने और गोकुल विधानसभा सीट के आरक्षित कोटे में चले जाने के बाद मायावत ने बसपा विधायक को गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र का को–ऑर्डिनेटर बना दिया और वहीं से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत दे दिया. क्षेत्र की जनता के स्वभाव से अपरिचित बसपा विधायक ने गोवर्धन में अपने पैर जमाने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी रहे पूर्व विधायक अजय कुमार पोइया के ख़ास गोवर्धन के चेयरमैन को दाना डाला. चेयरमैन ने पोइया का दामन छोड़ सत्ता के विधायक का दामन थाम लिया और क्षेत्र में उन्होंने वे सभी कार्य शुरू कर दिए जो पिछले काफ़ी दिनों से बंद थे. विधायक धृतराष्ट्र की तरह आखें बंद किए मस्त हो गए कि उनकी क्षेत्र में धाक जम रही है.

बसपा विधायक से हाथ मिलाने से पूर्व चेयरमैन ने रालोद नेता दीपक चौधरी से हाथ मिलाया था. गोवर्धन के प्रसिद्ध रमजानो कांड में जनता से चंदा एकत्र करके शव को रास्ते में रखकर जाम लगाकर क़स्बे की शांत फ़िज़ा में ज़हर घोला था. रमजानो के मामले को इन लोगों ने इतना उलझा दिया था कि वह मामला तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक सदर शशि शेखर सिंह व एस ओ डी.के. दुबे एवं उपनिरीक्षक सत्येंद्र शर्मा के लिए सिरदर्द बन गया था. गोवर्धन चेयरमैन और उनकी लॉबी के लोग थाने के सामने से होकर गुज़रने से भी डरते थे, लेकिन विधायक का संरक्षण मिलते ही वे थाने पर हुकूमत करते नज़र आने लगे. पुलिस अपने आपको बेबस और लाचार महसूस करती हुई दबी ज़ुबान में कहने लगी कि इस सरकार के बाद अन्य कोई सरकार आ गई तो इन लोगों से गिन–गिन कर बदला लिया जाएगा.

क़स्बे के एक और व्यक्ति हैं जर्नादन तिवारी, जो विधायक के ख़ास हो गए हैं. उनके नज़दीकी परिवार के एक युवक रमाकांत तिवारी पुत्र कृष्णकांत तिवारी ने 1990 के दशक में आत्महत्या कर ली थी. रमाकांत तिवारी के नाम से दिनांक 24.6.1983 को भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष महमदपुर तहसील व ज़िला मथुरा के बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत गोवर्धन–सोंख रोड पर एक प्लाट की रसीद हासिल कर ली. उक्त रसीद के आधार पर दिनांक 22.8.2006 को रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार मथुरा की बही नं. 4 जिल्द सं. 53 के पृष्ठ संख्या 291–298 में नंबर 287 पर एक रजिस्टर्ड मुख्तारनामा तैयार कराया. इसमें रमाकांत के स्थान पर जनार्दन तिवारी ने रमाकांत के छोटे भाई छुट्टन तिवारी उर्फ़ लक्ष्मीकांत को रमाकांत बनाकर पेश किया, क्योंकि रमाकांत की मौत 1990 में हो गई थी. इस तरह शैलेंद्र तिवारी के नाम यह रजिस्टर्ड मुख्तारनामा तैयार कराया गया. जर्नादन तिवारी पर्दे के पीछे रहा, मुख्तारनामे के अंतिम चरण में उसने गवाह बनकर अपने हस्ताक्षर कर दिए. इसी रजिस्टर्ड मुख्तारनामे के आधार पर तिवारी ग्रुप ने मथुरा जनपद के हाइवे थाना क्षेत्र के सतोह गांव के सीधे–साधे व्यक्ति हीरालाल को सस्ते में ज़मीन देने का प्रलोभन देकर लाखों रुपये ठग लिए. 10 मई 2007 को उपरोक्त ज़मीन का बैनामा हीरालाल की पत्नी सावित्री के नाम किया गया. जब ख़रीदार अपनी ज़मीन पर क़ब्ज़ा करने पहुंचा तो दिखाई गई जगह पर कोई ज़मीन नहीं थी, वहां तो ग्राम समाज की भूमि थी जिस पर सरकारी योजनाओं के अंतर्गत शुलभ शौचालय बन रहा था. पीड़ित ने 30.9.2009 को ज़िले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई. नतीजा ढाक के तीन पात, क्योंकि बसपा विधायक बीच में पड़ गए थे. उनका एक फंडा इन दिनों भी चल रहा है. क़स्बे के सोंख अड्डे पर एक धर्मशाला गोविंद भवन है, जो ग्वालियर के प्रतिष्ठित व्यवसायी रामकिशन वैश्य पुत्र पुरुषोत्तमदास वैश्य ने मार्कंडेय महादेव की स्थापना 15.2.1958 में कर इसे धार्मिक पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट को सौंपा था. जर्नादन तिवारी के बाबा कृष्ण चंद तिवारी को प्रबंधक नियुक्त किए थे. आज ट्रस्ट की ज़मीन की क़ीमत करोड़ों रुपयों में है. जनार्दन तिवारी के मन में लालच आ गया. उसने अपने बाबा को गुमराह करके 21 सितंबर 1999 को वाद संख्या 684 सन 1999 श्रीमान न्यायालय पंचम अतिरिक्त सिविल जज जूनियर डिवीजन मथुरा के यहां एक दीवानी वाद दायर करा दिया, जो विचाराधीन चला आ रहा था. दिनांक 28.9.2006 को वादी की मृत्यु हो जाने पर उक्त मुक़दमे में शैलेंद्र और लक्ष्मीकांत उर्फ़ छुट्टन वारिस बने. तिवारी ने वारिसों के साथ मिलकर धर्मशाला को बेचकर अच्छी ख़ासी रक़म लेने का प्लान बनाया और योजनाबद्ध तरीक़े से पुरुषोत्तमलाल पुत्र हरिहर प्रसाद निवासी नारायणपुरी धौली प्याऊ मथुरा से संपर्क कर उन्हें धर्मशाला बेचने का प्रस्ताव दिया. पुरुषोत्तमलाल के मन में भी लालच आ गया और उसने दोनों पक्षों को संतुष्ट करके 25 फरवरी 2009 को न्यायालय में राज़ीनामा कर लिया और वाद समाप्त करा दिया, लेकिन ज़मीन के राज़ीनामे से पहले ही दिनांक 15. जनवरी 2009 को लक्ष्मण प्रसाद पुत्र श्यामबाबू निवासी दसविसा गोवर्धन और प्रमोद कुमार गोयल पुत्र निरंजन प्रसाद निवासी सेठवाड़ा तिलक द्वार मथुरा को इक़रारनामा कर दिया गया. राज़ीनामे में शैलेंद्र तिवारी ने क़रीब 35 लाख रुपये तथा ज़मीन में 25 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखी थी. पैसा प्राप्त होने के बाद तिवारी के मन में पाप का अंकुर फूटा और जर्नादन तिवारी ने अपने साढ़ू गोवर्धन निवासी संजय शर्मा और परिजन शैलेंद्र तिवारी से मिलकर एक नूराकुश्ती की योजना के तहत एक दीवानी वाद दायर करके मामले को पुन: उलझा दिया. ख़रीदार पक्ष के लाखों रुपये अधर में लटक गए. अचानक मिली दौलत ने शैलेंद्र तिवारी को पंख लगा दिए थे. उसके दिन ऐश में गुज़रने लगे. उसका बड़ा भाई छुट्टन भी नशे का आदी हो गया. धीरे–धीरे ज़िंदगी पुराने ढर्रे पर लौटने लगी तो बड़े भाई को अपने हिस्से के पैसों की चिंता हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. पैसा समाप्त हो चुका था. इस संबंध में कई बार पंचायतें हुईं और तारीख़ें भी निर्धारित की गईं. लेकिन छुट्टन को उसका पैसा नहीं मिला. घर में आए दिन गृह युद्ध होने लगा. छुट्टन को प्रशासन ने ज़िला बदर कर दिया, शैलेंद्र पर अपने भाई से भी ज़्यादा संगीन मुक़दमे दर्ज हैं, लेकिन वह आज़ाद घूम रहा है. छुट्टन की 28 मार्च 2011 को मौत हो गई. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा ने तुरंत कार्रवाई कर शव को रुकवाया. श्मशान पर पुलिस देख सभी लोग भाग गए. सिर्फ़ जर्नादन और शैलेंद्र आदि एक दो घर के सदस्य रह गए थे, जिन्हें पुलिस उठा लाई. एक निजी चिकित्सक से स्वाभाविक मृत्यु क़रार दिलवाकर पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार करा दिया. इसमें पुलिस ने काफ़ी रक़म डकार ली.

राजकुमार

भानू भास्कर

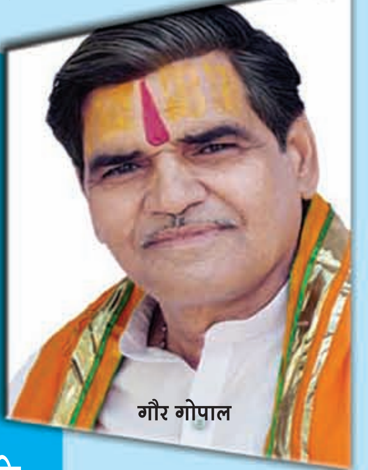

गौर गोपाल

> मायावती ने मथुरा जनपद को बसपा के मज़बूत क़िले में बदलने के लिए वहां विकास कार्यों की झड़ी लगा दी. विधायकों को भी बढ़ावा दिया, लेकिन वे गुंडों को संरक्षण देने लगे. विधायक जनता का विश्वास खो चुके हैं. आज़ादी के बाद से पहली बार गोवर्धन विधानसभा सीट सामान्य होने और गोकुल विधानसभा सीट के आरक्षित कोटे में चले जाने के बाद मयावती ने बसपा विधायक को गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र का को-ऑर्डिनेटर बना दिया और वहीं से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत दे दिया.

विधायक के नज़दीकी छैलो पंडित पिछली सरकार में समाजवादी होने का दावा करते थे. रालोद विधायक पूरन प्रकाश के चुनाव जीतते ही उनके क़रीबी हो गए थे. आज वह बसपा विधायक के क़रीबी हैं. उनके यहां महेंद्र उर्फ़ गुड्डू पुत्र विष्णु बनिया निवासी गोवर्धन रहता था. गुड्डू ने रहस्यमय परिस्थिति में आत्महत्या की थी. छैलो पंडित ने मामले को रफ़ादफ़ा कराया था. बाद में उसके नाम की चल संपत्ति को फ़र्ज़ीवाड़े से बेचकर लाखों रुपयों का गोलमाल किया था. बात करते हैं दलितों की सरकार में दलितों की नाराज़गी की. लक्ष्मण स्वरूप की पत्नी रितू देवी नगर पंचायत गोवर्धन के वार्ड नंबर दो की मौजूदा सभासद है. उसका पुत्र कृष्णकांत डीएवी इंटर कॉलेज गोवर्धन में कक्षा नौ का छात्र था. उसे उसके पिता द्वारा कॉलेज प्रशासन से फ़र्ज़ी नियुक्तियों की जानकारी, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगने पर परीक्षा से मात्र एक दिन पूर्व बिना कारण बताए निकाल दिया गया. इस संबंध में थाना गोवर्धन पर एक मुक़दमा 135 क़ायम हुआ. लक्ष्मणस्वरूप का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधक रालोद का कट्टर अनुयायी है, उसे अपने गुट में लेने के लिए विधायक ने मुक़दमा समाप्त करा दिया. पुलिस ने विधायक के नाम पर सारे नियम–क़ानूनों की धज्जियां उड़ाई हुई हैं. थाना गोवर्धन में तैनात उपनिरीक्षक सुभाष बाबू का स्थानांतरण सोनई चौकी इंचार्ज के पद पर होने के बाद थाना गोवर्धन से 8 अप्रैल 2011 को रपट संख्या 49 पर रवानगी हो गई थी. थाने पर तैनाती के दौरान उपनिरीक्षक पर वर्ष 2011 की मुक़दमा संख्या 71 धारा 384, 504, 506 में दिनांक 28.2.2011 को एफ. आर. न. बी–20 मुक़दमा अपराध संख्या 105 धारा 4/25, मुक़दमा अपराध संख्या 210 धारा 457, 380, 120 बी, में दिनांक 7 अप्रैल को एफ. आर. नं. बी–47 मुक़दमा अपराध संख्या 38 धारा 380 में दिनांक 30.1.2011 को एफ.आर.नं. बी–6 लगा दी. थाना गोवर्धन के रिकॉर्ड के हिसाब से उपनिरीक्षक सुभाष बाबू ने अपनी विवेचनाओं के संबंध में संबंधित पाटियों को संतुष्ट करके अपना धर्म तो पूरा कर लिया, लेकिन आगे की कार्यवाहियों को पूरा करते हुए पर्चे आज तक नहीं काटे हैं. इन मुक़दमों में लाखों रुपयों का हेरफेर किया गया. करोड़ो रुपयों की संपत्ति के वारिस चकलेश्वर निवासी निताई दास का शव पंखे में झूलता मिला. थानाध्यक्ष कैलाश चंद शर्मा ने आत्महत्या करार देकर मामला रफ़ा–दफ़ा कर दिया, लेकिन लोगों को महंत द्वारा आत्महत्या बताना गले नहीं उतरा तो चेयरमैन पक्ष ने अपनी राजनीतिक गोटियां सेंकनी चाहीं. मामला अख़बारों में आने लगा तो कप्तान ने अपने कार्यालय में तैनात उपनिरीक्षकों से जांच कराई और 7 मार्च को थाना गोवर्धन में मामला दर्ज हुआ, एक नामज़द को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. इस प्रकरण में पूर्व थाना प्रभारी कैलाश चंद शर्मा ने मोटी रक़म ली तथा विभाग के एक उच्चाधिकारी को भी रक़म दिलाई तभी कप्तान की बिना मर्ज़ी मामले को इतने दिनों दबाए रखा.

feedback@chauthiduniya.com

यहां विषाक्त मानव अंगों सहित अस्पतालों के कचरे लाकर नष्ट करने के कारण निकलती भयंकर दुर्गंध से संपूर्ण वातावरण दूषित हो जाता है.

फ़िरोज़ाबाद में शांति नगर शांतनु द्वारा बसाया गया था. यहां कई क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी. मुग़लिया शासन के दौरान इस नगर को तहस-नहस कर दिया गया था.

एक नज़र

शिव नाडर विश्वविद्यालय इसी सत्र से शुरू होगा

ज़िला गौतमबुद्ध नगर को दादरी में शिव नाडर विश्वविद्यालय(एसएनयू)के रूप में पहला अनुसंधान उन्मुख विश्वविद्यालय मिल गया है. विश्वविद्यालय ने स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की लांचिंग के साथ ही 2011-12 सत्र के दाख़िलों की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मई माह से संभवत: दाख़िला शुरू हो जाएगा. यह अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होगा जहां छात्रों को एक कोर्स में कई सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी होगी. शिव नाडर फाउंडेशन के ट्रस्टी टीएसआर सुब्रह्मण्यम के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिक्षा के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं. अब शिक्षा क्षेत्र में वैश्विक मानक तैयार करने के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों से मान्यता हासिल की जाएगी ताकि छात्र अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकें. एचसीएल के संस्थापक और एचसीएल टेक्नोलॉजी के चेयरमैन शिव नाडर ने बताया कि विश्वविद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के नए मानक तय करेगा. गौतमबुद्ध नगर के दादरी क्षेत्र में यह विश्वविद्यालय 286 एकड़ भूमि में तैयार किया जा रहा है. पहले चरण में 4000 और पूरा होने पर 8000 छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था होगी. विश्वविद्यालय के दूसरे चरण में स्कूल ऑफ बिजनेस, ह्यूमनिटीज, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस फैकल्टी की स्थापना की जाएगी. विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में इतना लचीलापन होगा कि छात्र अपने कोर्स में रहते हुए दूसरे कोर्स में भी अनुसंधन कर सकेंगे. शिव नाडर फाउंडेशन ने डॉ. निखिल सिन्हा को विश्वविद्यालय का संस्थापक कुलपति नियुक्त किया है.

वैट की रिकवरी के लिए विश्वविद्यालय के खाते सील

डॉ. बी. आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा ने वाणिज्य कर विभाग द्वारा आवेदनपत्रों की ख़रीद फरोख्त के लिए नोटिस देने के बाद भी जब टैक्स के आठ करोड़ तीस लाख रुपये जमा नहीं कराए तो विश्वविद्यालय के दो बैंकों के खातों को सील कर दिया गया. ज्ञात हो कि शैक्षिक संस्थानों में प्रवेशपत्रों की बिक्री पर वैट वसूला जा रहा है. वाणिज्य कर विभाग ने डॉ.बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय को प्रवेशपत्रों का ब्यौरा मिलने के बाद वैट की वसूली का नोटिस भेजा था और इसमें तीस दिन का समय दिया था. लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया. इस पर टैक्स की रिकवरी के लिए वाणिज्य कर विभाग को यह क़दम उठाना पड़ा. उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय द्वारा अपंजीकृत फर्म से 80 करोड़ रुपये के आवेदनपत्र ख़रीदे थे. इसके चलते वाणिज्य कर विभाग ने 5 प्रतिशत टैक्स लगाते हुए चार करोड़ रुपये वसूलने का नोटिस भेजा था. इसी प्रकार विश्वविद्यालय को फॉर्मों की बिक्री के लिए 86 करोड़ रुपयों पर 4.30 करोड़ रुपये टैक्स देना है. वाणिज्य कर विभाग ने विश्वविद्यालय प्रशासन से पिछले सालों के आवेदनपत्रों की ख़रीद-फरोख्त का ब्यौरा भी मांगा है. इससे विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया है.

दाग़ी वकीलों पर आयकर विभाग की नज़र

लखनऊ के आयकर विभाग ने आपराधिक चरित्र वाले वकीलों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर शुरू कर दी है. वकीलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के इरादे से सेंट्रल बार एसोसिएशन ने इन वकीलों के बारे में जानकारी मांगी है. इसके बाद इन वकीलों को नोटिस थमाई जाएगी. यही नहीं सेंट्रल बार एसोसिएशन ने दो दर्जन वकीलों का ब्यौरा आयकर विभाग को भेज भी दिया है. आयकर विभाग ने सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव से ऐसे वकीलों के वकालत का कार्यकाल, इनरोलमेंट नंबर, मूल एवं वर्तमान सहित अन्य ब्यौरा मांगा है. यह पत्र आयकर विभाग की जांच इकाई के निदेशक डॉ. नील जैन की ओर से भेजा गया है. आयकर विभाग ऐसे वकीलों की संपत्ति सहित कई मामलों की तह तक पहुंच चुका है. आयकर विभाग जल्द ही इन्हें नोटिस जारी करेगा.

महिलाओं ने लोकपाल मसौदा समिति में स्थान मांगा

वाराणसी में रमाबाई अंबेडकर महिला कल्याण संघ के बैनर तले महिलाओं ने जुलूस निकालकर जन लोकपाल मसौदा समिति में महिलाओं व दलितों की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की. जुलूस डॉ. अंबेडकर पार्क कचहरी से शुरू होकर ज़िला मुख्यालय पर समाप्त हुआ. प्रदर्शनकारी महिलाओं ने ज़िला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन भी किया और जनसभा भी की. सभा की अध्यक्षता करते हुए भाग्यवानी देवी ने कहा कि 85 प्रतिशत आबादी के अनुरूप अनुसूचित जाति/जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व महिलाओं को भी रखा जाना चाहिए. पिंडरा ब्लॉक प्रमुख प्रमिला देवी ने लोकपाल मसौदा समिति में सदस्यों के चयन की प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीक़े से कराने की मांग की.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

प्रशासन की लापरवाही से
अपराधियों के हौसले बुलंद

कमला प्रसाद गुप्त

समाजवादी पार्टी के राज में क़ानून व्यवस्था की स्थिति से आम नागरिकों में काफ़ी भय व्याप्त हो गया था. आए दिन हत्या, लूट, डकैती से लोग तंग आ गये थे. 2007 के विधानसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी ने वादा किया था कि बसपा की सरकार बनने पर सारे अपराधी जेल के अंदर होंगे. भयमुक्त क़ानून राज क़ायम होगा, जंगलराज का ख़ात्मा होगा. जनता ने इस बात पर भरोसा किया और बसपा की सरकार बनी, लेकिन इस सरकार में अपराधी और बुलंद हौसले के साथ अपराध करने लगे. उनके साथ पुलिस भी मिल गई. फ़ैज़ाबाद प्रमुख सचिव कुंवर तेगबहादुर का गृह जनपद है और यहां क़ानून व्यवस्था बद से भी बदतर है. यहां आए दिन किशोरियों की इज्ज़त तार-तार की जा रही है. विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर, बसपा के कई बड़े क़द्दावर नेताओं के इस जनपद में अपराधियों के साथ पुलिस का ज़ुल्म इस क़दर बढ़ गया है कि जनमानस परेशान है, लेकिन शांत है. आख़िर कब तक यह सरकार आज़मगढ़ की शालीन जनता का सब्र देखना चाहती है. यह सवाल पूरे जनपदवासियों का है. निज़ामाबाद क्षेत्र के बेलाऊं गांव के 35 वर्षीय अज़ीम की हत्या हो गई. इस मामले में पुलिस निज़ामाबाद थाना क्षेत्र बढ़या गांव निवासी 40 वर्षीय कमलेश सिंह को हत्या के छह दिन बाद उठा ले गई. तीन दिन तक पुलिस उससे थाने में पूछताछ करती रही. तीसरे दिन हिरासत में उसकी मौत हो गई. बिना उच्चाधिकारियों को बताए शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया. डॉक्टरों पर उन्होंने पक्ष में रिपोर्ट देने का दबाव बनाया. ऐसा न करने पर वे शव वहीं छोड़कर भाग गए. इसकी जानकारी डीआईजी राजकुमार क़ुरील को हुई. उन्होंने पूछताछ की तो बताया गया कि कमलेश ने अपने पाजामे के नाड़े से ख़ुदकुशी कर ली है. डीआईजी सहमत नहीं दिखे. कमलेश की मां की तहरीर पर उन्होंने एसपी को थानाध्यक्ष विजयसिंह, सिपाही मोहनलाल व विनोद त्रिपाठी के ख़िलाफ़ हत्या का मुक़दमा दर्ज कर निलंबित करने का आदेश दिया. उन्होंने एसपी को जांच करने को कहा. जिलाधिकारी ने भी मजिस्ट्रियल जांच की संस्तुति दे दी. डीआईजी ने मामले को अति संदिग्ध बताते हुए सीबीसीआईडी से जांच कराने की संस्तुति कर दी. उठाए जाने के दूसरे दिन ही कमलेश की हालत ठीक नहीं थी. उसका चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ था. डीआईजी ने बताया कि घटना के दिन सुबह दस बजे उन्हें कमलेश की मौत की सूचना मिली. पुलिसकर्मियों ने बताया कि कमलेश की मौत हवालात में पाजामे के नाड़े से फांसी लगाने से हुई. प्रथम दृष्टया यह मामला पूरी तरह संदिग्ध दिखाई पड़ा, क्योंकि गर्दन के अलावा नाड़े का दूसरा छोर हवालात में लगे बल्ब के होल्डर से लगा बताया गया. किसी बॉडी के बोझ को उठाने की छमता बल्ब की नहीं हो सकती. शव में चोट के निशान ज़्यादा नहीं थे. पुलिस ने 8 बजकर 5 मिनट हवालात में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का कमलेश पर आरोप लगाकर जीडी में 8 बजकर 10 मिनट पर मुक़दमा दर्ज कर लिया था, जबकि डीआईजी को बताया गया कि उसने पाजामे के नाड़े से फांसी लगाकर ख़ुदकुशी की है. कमलेश पर किसी थाने में मुक़दमा दर्ज नहीं था. वह आटा पीसकर तथा तेल की पेराई कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था. पुलिस हिरासत में कमलेश की मौत कोई पहली घटना नहीं है. इसके पूर्व भी वर्ष 2003 में रानी की सराय थाने में बैटरी चोरी के एक मामले में दौलतपुर गांव के हरीलाल यादव की थाने में गोली लगने से मौत हो गई थी. इस घटना में एसआई एनबी सिंह पर हत्या का मुक़दमा दर्ज हुआ था, जबकि थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी निलंबित हुए थे. एसआई एनबी सिंह ने थाने में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. वर्ष 2003 में रानी की सराय थाना क्षेत्र में विजयीपुर गांव निवासी वासदेव यादव को पकड़कर थाने में ले आई. पुलिस हिरासत में वासदेव यादव की मौत हो गई. इस मामले में थानाध्यक्ष जेएन यादव सहित कई पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुक़दमा दर्ज हुआ था. 4 दिसंबर 2005 को रानी की सराय थाना क्षेत्रांतर्गत तमौली गांव निवासी सुरेश यादव व ब्रजेश यादव पुत्र मुम्मर यादव को सिधारी थाने की पुलिस एक मामले में पकड़कर थाने पर ले आई. पुलिस हिरासत में ही सुरेश यादव की मौत हो गई. पुलिस का कहना था कि रात में सुरेश थाने से भाग रहा था कि समीप में ही स्थित पोखरे में गिर गया. डूबने से उसकी मौत हो गई, जबकि सुरेश के परिजनों ने हत्या करके सुरेश का शव पोखर में फेंके जाने का पुलिस पर आरोप लगाया था. इस घटना में थानाध्यक्ष सहित कई पुलिस वालों के विरुद्ध हत्या का मुक़दमा दर्ज हुआ था. 15 मई 2010 को हत्या के एक मामले में रानी की सराय थाने की पुलिस मृत सुरेश यादव के भाई बृजेश यादव को एक बार फिर पकड़ कर थाने पर ले आई. पुलिस हिरासत में ही बृजेश यादव की मौत हो गई. इस मामले में भी थानाध्यक्ष सहित कई पुलिसकर्मी बृजेश यादव के परिजनों की तहरीर पर हत्याभियुक्त बनाए गए. सभी मामले आज भी न्यायालयों में विचाराधीन हैं.

फ़ैज़ाबाद प्रमुख सचिव कुंवर तेगबहादुर का गृह जनपद है और यहां क़ानून व्यवस्था बद से भी बदतर है.

feedback@chauthiduniya.com

गंगा सफ़ाई परियोजना को केंद्र ने मंज़ूरी दी

7000 हज़ार करोड़ रुपये की राशि गंगा नदी की सफ़ाई के लिए कम नहीं है. अब तक जो भी गंगा सफ़ाई परियोजनाएं लागू की गईं, उनमें अरबों रुपये ख़र्च होने के बाद भी गंगा नदी आज भी मैली बनी हुई है.

गौरव अरोरा

भारत की महत्वपूर्ण नदी गंगा की सफ़ाई के लिए केंद्र सरकार ने 7000 करोड़ रुपये की परियोजना को हाल ही में मंज़ूरी दी है. इस परियोजना को राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण लागू करेगा. इस प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री और सदस्य जिन राज्यों से नदी गुज़रती है, वहां के मुख्यमंत्री होते हैं. इससे पूर्व भी गंगा नदी की सफ़ाई की अनेक परियोजनाएं लागू हो चुकी हैं, लेकिन सभी परियोजनाओं का परिणाम ढाक के तीन पात ही रहा. इसलिए इस बार 7000 हज़ार करोड़ रुपये की राशि पूरी गंगा नदी की सफ़ाई के लिए ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं है. अब तक जो भी गंगा सफ़ाई परियोजनाएं लागू की गईं उनका अरबों रुपया ख़र्च होने के बाद भी गंगा नदी आज भी मैली बनी हुई है क्यों? क्या गंगा को मैली करने वाले स्त्रोतों को बंद नहीं किया गया था या सफ़ाई परियोजना समाप्त होने के बाद भी यह मालूम नहीं हो सका कि गंगा मैली क्यों हो रही है. गंगा को प्रदूषित करने के स्त्रोत मालूम हो जाने के बाद उन्हें इसलिए ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया कि गंगा बराबर मैली होती रहे और बार-बार उसकी सफ़ाई के लिए परियोजनाएं बनती रहें.

नवंबर 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी तथा इलाहाबाद और हल्दिया के बीच 1600 किलोमीटर के गंगा नदी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया था, पर साथ ही केंद्र सरकार गंगा ने नदी के किनारे बिजली परियोजनाओं को मंज़ूरी देकर राष्ट्रीय नदी भावना का कचूमर भी निकालती रही. सवाल उठता है कि सरकार ने गंगा के प्रवाह को कमज़ोर करने के बजाय उसके विकल्पों पर विचार क्यों नहीं किया? हाल ही में कानपुर में गंगा नदी में हज़ारों मछलियां मरी हुई पाई गईं. इसकी शिकायत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को की गई. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी राधेश्याम ने बताया कि नवाबगंज के दुर्गापुरवा के पास गंगा नदी में हज़ारों मछलियों के मरने का असल कारण तो पानी की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा, लेकिन मौटे तौर पर इसका कारण जल-प्रदूषण ही है. क्या कानपुर की टेनरियों का प्रदूषित कचरा गंगा नदी में डाला जाना बंद हो गया?

गंगा नदी हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है. यह देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन-जन की आस्था का आधार भी है. 2071 किलोमीटर तक भारत तथा इसके बाद बांगलादेश में अपनी लंबी यात्रा करते हुए यह सहायक नदियों के साथ दस लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है. सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गंगा का यह मैदान अपनी घनी जनसंख्या के कारण भी जाना जाता है. 100 फीट की अधिकतम गहराई वाली यह नदी भारत में पवित्र मानी जाती है. गंगा की सफ़ाई की इस 7000 हज़ार करोड़ रुपये की परियोजना में 5,100 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और शेष 1,900 करोड़ रुपये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें वहन करेंगी. विश्व बैंक इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार को एक अरब डॉलर (क़रीब 4,600 करोड़ रुपये) सहायता मुहैया कराने पर सहमत है. गंगा सफ़ाई परियोजना की अवधि आठ वर्ष तय की गई है. इसके तहत किए जाने वाले कार्यों में गंगा नदी घाटी में पर्यावरणीय नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा, जैसे नगर निकायों के गंदे पानी के नालों, औद्योगिक प्रदूषण, कचरे व नदी के आसपास के इलाक़ों का बेहतर और कारगर प्रबंधन शामिल है. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले इस प्राधिकरण का उद्देश्य व्यापक योजना और प्रबंधन के ज़रिए गंगा नदी का संरक्षण करना है. जून में मनेगा गंगा संरक्षण सप्ताह. गंगा नदी को राष्ट्रीय महत्व की नदी घोषित करवाने और गंगा के पहले चरण (गोमुख से उत्तरकाशी तक के 145 किलोमीटर) को ईको सेंसिटिव जोन घोषित करवाने की सफ़लता के बाद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह जल-पुरुष की एक और पुरानी मांग को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है. हिंदू धर्म की परंपराओं में ज्येष्ठ माह की दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं. उनकी श्रद्धा और आस्था को ध्यान में रखते हुए राजेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार से विगत कई वर्षों से इन अवसरों पर नदी के प्रवाह में जल-राशि की पर्याप्त मात्रा की मांग की थी, जिसे 26 अप्रैल को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की स्वीकृति के बाद मान लिया है. इस आदेश को सभी संबंधित गांगेय राज्यों में मुख्यमंत्रियों को भेज दिया गया है. विगत वर्ष नई दिल्ली के विश्व युवा केंद्र में हुई 21 जून की बैठक में देश भर से आए जल और पर्यावरण विशेषज्ञों और पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश की उपस्थिति में राजेंद्र सिंह की तरफ़ से यह मांगपत्र प्रस्तुत किया गया था. इस मांगपत्र में गंगा दशहरा की मान्यता और आस्था को मद्देनज़र रखते हुए इस उपलक्ष्य में दस दिन गंगा के प्रवाह में जल-राशि पर्याप्त रखने की प्रमुख मांग की गई थी. केंद्र सरकार ने इस मांग को मानते हुए इस वर्ष 5 जून से 11 जून तक के सप्ताह को गंगा संरक्षण सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है. इस संबंध में गंगा सहित अन्य सभी नदियों की शुचिता और प्रवाह को अबाध करने के संबंध में भी केंद्र सरकार ने सहमति प्रकट की है. इस पूरे सप्ताह पूरे देश में गंगा के प्रति समर्पण जताते हुए पर्यावरण और ख़ासकर गंगा के प्रति जागरूकता और जन-भावना को जागृत करने का काम किया जाएगा. कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी मंडल के आयुक्तों ने इस आदेश के बारे में हर्ष जताया और इस कार्यक्रम में जन-सहभागिता के साथ बड़े सामूहिक कार्यक्रम करने की सहमति जताई. इन सभी ने इस पूरे सप्ताह को ज़िलेवार मनाने के लिए योजना बना ली है.

हिंदू धर्म की परंपराओं में ज्येष्ठ माह की दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं. उनकी श्रद्धा और आस्था को ध्यान में रखते हुए राजेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार से विगत कई वर्षों से इन अवसरों पर नदी के प्रवाह में जल राशि की पर्याप्तता की मांग की थी, जिसे 26 अप्रैल को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की स्वीकृति के बाद मान लिया है.

feedback@chauthiduniya.com

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का काला कारनामा

विश्व भर में प्रदूषण सर्वाधिक चिंता का विषय है. पीने के पानी से लेकर नदियों के प्रदूषण, वायु-प्रदूषण की रोकथाम के लिए विभिन्न उपाय अमल में लाए जा रहे हैं. अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर कमा-खा रही हैं, लेकिन प्रदूषण है कि बढ़ता ही जा रहा है. दरअसल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ही मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए प्रदूषण फैलाने वालों को संरक्षण दे रहा है.

फ़ैज़ाबाद रायबरेली मार्ग पर मऊशिवाला बाज़ार में एक कार्यशाला में विगत 5-6 वर्ष पहले रुई-पट्टी बनाने का कार्य होता था. कार्यशाला के स्वामी ने इस भवन को बेच दिया. इस भवन में एक अन्य कार्य के लिए सरकारी अनुमति लेने की प्रक्रिया शुरू हुई. मैसर्स सोनो मेडिकल सिस्टम (इंडिया) प्रा. लि., एफ-23, भीमताल इंडस्ट्रियल इस्टेट, भीमताल (उत्तरांचल) नामक फर्म द्वारा उक्त मऊशिवाला स्थित कार्यशाला में बायो मेडिकल वेस्ट के ट्रीटमेंट हैंडलिंग डिस्पोजल प्रोजेक्ट के लिए आवेदन किया. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र मांगा गया. इस संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय फ़ैज़ाबाद द्वारा भेजा गया पत्र सं. 406/ जी.चि.अ. /06-07 दिनांक 17-10-06 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 13-11-06 को प्राप्त हुआ. जवाब में कहा गया कि प्रस्तावित स्थल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होता है, अत: आवेदन अस्वीकृत किया जाता है. एस.एस. मेडिकल सिस्टम संस्था द्वारा जिस कार्य के लिए प्रमाणपत्र की याचना की गई थी वह पर्यावरणीय मानकों के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर वर्जित है. पास ही कई हज़ार की घनत्व वाली आबादी है. संस्था द्वारा यहां तमाम सरकारी और ग़ैर सरकारी अस्पतालों के तमाम कचरे, जिसमें अस्थि, मज्जा युक्त कचरा भी शामिल है, को तकनीकी उपकरणों की मदद से नष्ट करने वाला सिस्टम लगाने के लिए प्रमाणपत्र मांगा गया था. यहां घनी आबादी के बीच में कचरा सड़ाने, गलाने, जलाने का कार्य किया जाता है. संस्था को मऊशिवाला के निकट कचरे के विनष्टीकरण का अधिकारपत्र दे दिया गया. क्षेत्रीय प्रदूषण बोर्ड अधिकारी फ़ैज़ाबाद से लेकर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तक के लोग ही नहीं, बल्कि संबंधित मंत्रालय के तत्कालीन मंत्री भी इस अनापत्तिपत्र जारी करने के कृत्य में शामिल थे. मेडिकल सिस्टम (इंडिया) प्रा.लि. मऊशिवाला फ़ैज़ाबाद को संबोधित व प्रेषित किया गया, जिसमें नियमों का उल्लेख किया गया है. इसमें लिखा है कि मैसर्स एस.एस. मेडिकल सिस्टम (इंडिया) प्रा.लि. इज हीयर ग्रांटेड एन आथराइजेशन टू आपरेट ए फैसिलिटी फॉर कलेक्शन, रिसेप्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पोजल ऑफ बायो केमिकल्स वेस्ट इन द प्रिमिसेज सिचुएटेड एट मऊशिवाला फ़ैज़ाबाद. यह अधिकार पत्र दो वर्ष के लिए प्रभावी क़रार दिया गया है. कचरे के विनष्टीकरण के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत अधिकार पत्र के साथ ही मैसर्स एस.एस. मेडिकल सिस्टम संस्था द्वारा पूर्व निर्धारित कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया. इस संस्था में जिन-जिन जनपदों के चिकित्सालयों के कचरे के आने की व्यवस्था है, इनमें फ़ैज़ाबाद, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, सुलतानपुर, बाराबंकी सहित अंबेडकरनगर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच व श्रावस्ती शामिल हैं. क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फ़ैज़ाबाद द्वारा बताया गया है कि मैसर्स एस.एस. मेडिकल सिस्टम (इंडिया) प्रा.लि. रायबरेली रोड, मऊशिवाला फ़ैज़ाबाद जिसके स्वामी संचालक मुनीश भंडारी निवासी लखनऊ हैं और यह संस्था यूपी, एचएसडीपी द्वारा वित्तपोषित है जिसके संचालन का वर्ष जनवरी 2008 है. यहां विभिन्न अस्पतालों का लगभग 1600 कि.ग्रा. कचरा प्रतिदिन आता है. विषाक्त मानव अंगों सहित अस्पतालों के कचरे को यहां लाकर नष्ट करने के कारण निकलती भयंकर दुर्गंध से संपूर्ण वातावरण दूषित हो जाता है जो कई तरह की बीमारियों को जन्म दे रहा है. इस कार्यशाला को यहां से हटाए जाने के संबंध में स्थानीय निवासियों ने विरोधस्वरूप ज्ञापन, प्रार्थनापत्र, धरना प्रदर्शन आदि सबकुछ किया, लेकिन क्षेत्रवासियों की उपेक्षा के अलावा आज तक हुआ कुछ नहीं. उक्त संस्था के प्रतिनिधि रंजीत सिंह द्वारा क्षेत्र के प्रमुख विरोधी कार्यकर्ताओं जिनमें जंगजीत बहादुर सिंह, शिवराम सिंह, गयाबख्श सिंह, रवींद्र बहादुर सिंह, मनोज कुमार मालवीय, अशोक कुमार मिश्र, अर्जुन सिंह, जयनाथ सिंह, राम किशोर सिंह आदि के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान एक लिखित समझौता भी किया गया था. समझौते में कहा गया कि अब यहां कोई कचरा नहीं लाया जाता. स्थानीय लोगों ने भी इसकी पुष्टि की है. जनपद फ़ैज़ाबाद के एस.एस मेडिकल सिस्टम (इंडिया) प्रा.लि. के इंसीनेटर में लखनऊ, गोरखपुर, देवीपाटन मंडलों के आठ ज़िलों के सैकड़ों (निजी-सरकारी) अस्पतालों के कचरे सहित शहर फ़ैज़ाबाद के भी अस्पतालों का कचरा यहां आ रहा है. जनपद में इस समय 50 नर्सिंग होम व अस्पताल पंजीकृत हैं. बायो मेडिकल वेस्ट को इंसीनेटर में जलाकर नष्ट किया जाता है म्यूनिसिपल वेस्ट को मिट्टी के गड्ढों में पाट दिया जाता है सिरिंज, ग्लूकोज की बोतलों आदि को माइक्रो वेयर में उच्चताप पर उबालकर थ्रेडर में गलाया जाता है. एक अनुमान के मुताबिक़ यहां आने वाले कुल कचरे में 45 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक म्यूनिसिपल वेस्ट होता है. कंपनी के पास कचरे को जलाने हेतु इंसीनेटर प्लांट तो हैं, लेकिन इसका आंतरिक तापमान मानक से कम है जो कि 800 से 1000 सेंटीग्रेट तक होना चाहिए. संस्थान में एपीटी (शुद्धिकृत संयंत्र प्लांट) भी नहीं लगा है. पर्यावरण मंत्री के निर्देश पर उक्त संस्थान में हुई जांच के बाद जांच कमेटी ने पाया कि संस्थान का उत्प्रवाह शुद्धिकरण यंत्र सही नहीं है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार पीसीएल सिस्टम ऑटोमेटिक फीडिग सिस्टम प्रभारी तथा सेकेंड्री चेंबर हेतु लोमीटर तथा कूलिंग प्रेशर निगेटिव प्रेशर के मापन एवं रिकार्डिंग की मशीन नहीं लगी मिली. संस्थान के प्रतिनिधि के अनुसार कचरा लेकर प्रतिदिन शाम को गाड़ियां संस्थान पर आती हैं. ये गाड़ियों की कहां धुलाई की जाती है, इसका कोई अता-पता नहीं है. लखनऊ से फ़ैज़ाबाद के बींच की 130 किमी. की दूरी तय करके कौन-सी बंद एसी गाड़ी कचरे को लाती है, यह भी अंधेरे में है. समाचार पत्रों में क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फ़ैज़ाबाद द्वारा कहा गया है कि अस्पताल शैक्षिक संस्थानों न्यायालयों आदि के 100 मीटर की परिधि का क्षेत्र साइलेंट जोन माना गया है. यह भी कहा गया कि आवासीय क्षेत्र में औद्योगिक व्यवसायिक गतिविधियां मान्य नहीं हैं. एस.एस. मेडिकल्स के एक ठेकेदार मनोज कुमार मिश्र से भी उत्तेजित ग्रामीणों के मध्य स्थानीय पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में जो समझौता हुआ था वह भी हवा-हवाई ही है. स्थानीय लोगों में जंगजीत बहादुर सिंह, पत्रकार अनंत राम पांडेय, गया बख्श सिंह, जयनाथ सिंह, राज कुमार यादव, शिवराम सिंह, रंजीत सिंह, रमेश प्रताप, उमेश प्रताप, अरविंद कुमार, मंशाराम, अंकित यादव, विशाल यादव, मंगरू आदि अभी भी इस प्लांट को यहां से अन्यत्र स्थानांतरित कराने को प्रयासरत हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है. संस्थान को पहले अनुपयुक्त पाकर फिर किन दशाओं में अनापत्ति प्रमाण पत्र देकर संस्था को कार्य निष्पादन हेतु अधिकार पत्र निर्गत कर दिया. यह गंभीर रूप से जांच का विषय है. यह कहना अनुचित न होगा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इस विभाग के मंत्री और उनका मंत्रालय निश्चित ही इस अवैध और अवांक्षित कार्य के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है और दंडनीय भी. संक्रामक बीमारियों को जन्म देता संस्थान के स्वामी व प्रबंध द्वारा अपशिष्ट निस्तारण के नाम पर किया जा रहा धनार्जन मानव जीवन से खिलवाड़ है. मैसर्स एस.एस. मेडिकल सिस्टम (इंडिया) प्रा.लि. मऊ यदुवंशपुर फ़ैज़ाबाद कार्यालय का नवीनीकरण तो तत्काल ही रोक दिया जाना जनहित में होगा.

रंजीत बहादुर

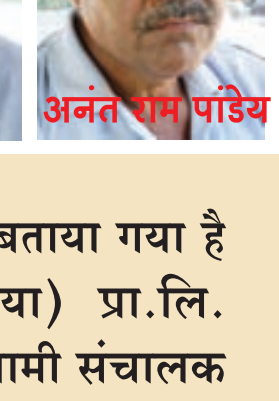

अनंत राम पांडेय

रविंद्र सिंह

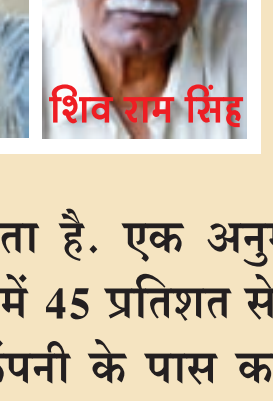

शिव राम सिंह

कुंवर बहादुर बिसेन
feedback@chauthiduniya.com

शहीदों की याद में वीर स्तंभ स्थापित करने की मांग

शिवम तिवारी

फ़िरोज़ाबाद के सांती क्षेत्र को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की मांग दशकों से उठाई जाती रही है. इस मांग को न तो ज़िला प्रशासन ने और न ही प्रदेश की किसी भी सरकार ने गंभीरता से लिया. सभी राजनीतिक दल इस बात को स्वीकारते हैं कि शहर में एक पर्यटन स्थल की सख्त ज़रूरत है और इसके लिए सांती क्षेत्र सबसे उपयुक्त और महत्व की जगह है. फ़िरोज़ाबाद क्षेत्र में कोई ऐसा स्थान नहीं है, जहां लोग अपने परिवार के साथ वीक एंड पर या कभी फुर्सत के क्षणों में जा सकें. इस संबंध में स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर मोहनसिंह और स्वर्गीय बाबूराम खैरगढ़ वाले जनपद के लोगों के सहयोग से निरंतर सांती क्षेत्र को पर्यटक स्थल बनाने की मांग उठाते रहते थे.

महाराजा शांतनु द्वारा बसाई गई नगरी सांती प्रारंभ से ही आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता की प्रेरणास्रोत रही है. यह क्षेत्र स्वाभिमान, सम्मान और राष्ट्र-प्रेमियों का गढ़ भी रहा है. इस वैभवशाली क्षेत्र में सन् 1857 की क्रांति के समय यहां के वीर सपूतों ने क्रांति का बिगुल फूंककर अपने प्राणों की आहुतियां दी थीं. अंग्रेजों ने यहां चंदन के बाग में सैकड़ों क्रांतिकारियों को चंदन के पेड़ पर लटकाकर उन्हें फांसी दी थी. इससे पूर्व इस धार्मिक नगरी पर मुहम्मद शाहबुद्दीन गौरी एवं महमूद ग़ज़नवी ने आक्रमण कर तहस-नहस कर दिया था. क्षेत्र के लोग लंबे अर्से से इस आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक क्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाने के साथ ही यहां शहीदों की स्मृति में वीर स्तंभ की स्थापना किए जाने की मांग भी करते आ रहे हैं. यहां ठाकुर राजा सरनाम सिंह के बाद ज़मींदार ठाकुर रेवतीराम सिंह ने अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया था और फ़िरोज़ाबाद को लुटने से बचाया था. अंग्रेजों ने फ़िरोज़ाबाद को लूटने के लिए आक्रमण किया, तभी ज़मींदार रेवतीराम सिंह ने अपनी फ़ौज को लेकर अंग्रेजी सेना का जमकर मुक़ाबला किया. जब अंग्रेजों को फ़ौजियों के मरने की जानकारी हुई तब उन्होंने ऐतिहासिक शांतनु नगरी सांती स्थित महलनुमा गढ़ी पर सामूहिक हमला बोला. ठाकुर साहब की फौज ने बड़ी बहादुरी के साथ मुक़ाबला किया, उनकी सेना का सेनापति एक वाल्मीकि था, उसके वीरगति को प्राप्त होते ही सेना में खलबली मच गई और सेना क़स्बा खैरगढ़ स्थित गढ़ी में पहुंचकर सुरक्षित हो गई. अंग्रेजों ने सांती स्थित गढ़ी पर क़ब्ज़ा कर लिया और वहां रखी तोप सहित अन्य संपत्तियों को ज़ब्त कर लिया. 1857 में जब क्रांति असफ़ल हो गई, तब यहां चंदन वाले बाग में क़रीब दो हज़ार क्रांतिकारियों को क्रूरता के साथ चंदन के वृक्ष पर फांसी दे दिया गया. यह लोमहर्षक हत्याकांड ग्राम प्रतापपुर निवासी स्व. तुलसी काछी की मां ने अपनी आंखों से देखा था. वह बताती थीं कि चंदन के बाग़ में क्रांतिकारियों को लटका दिया जाता था और अंग्रेज उन्हें लटका-लटकाकर तलवार से तीन बार काटते थे. इस तलवारीय खेल में कोई जीवित बच जाता था तो अंग्रेज इसे अंग-भंग अवस्था में छोड़ देते थे. तुलसी काछी की माता प्रतिदिन काली ओढ़नी ओढ़कर महाराज शांतनु द्वारा प्रतिस्थापित भगवान शांतेश्वर महादेव के दर्शन करने आती थीं. वह बाज़ार करने भी इसी मार्ग से होकर आती-जाती थीं. तब वह क्रूरतापूर्ण दृश्य देखा करती थीं. इस क्रांति में प्रतापपुर निवासी रुद्र प्रताप के भाई भी थे, जिन्हें अंग्रेजों ने वृक्ष पर लटकाया था और वह जीवित बच गए थे. उनके दोनों पैर और एक हाथ कट गया था. इतिहासविद् डॉ. राणाप्रताप गुप्त ने बताया कि यह क्षेत्र पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व का है. साढ़े पांच हज़ार वर्ष पूर्व महाराजा शांतनु ने इसे अपनी उपासना स्थली बनाया था. इसके बाद यहां बड़ी-बड़ी हस्तियों ने जन्म लिया. इस क्षेत्र के जवानों एवं ज़मींदारों ने गदर के समय अंग्रेजों से लोहा लिया था और हज़ारों क्रांतिवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी. शांतनु खेरा तथा श्री शांतनु महादेव शिव मंदिर आदर्श धार्मिक पाठशाला एवं संस्कारशाला में हर समय देश प्रेम के साथ भक्ति ज्ञान और वैराग्य की धारा बहती रहती थी. शांतनु खेरा और मंदिर सदियों पुरानी कई ऐतिहासिक स्मृतियों को अपने गर्भ में संजोए हुए है. डॉ. गुप्त के अनुसार अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए नेता सुभाष चंद्र बोस व महात्मा गांधी के आह्वान पर सर्वप्रथम इस क्षेत्र के मंगलसिंह, सियाराम आज़ाद, लालाराम उर्फ़ बाबा, प्रेमानंद, झुम्मन, आजाद उर्फ़ निहाल सिंह व बाबूराम (खैरगढ़) एवं मोहन सिंह आदि ने देश में क्रांति की ज्योति जलाई थी. यहीं से स्वतंत्रता की चिंगारी उठी थी, जिसमें अनेक क्रांतिकारी शहीद हुए थे. इन शहीदों की स्मृति में यहां वीर स्तंभ की स्थापना केंद्र व प्रदेश सरकार को करानी चाहिए तथा सांती की खंडहर हो चुकी दो किलोमीटर लंबी-चौड़ी गढ़ी की खुदाई कराकर पुरातत्व एवं सांस्कृतिक विरासत को सहेजना चाहिए. चूंकि यह क्षेत्र पौराणिक, ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है, इस कारण इसे आकर्षक पर्यटक स्थल का स्वरूप मिलना आवश्यक है.

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

केले की खेती ने मालामाल किया

बहराइच के कैसरगंज तहसील के किसानों ने तेज़ी के साथ केले की खेती को अपनाया है. केले की यह खेती उन्हें मालामाल ही नहीं कर रही, बल्कि बेरोज़गारों के लिए रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध करा रही है. किसान क्लब इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. जमल्दीपुर गांव का एक बड़ा हिस्सा अब केले की खेती के लिए जाना जाता है. इसका श्रेय यहां के किसान क्लब को है. किसानों के अनुसार टिश्यू कल्चर खेती से उत्पादन बढ़ा है, जिससे किसानों की आय बढ़ी है. केले की पौध लगाने का समय मई से अगस्त तक होता है. अच्छी तरह जुताई करके जब खेत तैयार हो जाए तो एक गड्ढे में रासायनिक खाद, माइक्रोन्यूट्रिसंस एवं मैक्रोन्यूट्रिसंस उचित मात्रा में मिलाकर गड्ढे में भर देते हैं. केले की पौध को गड्ढे के बीचों बीच शाम के समय लगाते हैं. पौधरोपण के तुरंत बाद ही केले की सिंचाई की जाती है. केले की खेती के लिए ज़मीन हर समय नम रहनी चाहिए, पर जलभराव जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए. इसमें 9 से 10 महीने बाद केले के पेड़ में फूल आ जाते हैं और फूल आने के तीन से चार महीने बाद केले मंडी में बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं. प्रत्येक पौधे के घार में 8 से 10 गुच्छे होते हैं और प्रति घार में केले की फलियों की संख्या 300 से 375 होती है और प्रत्येक घार का औसत वजन 32 किलो से 50 किलो होता है.

छठी शताब्दी के अवशेष मिले

उन्नाव ज़िले का सोनिक गांव क़रीब 25 सौ साल पुरानी सभ्यता को कोख में छिपाये रखने वाले एक गांव के रूप में जाना जाने लगेगा. रेल की पटरियों के सहारे बसे इस गांव में पुरातत्व विभाग को पिछले दिनों खुदाई के दौरान यहां से छठी-सातवीं शताब्दी के सांस्कृतिक व रिहायशी अवशेष प्राप्त हुए थे. इससे सिद्ध होता है कि इस ज़माने में यहां कोई गांव बसा हुआ होगा. सोनिक रेलवे स्टेशन से क़रीब आधा किलोमीटर दूर बसहा झील के पास 150 मीटर क्षेत्र में खुदाई के दौरान राज्य पुरातत्व विभाग की टीम को हज़ारों वर्ष पहले के सांस्कृतिक एवं रिहायशी अवशेष प्राप्त हुए हैं. अवशेषों में मिट्टी के काले व लाल रंग के भांड (बर्तन), थाली, कटोरे, छोटे आकार के घड़े, अलंकृत व चित्रित पात्र व कुछ छोटे आकार के पूजा पात्र मिले हैं. सांस्कृतिक अवशेषों में हड्डी के बने हुए बाण, बाणों के नुकीले हिस्से को रखने के लिए हड्डी के खोल, गले में पहनने वाले पत्थर व मिट्टी के मनके आदि मिले हैं. इसके अलावा रिहायशी अवशेषों में मिट्टी की दीवारों व झोपड़ी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं. खुदाई स्थल पर आधा दर्जन गोल व यू आकार के चूल्हे भी पाए गए हैं. इन चूल्हों के पास की ज़मीन काली पाई गई है. खुदाई में फर्शनुमा ज़मीन भी मिली है.

रेल नीर की जगह नेस नीर

आगरा रेल मंडल के सभी स्टेशनों पर इन दिनों अधिकृत रूप से बिकने वाले रेल नीर के स्थान पर मिलते-जुलते नाम और डिजाइन वाला नेस नीर बेचा जा रहा है, जबकि रेल नीर स्टेशनों से एकदम ही ग़ायब कर दिया गया है. नेस नीर की बोतल और उसका लेबल हूबहू रेल नीर से मिलता-जुलता है. सामान्य अनपढ़ ग्राहक को इसके नक़ली होने का आभास तक नहीं होता. वह तो पढ़ा लिखा ग्राहक जब लेबल को पढ़ता है तब ही इसे इस घपलेबाज़ी का पता चलता है. यह सारी घपलेबाज़ी की जानकारी रेलवे अधिकारयों को भी है, लेकिन सभी मौन हैं. इसका सीधा अर्थ यही निकलता है कि इस घपलेबाज़ी में कोई बड़ा खिलाड़ी शामिल है. बोतल को हाथ में लेकर देखो तो न तो इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है और न पानी की गुणवत्ता के बारे में. इन दिनों यहां गर्मी भी भीषण रूप से पड़ने लगी है, जबकि किसी भी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को ठंढे पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है. इसलिए प्यास के मारे यात्री पानी की ठंडी बोतल लेने के लिए दौड़ते हैं और ठगी का शिकार होते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि यह पानी की बोतल भी सामान्य रेट से महंगे दामों में बेची जा रही है. आगरा रेल मंडल से हर रोज़ क़रीब ढाई सौ ट्रेनें गुज़रती हैं. अनुमानत: पांच हज़ार पानी की बोतलों की प्रतिदिन खपत होती है. यह घपलेबाज़ी चार सौ बीसी ही नहीं है, बल्कि जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ भी है.

वाराणसी के 12 हज़ार कुओं में पानी नहीं

गर्मी और भूजलस्तर नीचे चले जाने के कारण वाराणसी ज़िले के 12 हज़ार कुओं से पानी ग़ायब हो गया है. ये ऐसे कुएं हैं जहां से लोग पेयजल, स्नान और अन्य कार्यों के लिए पानी इस्तेमाल करते थे. स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराए गए सर्वे की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है. कुओं के पानी को विसंक्रमित करने के लिए अभियान शुरू किया गया है. पिछले वर्ष भी जून माह में अधिकांश कुएं सूख गए थे, लेकिन इस वर्ष अप्रैल माह में ही स्थिति भयावह हो गई है. स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भूगर्भीय जलस्तर नीचे चले जाने से ऐसी स्थिति हुई है. इन इलाक़ों के हैंडपंप भी पानी छोड़ने लगे हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि हालात न बदले तो अगला विश्वयुद्ध पानी के लिए ही होगा. इसलिए हमारे राजनीतिज्ञों को पानी बचाने और नदियों को पुनर्जीवित करने पर ध्यान देना चाहिए.

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

पुष्टाहार की कालाबाज़ारी

महेंद्र अवधेश

सरकार के चाहने से भला क्या होता है! हो भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक अधिकारियों कर्मचारियों की मर्ज़ी नहीं होगी, तब तक कोई भी ताक़त किसी कार्यक्रम को कामयाब नहीं बना सकती. प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों में अध्ययन–अध्यापन की दयनीय दशा और बाल पुष्टाहार योजना में बंदरबांट की आएदिन मिलने वाली शिकायतें इस बात की गवाह हैं. कोई आश्चर्य नहीं हुआ, जब ज़िला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान कानपुर के नवीन नगर और राजा पुरवा स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चे नदारद पाए गए, उपस्थिति रजिस्टर में विसंगतियां मिलीं और पता चला कि बतौर पुष्टाहार पंजीरी और हॉट कुक्ड योजना का राशन केंद्र की कार्यकर्ताओं द्वारा डकारा जा रहा है. यह काम अर्से से हो रहा है. सरकार कुपोषण से लड़ने के लिए नानाविध इंतज़ाम कर रही है, लेकिन केंद्र संचालिकाएं बच्चों–महिलाओं के हक़ पर बटमारी कर रही हैं. पढ़ाना–लिखाना तो दूर की बात, अधिकांश केंद्र रोज़ नियम से खुलते तक नहीं हैं. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का ध्यान सिर्फ़ इस बात पर रहता है कि किस घर में कितने बच्चे हैं, कितनी महिलाएं हैं और उनमें कितनी गर्भवती हैं, उनकी उम्र कितनी है. सारा विवरण दर्ज करके वे सिर्फ़ अपना रजिस्टर मेंटेन करती रहती हैं, जिससे अधिक से अधिक पुस्तकें, कॉपियां, बस्ते, पंजीरी और अन्य सामग्री हासिल की जा सके और उन्हें बाज़ार में बेचकर अवैध कमाई की जा सके.

जानकारी के अनुसार, पचास लाख से भी ज़्यादा आबादी वाले कानपुर में 2022 आंगनवाड़ी और 112 लघु आंगनवाड़ी केंद्र हैं. हर केंद्र पर एक कार्यकर्ता और एक सहायक की तैनाती है. ज़िले में बाल पुष्टाहार योजना के तहत 2,85,375 बच्चे, 59,436 गर्भवती/धात्री महिलाएं और 1,64,562 किशोरियां पंजीकृत हैं. इनमें से 81,360 बच्चे कुपोषण का शिकार हैं. आंगनवाड़ी केंद्रों पर इन बच्चों को प्रतिदिन 50 ग्राम पंजीरी या चना–गुड़ और दोपहर में पका हुआ भोजन, महिलाओं एवं किशोरियों को प्रतिदिन 125 ग्राम पंजीरी देने का प्रावधान है, लेकिन शायद ही किसी केंद्र पर इस नियम का पालन होता हो. प्रदेश शासन के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा निगरानी के बावजूद केंद्र संचालिकाओं की मनमानी चरम पर है. नवीन नगर स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीयन रजिस्टर और उपस्थिति रजिस्टर में फ़र्क़ मिला और मालूम हुआ कि प्रतिदिन चार–पांच बच्चे ही आते हैं, लेकिन उपस्थिति 25–30 बच्चों की दिखाई जाती है. राजा पुरवा स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर तो एक भी बच्चा नहीं मिला. जांच करने पर पता चला कि केंद्र संचालिका महीने के अंत में मनमाने तरीक़े से उपस्थिति दर्शाकर पंजीरी और अन्य खाद्य सामग्री ख़ुद हज़म कर जाती थी. इस अनियमितता और धांधली के लिए बतौर सज़ा इन दोनों केंद्रों की संचालिकाओं से तीन–तीन माह की पंजीरी एवं अन्य खाद्य सामग्री के मूल्य की रिकवरी के आदेश ज़िला कार्यक्रम अधिकारी दिनेश सिंह द्वारा दिए गए हैं.

शिकायत करने की बात पर केंद्र संचालिकाओं का जवाब होता है कि उन्हें पर्याप्त मानदेय नहीं मिलता और जो मिलता है, वह देर–सबेर और ख़ुशामद के बाद मिलता है. ऐसे में पुष्टाहार को बेच देना उनकी मजबूरी है. केंद्रों में अव्यवस्था का आलम यह है कि टाट–पट्टी तक सही सलामत नहीं हैं, फर्स्ट एड किट का कोई अता–पता नहीं है. बच्चे आएं न आएं, केंद्र संचालिकाओं को कोई परेशानी नहीं, उनका काम तो चल रहा है. सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतने बड़े पैमाने पर धांधली होती है और कोई देखने वाला नहीं है.

बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं के लिए शुरू की गई इस योजना का यह हाल सिर्फ़ कानपुर में नहीं है, पूरे प्रदेश की यही स्थिति है. शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, अमरोहा, सहारनपुर, अलीगढ़, बदायूं, हाथरस, पीलीभीत, बुलंद शहर, आगरा, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, मेरठ, बाग़पत, मुजफ्फ़रनगर, फ़ैज़ाबाद, बलरामपुर, गोंडा, लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच, इटावा, रायबरेली, अमेठी, हमीरपुर, फ़तेहपुर, बांदा, फ़र्रुख़ाबाद, कौशांबी, राबर्ट्सगंज, गोरखपुर, वाराणसी और सोनभद्र आदि ज़िलों में भी हालत काफ़ी ख़राब है. बच्चों–गर्भवती/धात्री महिलाओं का स्वास्थ्य सुधारने के लिए दिया जाने वाला पुष्टाहार दुधारू पशुओं की सेहत सुधार रहा है. यह सरकारी पुष्टाहार बाज़ार में सहज उपलब्ध है, जिसे पशुपालकों द्वारा ख़रीदा जाता है. गाय और भैंसों की दूध देने की क्षमता बढ़ाने के लिए पशुपालक उन्हें यही पुष्टाहार खिला रहे हैं. सोनभद्र, अलीगढ़ और गोरखपुर में ऐसी शिकायतें मिलने पर आंगनवाड़ी संचालिकाओं के ख़िलाफ़ कार्यवाही भी हो चुकी है. वाराणसी एवं मिर्ज़ापुर के ग्रामीण इलाक़ों की अधिकांश महिलाओं को तो यह भी नहीं मालूम कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर उनके और बच्चों के लिए पुष्टाहार की भी व्यवस्था है. सोनभद्र में पुष्टाहार की एक बोरी पांच सौ रुपये में बिकती है. यही हाल राबर्ट्सगंज का है, यहां पुष्टाहार की खेप आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचते–पहुंचते आधी हो जाती है. कौशांबी में पशुपालक हमेशा इसी ताड़ में लगे रहते हैं कि कब केंद्रों पर पुष्टाहार उतरे और कब वे अपना उल्लू सीधा करें. पक्के भोजन के लिए आवंटित होने वाला राशन तो अफ़सरों के पेट में चला जाता है. पात्र बच्चे–महिलाएं सरेआम वंचित रह जाते हैं.

शिकायत करने की बात पर केंद्र संचालिकाओं का जवाब होता है कि उन्हें पर्याप्त मानदेय नहीं मिलता और जो मिलता है, वह देर–सबेर और ख़ुशामद के बाद मिलता है. ऐसे में पुष्टाहार को बेच देना उनकी मजबूरी है. केंद्रों में अव्यवस्था का आलम यह है कि टाट–पट्टी तक सही सलामत नहीं हैं, फर्स्ट एड किट का कोई अता–पता नहीं है. बच्चे आएं न आएं, केंद्र संचालिकाओं को कोई परेशानी नहीं, उनका काम तो चल रहा है. सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतने बड़े पैमाने पर धांधली होती है और कोई देखने वाला नहीं है. सब कुछ राम भरोसे! बिजनौर, बहराइच, बदायूं, सीतापुर, लखीमपुर और इलाहाबाद में भी यही हाल है. कई जनपदों में आंगनवाड़ी संचालिकाओं और सहायिकाओं को पिछले कई महीने से मानदेय ही नहीं मिला. प्रतापगढ़, गोरखपुर, कानपुर, इटावा, रायबरेली, अमेठी, हमीरपुर, फ़तेहपुर और बांदा में करोड़ों रुपये इस योजना के तहत आवंटित हो रहे हैं, लेकिन पुष्टाहार बच्चों–महिलाओं के स्थान पर जानवर खा रहे हैं. मेरठ में कार्यकर्ताओं के आधे से ज़्यादा पद ख़ाली हैं, लेकिन भर्ती नहीं हो रही है. मुरादाबाद में इस पद पर भर्ती के लिए जमकर मनमानी हुई. बुलंद शहर का भी यही हाल है. सहारनपुर, मुजफ्फ़रनगर एवं आगरा में पुष्टाहार को लेकर आएदिन हाय–तौबा मची रहती है. हाथरस में सवा लाख बच्चे और 90 हज़ार महिलाएं पंजीकृत हैं, लेकिन ज़्यादातर इलाक़ों में लोगों को इस योजना की जानकारी ही नहीं है. हॉट कुक्ड भोजन के लिए पैसा तो आवंटित हो रहा है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई कुछ और है. बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर और अमरोहा में भी यही हाल है. कहने का मतलब यह कि बच्चों–गर्भवती/धात्री महिलाओं का हक़ हर जगह मारा जा रहा है. तुर्रा यह कि उचित मानदेय नहीं मिलता और समय पर नहीं मिलता, जबकि सच तो यह है कि केंद्र संचालिका को 2500 और सहायिका को 1000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है और केंद्र के किराये के रूप में 750 रुपये अलग. अधिकांश केंद्र तो कार्यकर्ताओं ने अपने घर पर ही खोल रखे हैं. पल्स पोलियो अभियान और अन्य सर्वेक्षण कार्यों के लिए अलग से भत्ते की व्यवस्था है.

m_awdhesh@chauthiduniya.com

यमुना अब नाला हो गई है

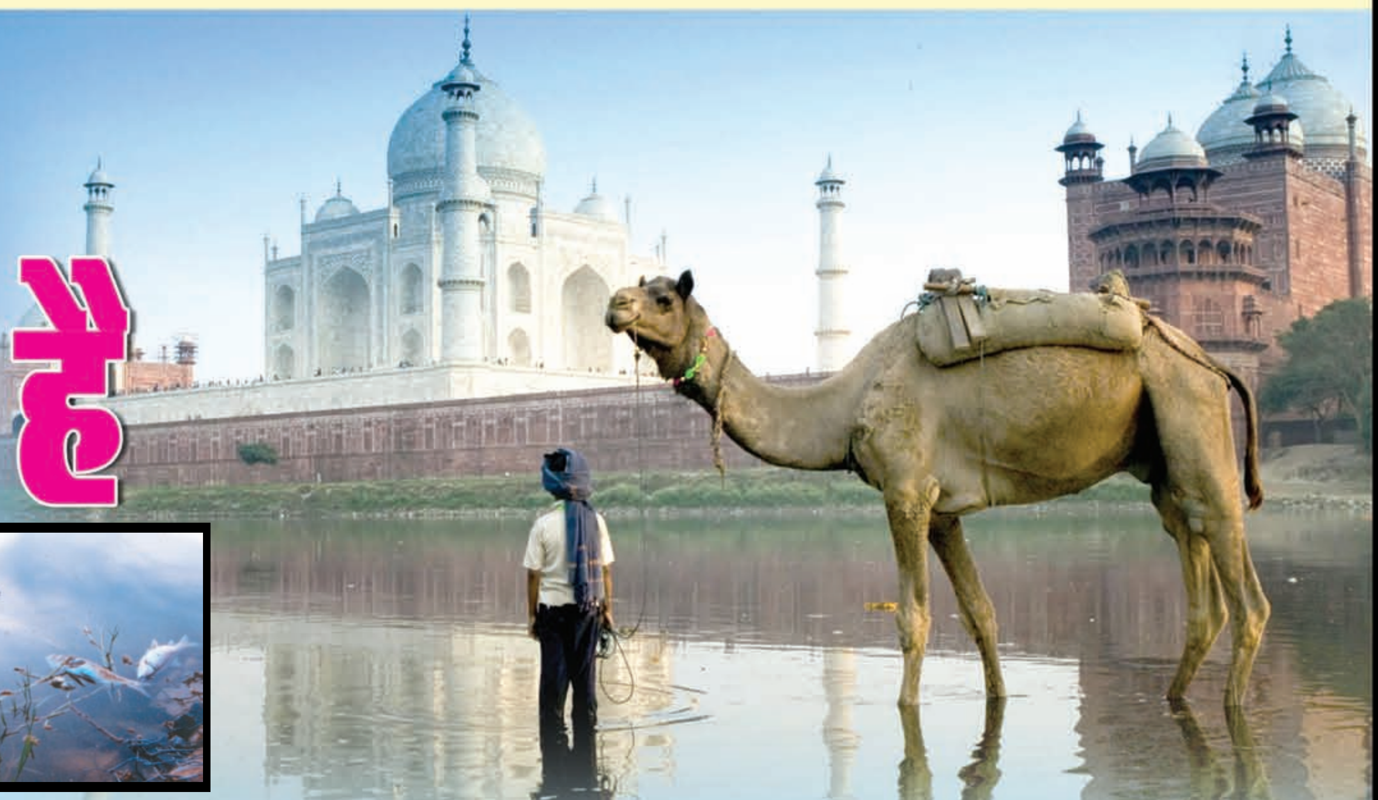

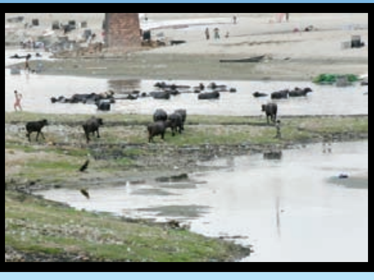

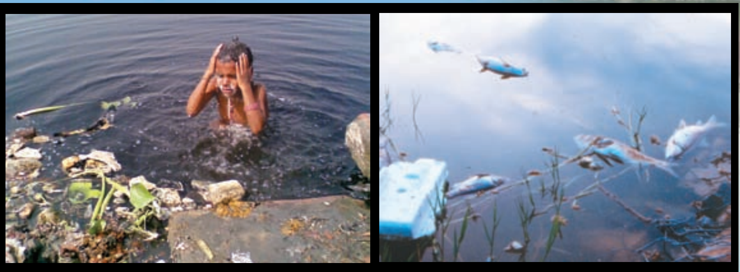

नदियों की सफ़ाई की बात आए दिन होती ही रहती है और उनकी सफ़ाई पर करोड़ों रुपये ख़र्च भी होते हैं. इसके बावजूद आजतक नदियां साफ़ तो नहीं हो पाईं, लेकिन दिनोदिन और गंदी ज़रूर होती जा रही हैं. उनमें प्रदूषण का आलम यह है कि नदियों का पानी पीने की बात तो छोड़िए, नहाने के योग्य भी नहीं रहा. यमुना की बात करें तो यह नदी हरियाणा तक तो अपने प्राकृतिक रूप में दिखाई देती है, लेकिन इसके बाद दिल्ली तक इसका रूप निरंतर विकृत होता चला जाता है. नदियों में प्रदूषण का मामला कई दशक पूर्व से ज़ोर–शोर से उठ रहा है. 15 साल पहले केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया था, लेकिन सालों से इसकी संचालन समिति की कोई बैठक नहीं हुई, जबकि इसकी हर तीन महीने में बैठक होनी चाहिए. पिछले 10 सालों में 20 राज्यों की 38 प्रमुख नदियों के संरक्षण और उन्हें प्रदूषण मुक्त करने के नाम पर 26 अरब रुपये ख़र्च किए गए, लेकिन स्थिति में कोई ख़ास बदलाव नहीं आया. यमुना नदी की गंदगी दूर करने के लिए दिल्ली सरकार अब तक 4000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा ख़र्च कर चुकी है, लेकिन इससे यमुना की गंदगी दूर करने वालों ने अपनी गंदगी भले ही दूर कर ली हो यमुना का प्रदूषण तो घटने के बजाय दिन पर दिन बढ़ा ही है. सबसे चिंताजनक बात यह है कि यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा इतनी अधिक हो गई है कि इसे साफ़ करना जलशोधक संयंत्रों के बस की बात भी नहीं रह गई है. यही नहीं अमोनिया के साथ अन्य घातक रसायन भी पानी में ज़हर घोल रहे हैं.

दरअसल पिछले कई दशकों से औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के कारण प्रमुख नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है. सिंचाई, पीने के पानी, बिजली तथा अन्य उद्देश्यों के लिए पानी के अंधाधुंध इस्तेमाल से चुनौती काफ़ी बढ़ गई है. नदियां नगर निगमों के शोधित एवं अपशिष्ट एवं औद्योगिक कचरे से प्रदूषित होती हैं. सभी बड़े एवं मझोले उद्योगों ने तरल अपशिष्ट शोधन संयंत्र लगा रखे हैं और वे सामान्यत: जैव रसायन ऑक्सीजन रसायन मांग (बीओडी) के निर्धारित मानकों का पालन करते हैं. हालांकि कई औद्योगिक क्षेत्र देश के कई हिस्सों में प्रदूषण को काफ़ी बढ़ा देते हैं. प्रदूषकों की उपस्थिति के आधार पर प्रमुख रूप से तीन प्रकार का प्रदूषण होता है–वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण. जल प्रदूषण अपशिष्टों के सीधे जल में मिलने के कारण भी होता है और वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषण के कारण वर्षा के द्वारा भी. नगर निगम अपशिष्ट के मामले में ऐसा अनुमान है कि प्रथम श्रेणी के शहर (423) और द्वितीय श्रेणी के शहर (449) प्रतिदिन 3,30,000 लाख लीटर तरल अपशिष्ट उत्सर्जित करते हैं, जबकि देश में प्रतिदिन तरल अपशिष्ट शोधन की क्षमता 70,000 लाख लीटर है. अपशिष्ट पदार्थों के शोधन का काम संबंधित नगर निगमों का होता है. जब तक ये निगम प्रशासन पूर्ण क्षमता तक अपशिष्टों का शोधन नहीं कर लेते तब तक डीओबी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता.

पिछले दिनों मैगसेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह ने जल के महत्व पर बोलते हुए चेतावनी दी थी कि यदि हालात न बदले तो अगला विश्वयुद्ध पानी के लिए ही होगा. इसलिए हमारे राजनीतिज्ञों को पानी बचाने और नदियों को पुनर्जीवित करने पर ध्यान देना चाहिए. गंगा–यमुना बचाओ को सिर्फ़ सरकारी ढकोसला बताते हुए उन्होंने कहा कि इन नदियों की सेवा मां के भाव से करने की ज़रूरत है. आदिकाल से गंगा–यमुना को हम मां कहकर पुकारते आए हैं, लिहाज़ा इससे बेटे के तौर पर ही जुड़ना होगा. गंगा और यमुना की सफ़ाई के लिए हमें इसके दर्शन और दृष्टि को समझने की ज़रूरत है. उन्होंने नीर, नारी और नदी के सम्मान को ही विकास का मूल मंत्र बताया. यमुना में आज दिल्ली के बाद हमें जो पानी दिखाई देता है वह पानी नहीं, बल्कि सीवर की गंदगी है. यमुना से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है. यमुना में स्नान या आचमन करना तो दूर कृषि कार्य योग्य पानी भी नहीं बचा है. इसके लिए ज़रूरी है कि दिल्ली और हरियाणा का औद्योगिक कचरा, सीवर की गंदगी और नालों का यमुना में गिरना बंद हो. संतों, बुद्धिजीवियों, किसानों, महिलाओं व अन्यों द्वारा पूर्ण मनोयोग से विगत माह इलाहाबाद के संगम से शुरू किया गया यमुना बचाओ आंदोलन हमें आशा की किरण दिखाता है. यमुना का प्राकृतिक स्वरूप हमें फिर देखने को मिले, यही आशा है. इन प्रतिष्ठित लोगों ने अपनी पद यात्राओं से लेकर यमुना को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिज्ञाएं और आमरण अनशन तक चलाया, यह निश्चय ही सराहनीय क़दम है. इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है. पहली बार देखने में आया है कि संत और किसान किसी समस्या के समाधान के लिए एकजुट होकर सड़कों पर निकले. जल है तो हमारा कल है. जल के बिना सबकुछ शून्य है. भले ही यह देर से उठाया क़दम था, लेकिन यह भविष्य के लिए निश्चय ही मील का पत्थर साबित होगा.

डॉ. नरेश चंद्र भारद्वाज
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया बिहार झारखंड

दिल्ली, 16 मई–22 मई 2011 | www.chauthiduniya.com

"संजीवनी का है ऐलान, झारखण्ड-बिहार में हो सबका मकान"

Website : sanjeevanibuildcon.in

AISHWARIYA RESIDENCY
Argora-Kathalmore Road, Ranchi
PLOT 6 LAC | DUPLEX 18 LAC

SANJEEVANI HIGHWAY
Ranchi Patna Highway Road
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

THE DYNASTY
Sidhu Kanhu Park, Kanke Road
PLOT 13 LAC | DUPLEX 25 LAC

SANJEEVANI TOWNSHIP
4 Lane, Kanke Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

9973959681
9471356199
9431190351
9472727767
9471527830

सियासी तलवारें चलने लगीं

सरोज सिंह

बिहारी सियासत में राजपूत क्षत्रप का दर्जा हासिल करने की होड़ मची है. पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह के असामयिक निधन और प्रभुनाथ सिंह के अपने ही गढ़ सारण में पराभव के बाद क्षत्रिय राजनीति में खालीपन का अहसास तो स्पष्ट रूप से होता है. जातीय राजनीति के बूते राजनीतिक सौदेबाज़ी करने की काबिलियत हासिल करने वाले बाहुबली आनंद मोहन कृष्णैया हत्याकांड में सजायाफ्ता हो पुराने रुतबे को याद कर जेल में बिसुरने को विवश हैं. इसके बाद कुछेक दिग्गजों को छोड़ क्षत्रिय राजनीति में मसखरों का बोलबाला हो गया. जो सियासी हस्तक्षेप की हैसियत नहीं रखते हैं. चिरौरी और चापलूसी के बूते स्वार्थसिद्धी तक ही इनकी राजनीतिक औकात सीमित है. लिहाजा, महानायकों की जातिगत पहचान को भुनाने की परंपरा चल पड़ी. यह रोग यूं तो कमोबेश सभी जातियों के राजनीतिक प्राणियों में पाई जाती है. लेकिन राजपूत समाज के कतिपय सियासी दिग्गज इस हथकंडे का बख़ूबी इस्तेमाल करते हैं. पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह ने नीतीश कुमार के विरोध में शंखनाद महाराण प्रताप जयंती समारोह से किया था. हालांकि, इनके विरोध का गुब्बारा फूलने से पहले ही पिचक गया. पर, इस आयोजन में प्रभुनाथ सिंह के साथ क़दमताल करने वाले जदयू विधायक जयकुमार सिंह इस बार जदयू के द्वारा आयोजित बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती समारोह के मुख्य कर्ता धर्ता थे. यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उन्हें चतुर सुजान बताने से नहीं चूके. अपने संबोधन के दौरान खुलेआम मंच से उन्होंने कुंवर सिंह सेवा समिति के संयोजक जय कुमार सिंह को चतुर बताया. फिर स्पष्ट भी किया– विजयोत्सव समारोह के एक दिन पूर्व ही आयोजन कर उन्होंने पक्का जुगाड़ कर लिया कि केवल उनके समारोह की ही ख़बर कुंवर सिंह जयंती के दिन छपे. जयंती के दिन तो अनेक संगठनों के कार्यक्रम प्रकाशित होंगे. हालांकि, इस प्रशंसा के निहितार्थ कुछ अलग भी है. प्रभुनाथ सिंह से पाला बदल इन्होंने नीतीश कुमार की शागिर्दी क़बूल करने में तनिक भी हिचक नहीं दिखाई थी. क़ाबिलेग़ौर है कि तब प्रभुनाथ सिंह के साथ क़दमताल करने वाले बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन के पुराने शार्गिद सोनवर्षा के पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना इतनी चतुराई नहीं दिखा पाए. पिछले चुनाव में नीतीश कुमार की सरदारत न कबूल करने के कारण वह दोबारा विधायक बनने से वंचित रह गए. जयकुमार सिंह एक और मामले में माहिर साबित हुए. भोजपुर–शाहाबाद इलाक़े में कुंवर सिंह के नाम पर राजनीति के अघोषित ठेकेदार बाहुबली जदयू नेता सुरेंद्र सिंह माने जाते थे. पिछले विधानसभा चुनाव में बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में उनकी पत्नी के पराजय के बाद से उनका इक़बाल कमज़ोर हुआ है. मौक़े का फ़ायदा उठा जयकुमार सिंह ने वह थाती हथिया लिया. जदयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के ख़ास सिपहसालार बन बैठे हैं जयकुमार सिंह. इस आयोजन में जदयू के मुख्य प्रवक्ता विधान पार्षद संजय कुमार सिंह, प्रदेश जदयू अनुशासन समिति के अध्यक्ष विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, विधान पार्षद विनोद सिंह, प्रदेश महासचिव राजकुमार सिंह, छोटू सिंह, फतुहा से विधानसभा चुनाव में हारे अजय कुमार सिंह इस आयोजन में ख़ासे सक्रिय थे. माना जाता है कि आगामी विधान परिषद एवं राज्यसभा चुनाव के नज़रिए से यह आयोजन शक्ति प्रदर्शन का भी सुनहरा अवसर था. प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, प्रदेश महासचिव राजकुमार सिंह, फतुहा से चुनाव हारने वाले अजय कुमार सिंह और राजद से आये छोटू सिंह आदि का नाम इस फ़ेहरिस्त में शामिल है. प्रदेश महासचिव छोटू सिंह ने 251 किलो की विशालकाय माला पहनाकर मुख्यमंत्री व अन्य का अभिनंदन कर अपनी मंशा प्रकट कर दी. छोटू सिंह कहते हैं कि जदयू व नीतीश कुमार के लिए वह हर कुर्बानी देने को तैयार हैं. उधर, आरा की पार्टी सांसद मीना सिंह की अनुपस्थिति चौंकाने वाली थी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी स्मृति में हार्डिंग पार्क का नाम बाबू वीर कुंवर सिंह पार्क करने की घोषणा की. जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि जदयू के स्वास्थ्य प्रकोष्ठ द्वारा विजयोत्सव के मौक़े पर हर वर्ष प्रत्येक ज़िले में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा. उधर, भाजपा के समारोह में कोइलवर पुल को बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर रखने की घोषणा कर दी गई. दिलचस्प है कि वह पुल जंग–ए–आज़ादी के महान योद्धा अब्दुल बारी के नाम समर्पित है. लिहाज़ा, इससे बेमतलब विवाद खड़ा होगा.

भाजपा की ओर से अगले दिन ही वहां वीर कुंवर सिंह का जन्मोत्सव मनाया गया. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार हरिहर सिंह के पुत्र भाजपा के वरिष्ठ विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह और विधान पार्षद राजवंशी सिंह इस आयोजन के मुख्य कर्ता–धर्ता थे. वहीं इस क्रार्यक्रम में बतौर राष्ट्रीय नेता पूर्व पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को बुलाना भी महज संयोग नहीं है. वह भी राजपूत समुदाय से आते हैं. इस वर्ग से आने वाले दो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह और राधामोहन सिंह ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. राज्य सरकार में भाजपा कोटे से इस बिरादरी के दोनों मंत्री जनार्दन सिंह सिग्रिवाल और रामाधार सिंह भी ख़ासे सक्रिय थे. लेकिन जातीय चश्मे से ही देखें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी, पूर्णियां के पार्टी सांसद उदय सिंह, विधायक संजय टाइगर, राणा गंगेश्वर सिंह आदि कई दिग्गज कार्यक्रम में नहीं दिखे.

पार्टी सूत्रों की माने तो प्रदेश मंत्री निवेदिता सिंह, पूर्व मंत्री कामेश्वर सिंह, सिकंदर सिंह विधान पार्षद बनने की तमन्ना पाल इस कार्यक्रम में ख़ासे सक्रिय थे. राजपूत मतदाता राजद लोजपा के भी प्रमुख आधार वोटर रहे हैं. लेकिन चुनावी हार के बाद से इन दलों के होश–उड़े हुए हैं. राजद के राजपूत समुदाय से आने वाले प्रमुख दिग्गज नेताओं पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह और जगदानंद सिंह पार्टी में समर्थ नेताओं के रूप जाने जाते रहे हैं. दलीय सुप्रीमो लालू प्रसाद भी उनकी राय को कभी यूं ही दरकिनार नहीं कर सकते थे. लेकिन सत्ता सुख के चक्कर में जुबान पर स्वयं ताला लटका लिया था. परिणाम जगज़ाहिर है. सब कुछ लुट जाने के बाद बेलाग लपेट बेबाक विचार व्यक्त कर रहे हैं. लिहाज़ा इन पर अब पछताय होत क्या, जब चिड़ियां चुग गईं खेत बख़ूबी चरितार्थ होता है. रघुवंश प्रसाद सिंह गत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने को दुर्भाग्यपूर्ण क़रार देते हैं. क़ाबिलेग़ौर है कि लोकसभा चुनाव के समय जब गठबंधन को अंतिम रूप दिया जा रहा था, उस वक़्त उन्हें सांप क्यों सूंघ गया था! इसी तरह लालू प्रसाद के कुकृत्यों पर पर्दा डालने में अव्वल जगदानंद सिंह को पार्टी की चुनावी हार के बाद उनमें ख़ामियां नज़र आ रही हैं. लालू प्रसाद के ख़िलाफ राजद विधान पार्षद नवलकिशोर यादव के बयान के बाद कथित तौर पर उन्हें दल से निकालने का निर्देश पार्टी सुप्रीमो ने दिया था. लेकिन बतौर पार्टी अनुशासन समिति के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कथित तौर पर ऐसा करने से इंकार कर दिया. दबाव बनाने पर पद छोड़ने की भी धमकी दे डाली. शायद यह सदशयता पहले आ जाती तो देश, प्रदेश के साथ पार्टी का भी भला होता. उधर, जदयू से आये पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह पूरी तरह निष्क्रिय हैं. वहीं उनके राजद में आगमन से उनके धुर विरोधी सांसद उमाशंकर सिंह भी परिदृश्य से ओझल हैं. वहीं लोजपा में विधायक दल के पूर्व नेता महेश्वर सिंह ही पार्टी फोरम पर दिखते हैं. वहीं दिग्गज बाहुबली पूर्व विधायक रामा सिंह चुनावी पराजय के बाद गधे के सिर से सींग की तरह ग़ायब हो गए हैं. लिहाजा इन दलों में कुंवर सिंह जयंती सादे समारोह में रस्म अदायगी तक ही सीमित रही. चींटी वहीं नज़र आती है जहां चीनी की गुंजाइश दिखती है. राजद–लोजपा में कुंवर सिंह के नाम पर बवाल मचाने से कुछ मिलना तो था नहीं.

बहरहाल, कुंवर सिंह के व्यक्तित्व पर ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने लिखा है, इस बूढ़े राजपूत ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अद्भुत वीरता और आन–बान के साथ लड़ाई लड़ी. यह गनीमत थी कि युद्ध के समय कुंवर सिंह की उम्र अस्सी के क़रीब थी. अगर वह जवान होते तो शायद अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता. विदेशियों ने कुंवर सिंह को पहचान लिया. लेकिन उनके बिरादरी वाले उन्हें जातीय परिधी से आगे नहीं जाने देते हैं. ग़ौरतलब है कि कुंवर सिंह के सिपहसालारों में करीम शाह, पीताम्बर शाही, निशान सिंह, देवकी दुबे, पीर अली, रंजीत अहीर, याहिया खां, अली करीम, किशुन कोइरी, नंदा कहार समेत सभी जाति के लोग थे. ऐसे में उन्हें जाति का नायक करार देना क्रूर मज़ाक है.

feedback@chauthiduniya.com

भोजपुर शाहाबाद इलाक़े में कुंवर सिंह के नाम पर राजनीति के अघोषित ठेकेदार बाहुबली जदयू नेता सुरेंद्र सिंह माने जाते थे. पिछले विधानसभा चुनाव में बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में उनकी पत्नी की पराजय के बाद से उनका इक़बाल कमज़ोर हुआ है. मौक़े का फ़ायदा उठाकर जयकुमार सिंह ने वह थाती हथिया ली. जदयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के ख़ास सिपहसालार बन बैठे हैं जयकुमार सिंह.

एक नज़र

शक्तिपात दीक्षा आंतरिक दिव्यता का जागरण है : मां विजया

प्रत्येक मनुष्य दिव्य है. वह असीम ऊर्जा से भरा और दिव्य शक्तियों से जुड़ा है, किंतु संसार के माया रूपी मल और अज्ञानता के आवरण से उसकी दिव्यता ढकी रहती है. ऊर्जा के उसके असीम भंडार के द्वार पर ताला जड़ा रहता है. एक सक्षम आध्यात्मिक गुरु अपनी शक्तियों से इच्छुक श्रद्धालुओं को इन्हीं माया रूपी मल या आवरण का नाश कर इनकी सुसुप्त दिव्यता को जागृत कर सकता है. इस्सयोग की शक्तिपात दीक्षा वस्तुत: मानव की इसी आंतरिक दिव्यता के जागरण की क्रिया है. यह बातें विश्व समादृत आध्यात्मिक संस्था अंतरराष्ट्रीय इस्सयोग समाज के तत्वाधान में इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च, बेइर के सहस्त्राब्दि सभागार में आयोजित शक्तिपात दीक्षा कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन देती हुई संस्था की अध्यक्ष एवं ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुमाता मां विजया ने कहीं. उन्होंने कहा कि इस्सयोग की सूक्ष्म और सहज किंतु अत्यंत शक्तिशाली आंतरिक साधना पद्धति, कोई व्यायाम अथवा क्रिया नहीं, अपितु इन सबसे अलग और ऊपर तथा सर्व सामान्य के लिए भी सहज प्राप्त है. यह किसी संप्रदाय अथवा समुदाय के पूर्वाग्रह से भी ग्रस्त नहीं, बल्कि शुद्ध आध्यात्मिक क्रिया है, जो साधकों को सीधे ब्रह्मा से जोड़ती है. इसके पूर्व सद्गुरुमां ने विभिन्न ज़िलों से आए दो हज़ार से अधिक नव जिज्ञासुओं को इस्सयोग की साधना की दीक्षा प्रदान की. संस्था के संयुक्त सचिव डॉ. अनिल सुलभ ने बताया कि विशिष्ट शैली में अखंड भजन-कीर्तन से आरंभ हुए इस कार्यक्रम का समापन प्रसाद वितरण के साथ हुआ.

-चौथी दुनिया ब्यूरो

वैष्णवी ग्लोरी ऑफ इंडिया बनी

भारत की नन्हीं सी गुड़िया वैष्णवी को ग्लोरी आफ इंडिया अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया. यह पुरस्कार थाईलैंड के पूर्व उप प्रधानमंत्री एच ई कॉर्न डब्बाश्नसी के हाथों थाईलैंड की राजधानी बैंकाक के प्रसिद्ध होटल होली डे इंटरनेशनल इन में प्रदान किया गया. छपरा ज़िला निवासी कृष्ण कुमार वैष्णवी व नूतन गुप्ता की पुत्री वैष्णवी ने मात्र 10 वर्ष की उम्र में कई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पाकर न सिर्फ़ ख़ानदान का नाम रोशन किया है, बल्कि अपने गृह राज्य बिहार सहित संपूर्ण भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया है. सम्मान समारोह के अंतरराष्ट्रीय मंच पर गायत्री मंत्र का उच्चारण कर जहां भारत के अध्यात्म को दर्शाया, वहीं भारतीय नृत्य कर इस नन्हीं सी गुड़िया ने भारतीय संस्कृति का जलवा विखेर दिया. माता का जागरण के माध्यम से विशेष पहचान क़ायम करने वाली वैष्णवी दो दर्जन से अधिक अलबमों, धारावाहिकों और सैकड़ों स्टेज-शो कार्यक्रम से दर्शकों का दिल जीत चुकी है. इतना ही नहीं पिछले साल रिलीज फिल्म जय मईया अम्बे भवानी और बीए पास बहुरियां और इस साल रिलीज फिल्म में नागिन तू नगीना में अपनी अभिनय क्षमता का बेजोड़ उदाहरण भी पेश कर चुकी है.

-विजयेंद्र कुमार

नाराज़ उपभोक्ताओं ने सड़क जाम की

बिजली की अनियमित आपूर्ति से परेशान खगड़ियावासियों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया है. लगभग एक सप्ताह पूर्व भी खगड़ियावासियों ने जगह-जगह सड़क जाम कर अपना विरोध जताया था. बावजूद इसके व्यवस्था में सुधार नहीं होने से नाराज़ लोगों ने एक बार फिर नियमित बिजली आपूर्ति के लिए न केवल जमकर प्रदर्शन किया, बल्कि जगह-जगह सड़क जाम कर आवागमन बुरी तरह प्रभावित कर दिया. बिजली उपभोक्ताओं का कहना है कि एक तो बिजली नहीं रहने के कारण लोगों का जीना मुहाल है, ऊपर से बिना बिजली दिए ही अनाप शनाप बिजली बिल भेजे जा रहे हैं. इसलिए न केवल बिजली व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, बल्कि अनाप शनाप बिल भेजना भी बंद किया जाना चाहिए. इतना ही नहीं ज़िले में कम से कम सोलह घंटे बिजली की व्यवस्था नहीं की गई तो आंदोलन चलता रहेगा. जाम का समर्थन नगर परिषद अध्यक्ष मनोहर कुमार यादव ने भी किया. मौक़े पर चंद्रशेखर कुमार, धर्मेंद्र कुमार, अरूण कुमार ठाकुर आदि उपस्थित थे.

- सूर्यनारायण भारती

साइबर कैफे वाले लोगों का अमन चैन लूट रहे हैं

ज़िला मुख्यालय स्थित दो दर्जन से अधिक साइबर कैफे अवैध रूप से चल रहे हैं. इस कारनामे के प्रति ज़िला शिक्षा विभाग एवं ज़िला प्रशासन भी उदासीन रवैया अपनाता है. परिणामस्वरूप अक्सर इन साइबर कैफे की अप्रिय वारदातें चर्चा में आ जाया करती है. पिछले दिनों कई ऐसे केंद्रों पर अभिभावकों एवं कैफे के संचालकों में ग़लत तौर तरीक़ों को लेकर तू तू-मैं मैं होते देखी गई. चूंकि पहुंचवाले लोगों के परिजन इन साइबर कैफे के व्यवसाय से लाभान्वित होते हैं, इसलिए जब कभी कोई मामला आगे बढ़ता भी है तो उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है. युवा पीढ़ी में पढ़ाई के साथ-साथ कमाई की ललक भी हिलकोरे मारती है. इसलिए जाने-अनजाने में कई मुश्किलें खड़ी होती हैं, जिससे अभिभावक भी मुंह मोड़े रहते हैं.

-चौथी दुनिया ब्यूरो

PATALIPUTRA SCHOOL OF FIRE & SAFETY MANAGEMENT

Estd. 2000

- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, which is Govt. of India registered, Regd. No. 03-09284 of 2000-2001.
- ISO 9001:2000 certified, Regd. No. CCPL/QMS/C1487
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where Practicals are conducted.
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where one full paper of 100 marks on petroleum is taught.
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where students of Industrial Safety Management Course of
- Patna University & Magadh University get Practical Training.

FREE Demo-Classes in the Morning & Evening from Monday to Friday

Excellent Placement with Handsome Salary

Website : www.psfsm.com

410, Ashiana Galaxy, Exhibition Road, Patna-800 001

Ph : 0612-6455019, Mob. : 9334107607, 9835042835, 9234729075

उद्योगों की क़ब्रगाह

सरकारी अव्यवस्था के कारण बक्सर उद्योगों का क़ब्रगाह बनकर रह गया है. चालू होने से पहले ही एक-एक औद्योगिक इकाइयां रूग्ण हो गई हैं. इसके साथ ही सरकार के करोड़ों रुपये डूबे और उद्यमी भी कंगाल हो गए.

सुशासन की सरकार में नई औद्योगिक नीति से जगी आस भी धूमिल हो गई. बड़े पैमाने पर इकाइयों का आवंटन रद्द करने तथा नए लोगों को आवंटित करने के बाद आज तक एक भी औद्योगिक इकाई चालू नहीं हो पाई. अधिक हुआ तो कुछ लोगों ने वहां राइस मिल का धंधा शुरू कर दिया. केंद्र सरकार ने 1974 में बक्सर को उद्योग विहीन ज़िला घोषित कर यहां उद्योग लगाने की योजना स्वीकृत की. लगभग 50 एकड़ ज़मीन की व्यवस्था कर 91 उद्योगों को लगाने की स्वीकृति दी गई. इसमें आर्युवेदिक तथा एलोपैथिक दवा, प्लास्टिक, सीमेंट, ऑटोपार्ट्स गेट-ग्रील होजियारी, केमिकल, जूता-चप्पल, पाइप कोल्ड स्टोर आदि उद्योगों को स्थापित किया गया. इसके लिए पटना औद्योगिक क्षेत्र में विकास प्राधिकरण द्वारा ज़मीन आवंटित की गई तथा बिहार राज्य वित्त निगम द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया, लेकिन स्थापना के साथ ही मनमानी तथा धांधली का दौर शुरू हो गया. वित्त निगम तथा बैंकों द्वारा उद्यमियों को टुकड़ों में लोन दिया गया. किसी को भवन के लिए मिला तो किसी को मशीन के नाम पर लोन मिला, जैसे-तैसे उद्यमियों ने रुपयों की व्यवस्था कर उद्योगों को खड़ा किया, लेकिन उद्योग चलाने के लिए कार्यशील पूंजी नहीं दी गई. कुछ लोगों ने शुरू भी किया तो बिजली तथा कच्चे माल तथा पूंजी के अभाव में पिछड़ गए. विद्युत विभाग तथा सेलटैक्स विभाग की मनमानी और बिजली संकट से उद्योगों पर ऐसा ग्रहण लगा कि उद्यमी अपंग हो गए. वहीं बियाडा ने भी अपनी करतूत दिखानी शुरू कर दी अर्थात विभिन्न विभागों के नौकरशाहों ने बक्सर औद्योगिक क्षेत्र का बेड़ा ग़र्क कर दिया और एक-एक कर औद्योगिक इकाइयां शुरू होने के बाद भी मृत हो गईं. 1990 में वित्त निगम भी कंगाल हो गया और इद्यमी लाखों के मालिक बनकर ख़ाकपति बन गए. बियाडा द्वारा मनमानी ढंग से उद्योगों को रूग्ण घोषित कर दूसरे व्यक्ति को शेड आवंटित किया गया. इस खेल में उद्यमियों के लाखों फंस गए. हाईकोर्ट तक मुक़दमेबाज़ी भी हुई. उद्यमी विनोधर ओझा कहते हैं कि वियाडा की धांधली अभी बंद नहीं हुई है. सुशासन सरकार की नई औद्योगिक नीति भी भेदभावपूर्ण है. पुराने उद्यमियों को पुनर्वास तथा संरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई. वहीं बक्सर ज़िला उद्यमी संघ के अध्यक्ष बृज किशोर सिंह कहते हैं कि सरकार द्वारा तीन इकाइयों को चालू करने की शर्त पर आज़मगढ़ के एक व्यक्ति को कौड़ी के मोल बेच दिया गया. आज तक एक भी उद्योग चालू नहीं हुआ और उसका क्रैप बेच कर लाखों की कमाई की गई. सिंह कहते हैं कि बक्सर औद्योगिक क्षेत्र को कलस्टर सेंटर घोषित कर देने से उद्यमियों को सुविधा मिलेगी, क्योंकि आसपास 60-70 राइस मिल हैं तथा धान का उत्पादन क्षेत्र भी है.

> विद्युत विभाग तथा सेलटैक्स विभाग की मनमानी और बिजली संकट से उद्योगों पर ऐसा ग्रहण लगा कि उद्यमी अपंग हो गए. वहीं बियाडा ने भी अपनी करतूत दिखानी शुरू कर दी अर्थात विभिन्न विभागों के नौकरशाहों ने बक्सर औद्योगिक क्षेत्र का बेड़ा ग़र्क कर दिया और एक-एक कर औद्योगिक इकाइयां शुरू होने के बाद भी मृत हो गईं.

इसी प्रकार करोड़ों रुपये की लागत से बनी नया भोजपुर की ग्लेज्ड टाइल्स मिल भी चालू होने से पूर्व ही कबाड़ख़ाना बन गई. करोड़ों रुपये की मशीन ज़ंग खाकर बेकार हो गई. हद तो यह है कि बड़े पैमाने पर मिल की मशीन, पार्ट, दरवाज़ा खिड़की करकट आदि की चोरी कर इसे खंडहर बना दिया गया. यहां के लोग चालू कराने के लिए धरना प्रदर्शन कर थक गए, लेकिन परिणाम ढाक के तीन पात साबित हुआ. इन उद्योगों की स्थापना से बड़े पैमाने पर नियोजन की संभावना भी क्षीण हो गई. उद्योगों का जाल बिछाने की घोषणा करने वाली सुशासन सरकार की नज़रें इनायत अब तक नहीं हुई हैं.

जयमंगल पाण्डे
feedback@chauthiduniya.com

एनसीईआरटी की पुस्तकों के लिए मारामारी

अभिभावक बेहाल फ़र्ज़ी प्रकाशक मालामाल

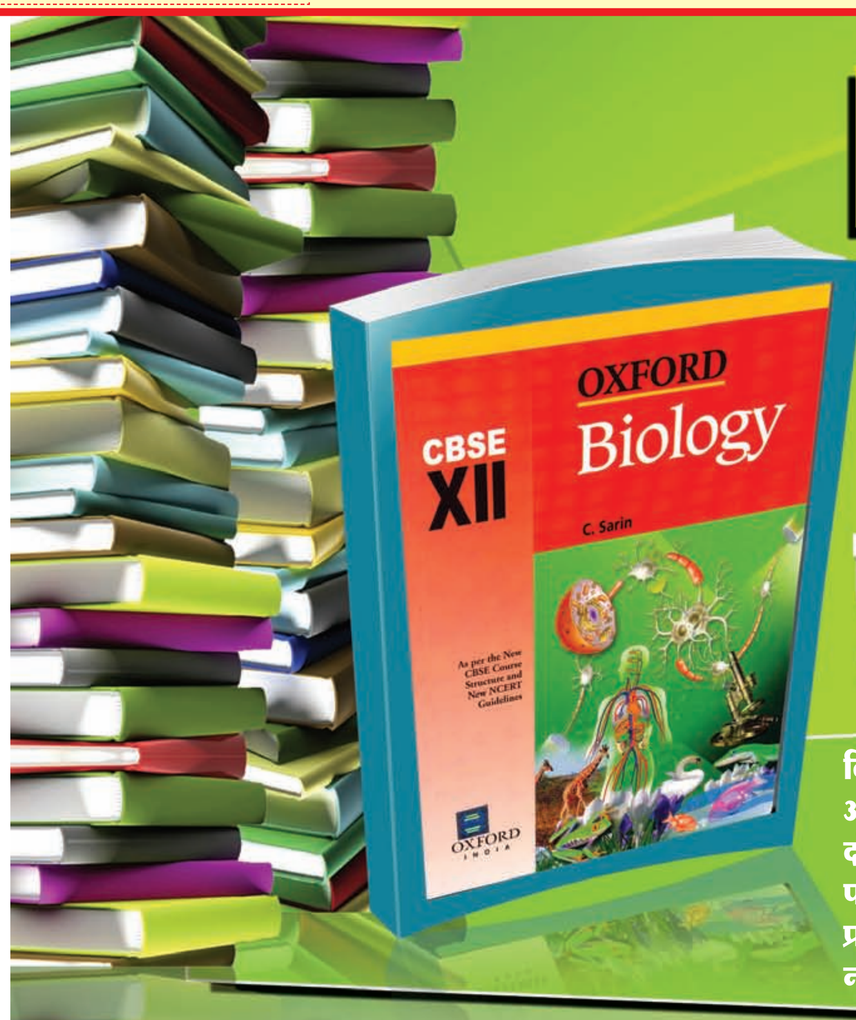

बिहार के मगध प्रमंडल के पांच ज़िलों में क़रीब पचास से अधिक स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हैं, जिनमें क़रीब दो दर्जन स्कूल गया ज़िले में ही हैं. नया सत्र शुरू होते ही पहली कक्षा से लेकर बारहवीं तक के सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को समय से पुस्तकें न मिलने पर पढ़ाई समुचित ढंग से शुरू नहीं हो पाती है.

एन सी ई आर टी
NCERT

सुनील सौरभ

बिहार में नया शैक्षणिक सत्र एक अप्रैल से शुरू हो चुका है. बच्चे नई क्लास में चले गए हैं. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में चलने वाली एनसीईआरटी तथा सीबीएसई की पुस्तकें नहीं मिल पा रही हैं. बच्चे और अभिभावक परेशान हैं तो शिक्षक भी मुश्किल में हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए. पर्याप्त मात्रा में कोई वस्तु बाज़ार में हो और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर न मिले और वही चीज़ अधिक राशि पर उपलब्ध रहे तो इसे कालाबाज़ारी कहते हैं, लेकिन जब उपभोक्ताओं की संख्या भी मालूम हो और वस्तु को उपलब्ध कराने के सारे संसाधनों के बावजूद वस्तु उपलब्ध न हो तो इसे क्या कहा जाए. ऐसी ही स्थिति है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रकाशित पुस्तकों की. पूरे देश में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में उक्त दोनों संस्थाओं से प्रकाशित पुस्तकें ही पढ़ाई जाती हैं. स्कूल संचालक विभिन्न क्लासों में अन्य प्रकाशकों की पुस्तकें भी अपने-अपने हिसाब से चलाते हैं, लेकिन दसवीं तथा ग्यारहवीं में तो पूर्णत: एनसीईआरटी तथा सीबीएसई की पुस्तकों से ही पढ़ाई होती है, क्योंकि दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षा में इन्हीं की पुस्तकों से सवाल पूछे जाते हैं. बिहार के मगध प्रमंडल के पांच ज़िलों में क़रीब पचास से अधिक स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हैं, जिनमें क़रीब दो दर्जन स्कूल गया ज़िले में ही हैं. नया सत्र शुरू होते ही पहली कक्षा से लेकर बारहवीं तक के सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को समय से पुस्तकें न मिलने पर पढ़ाई समुचित ढंग से शुरू नहीं हो पाती है. एनसीईआरटी या सीबीएसई से प्रकाशित कई पुस्तकें तो आधा सत्र समाप्त हो जाने के बाद आ पाती हैं. ऐसा होने से फ़र्ज़ी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित इन संस्थाओं से प्रकाशित पुस्तकों का फ़र्ज़ी संस्करण लेना मजबूरी हो जाता है. सीबीएसई द्वारा दसवीं के लिए प्रकाशित अंग्रेजी की पुस्तक लिटरेचर रीडर का रिवाईज संस्करण प्रकाशित किया गया है. इस पुस्तक पर छपी प्रतियों की संख्या डेढ़ लाख है, जबकि एक अनुमान के अनुसार पूरे देश में सीबीएसई की दसवीं बोर्ड की परीक्षा में इससे कई गुना अधिक बच्चे शामिल होते हैं. इस संबंध में जब जानकारी ली गई तो पता चला कि एनसीईआरटी और सीबीएसई के पदाधिकारी कैपिटल, नाईस तथा अन्य कई नामों के प्रकाशकों से मिलीभगत कर फ़र्ज़ी या डुप्लिकेट पुस्तकों को ख़रीदने के लिए बच्चों या अभिभावकों को लाचार कर देते हैं. फ़र्ज़ी या डुप्लिकेट पुस्तकें सीबीएसई और एनसीईआरटी की पुस्तकों की तुलना में मंहगी दर पर बिकती हैं तथा इसमें अधिक फ़ायदा खुदरा विक्रेताओं को भी होता है. गया शहर के सबसे पुराने और प्रमाणिक पुस्तकों के विक्रेता साहित्य सदन के अजीत अग्रवाल कहते हैं कि सीबीएसई के पदाधिकारी दसवीं या बारहवीं की परीक्षा और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के समय नए सत्र में जानेवाले बच्चों के लिए पुस्तक वितरण में रुचि नहीं लेते हैं. उन्होंने बताया कि इन पुस्तकों की अनुपलब्धता के मुख्य तीन कारण हैं. पहला यह कि प्रकाशित पुस्तकों को समय पर उपलब्ध न कराना, समुचित मात्रा में उपलब्ध न कराना तथा वितरण की व्यवस्था का सुचारू न होना. इसके लिए जब सीबीएसई के कार्यालय के टेलीफोन नंबर 011- 22509252 पर संपर्क करने का प्रयास किया गया तो बात नहीं हो पाई. इस प्रकार जहां बच्चों की पढ़ाई के लिए अभिभावक पुस्तकें नहीं मिलने पर परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद एनसीईआरटी और सीबीएसई की प्रकाशित पुस्तकों के फ़र्ज़ी संस्करण छाप कर कुछ प्रकाशक मालामाल हो रहे हैं.

> एनसीईआरटी और सीबीएसई के पदाधिकारी कैपिटल, नाईस तथा अन्य कई नामों के प्रकाशकों से मिलीभगत कर फ़र्ज़ी या डुप्लिकेट पुस्तकों को ख़रीदने के लिए बच्चों या अभिभावकों को लाचार कर देते हैं. फ़र्ज़ी या डुप्लिकेट पुस्तकें सीबीएसई और एनसीईआरटी की पुस्तकों की तुलना में मंहगी दर पर बिकती हैं तथा इसमें अधिक फ़ायदा खुदरा विक्रेताओं को भी होता है.

feedback@chauthiduniya.com

पंचायत चुनाव में जाली नोट

चंपारण जाली नोट के कारोबार को लेकर जाना जाता रहा है. कभी दिल्ली और पंजाब जानेवाली ट्रेनों में जाली नोट के कारोबारी पुलिस के हत्थे छापामारी दौरान पकड़े जाते रहे हैं.

प्रो. अरविंद नाथ तिवारी

भारत नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि और गांधी की भूमि एक बार फिर जाली नोट की खपत के लिए चर्चा में है. अबकी बार जाली नोट की खपत दिल्ली और मुंबई के लिए बल्कि व्यापक स्तर पर चंपारण में हुए पंचायत चुनाव में हो रही है. पहली बार पंचायत चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने असली नोटों के संग जाली नोटों की खपत करके चुनाव लड़ना मुनासिब समझा है, जिसकी चर्चा दबी जुबान मतदाताओं में है. मतदाताओं ने जब जाली नोट की बात प्रत्याशियों के सामने लाई तो प्रत्याशियों का यह टका सा जवाब होता है कि क्या करेंगे काका असली और नक़ली में अब फ़र्क़ कहां रह गया है.

जानकारी हो कि चंपारण जाली नोट के कारोबार को लेकर जाना जाता रहा है. कभी दिल्ली और पंजाब जानेवाली ट्रेनों में जाली नोट के कारोबारी पुलिस के हत्थे छापामारी दौरान पकड़े जाते रहे हैं. यहां के रहने वाले दिल्ली, पंजाब, असम में जाली नोट की खेप के संग पकड़े जाते रहे हैं. पकड़े जाने के बाद पूछताछ के लिए पुलिस यहां लेकर उन्हें आती रही है. अबकी बार जाली नोट के धंधेबाज़ दिल्ली, पंजाब का रुख़ कम करके चंपारण में जाली नोट सहजता से खपाने के फेर में लगे हुए हैं. पंचायत का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी असली में नक़ली नोट की मिलावट करके चुनाव लड़ रहे हैं. असली में नक़ली नोटों की मिलावट करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि वे पैसे के मामले में पहले से जीते हुए प्रतिनिधियों का सामना नहीं कर पा रहे हैं. इसलिए बहुत प्रत्याशी असली नोट में जाली नोट की मिलावट करके चुनाव लड़ लेना होशियारी समझ रहे हैं. बताया जा रहा है कि मुखिया लोगों को सरकार की तरफ़ से वित्तीय अधिकार मिलने के कारण अबकी बार मुखिया का चुनाव सभी प्रत्याशियों के लिए लड़ना काफ़ी महंगा पड़ रहा है. जाली नोट से चुनाव लड़ने का जब मामला सामने आया है तो लोग दंग रह गए. प्रत्याशियों द्वारा दिए गए रुपये में जाली नोट की बात जब सामने आई तो प्रत्याशी कह रहे हैं असली में जाली आ गया होगा. अब तो बैंक में जाली नोट निकल रहे हैं. चंपारण के बगहा रजवटिया, ठकराहा, आदापुर, बड़गो, पीपरासी, संतपुर सोहरीया, रामनगर भावल आदि पंचायत में जाली नोट की मिलावट करके चुनाव लड़ने की बात उभरकर लोगों के सामने आई है. वैसे चंपारण में जाली नोट का धंधा चोरी से तो अरसे पहले से चल रहा है, किंतु पुलिस को इसका पुख्ता प्रमाण नहीं मिल रहा था. सन 2008 में जाली नोट का मामला उजागर हुआ. 14 दिसंबर 2008 को पंजाब पुलिस ने होशियारपुर में बेतिया के चार लोगों को जाली नोट के संग गिरफ्तार करके बेतिया में लेकर आई तब यह सनसनी फैल गई. बेतिया के जिन लोगों को पंजाब पुलिस पकड़कर लाई थी. उनका नाम था मोहन मुखिया पिता महराज मुखिया, बनारसी शाह पिता राजेंद्र शाह, बिहारी मुखिया पिता सूबा मुखिया रामायण मुखिया पिता घोड़ा मुखिया. इनके पकड़े जाने के बाद लोगों को यह विश्वास हो गया कि चंपारण में जाली नोट का कारोबार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है. गत वर्ष पुलिस ने 22 जनवरी 2010 को दिल्ली के बाटला हाउस से 6 धंधबाज़ों को पुलिस सत्यापन के लिए चंपारण लेकर आई. सभी रक्सौल निवासी थे. उनका नाम मूर्तिया, रज़ा हुसैन की पत्नी नूरजहां नवका टोला, शकील, सेराजुल अंसारी पत्नी नूरनेशा, रामगढ़वा बहुअरी, मंसूर मियां पुत्री शाहीन ख़ातून है. पुलिस ने 18 जून 2010 को नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पर 402 खड़ी डाउन सवारी गाड़ी से 93 हज़ार जाली नोट के संग भूअर अंसारी, मनोज सहनी को गिरफ्तार किया. सूत्रों की बात अगर मानी जाए तो नेपाल से सटे बिहार के लगभग सभी क्षेत्रों में जाली नोट का करोबार फैल चुका है. यक्ष प्रश्न यह उठता है कि सीमा पर भारतीय सुरक्षा के नाम पर सरकार प्रत्येक वर्ष अरबों रुपया ख़र्च कर रही है. इसके बावजूद जाली नोट का करोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

भ्रष्टाचार के साये में बिहार मदरसा बोर्ड

अशरफ़ अस्थानवी

बिहार की नीतीश सरकार न केवल भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान चला रही है, बल्कि सत्ताधारी दल अगला एमपी चुनाव भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ने का मिज़ाज बना चुका है. यह तस्वीर का पहला रुख़ है. तस्वीर का दूसरा रुख़ कुछ अजीब सा है. सरकार की विकासोन्मुखी योजनाओं की आड़ में ही भ्रष्टाचार फल-फूल रहा है. नीतीश कुमार को विकास पुरुष मानने वाली राज्य की मासूम जनता इस भ्रम में है कि नीतीश सरकार के सुशासन में बहुत बेईमानी या लूट-खसोट की गुंजाइश नहीं है. जनता की इसी मासूमियत का फ़ायदा भ्रष्ट पदाधिकारी और घूसखोर पदाधिकारी उठा रहे हैं. इस स्थिति की ताज़ा मिसाल बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड का पत्रांक 1442 दिनांक 11.04.2011 है. यह पत्र राज्य के 2460 मदरसों की प्रस्वीकृति से संबंधित है. राज्य के मानव संसाधन विकास विभाग के ज्ञापांक 162 दिनांक 15.02.2011 का हवाला देते हुए बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना एज़ाज अहमद ने पूरे राज्य के मदरसा शिक्षा व्यवस्था पर अपनी पकड़ बना ली है. मदरसा शिक्षकों और मदरसा संचालकों तक अप्रत्यक्ष रूप से यह संवाद पहुंचा दिया गया है कि मदरसों की प्रस्वीकृति संबंधी जांच प्रतिवेदन मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिवेदनों की समीक्षा कर प्रस्वीकृति की अनुशंसा सरकार से की जाएगी.

मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के निर्देश से राज्य के सभी ज़िला शिक्षा पदाधिकारियों को यह पत्र भेजा गया है और प्रस्वीकृति की कतार में खड़े मदरसों की जांच 5 बिंदुओं पर करके जांच प्रतिवेदन शीघ्र मदरसा बोर्ड को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. दूसरी ओर कुछ दलाल पूरे राज्य में फैल चुके हैं और सरकारी स्कूल के शिक्षकों के बराबर वेतनमान नव प्रस्वीकृति मदरसा शिक्षकों को झांसा देकर पैसे की उगाही के धंधे में जुट गए हैं. इसके लिए जगह-जगह मदरसा बेदारी कांफ्रेंस का आयोजन भी हो रहा है. मदरसा बेदारी कांफ्रेंस में नीतीश कुमार का भजन होता है. नीतीश कुमार को यह पैग़ाम देने की कोशिश की जाती है कि 2460 मदरसों के शिक्षक नीतीश कुमार को अपना मसीहा तस्लीम कर चुके हैं. मदरसा एजुकेशन बोर्ड बिहार राज्य की मदरसा शिक्षा को संचालित करने वाला एक महत्वपूर्ण संस्थान है. यह तय है कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड की कार्य संस्कृति जैसी होगी, उसी के अनुसार राज्य मदरसा शिक्षा व्यवस्था भी होगी. मदरसा एजुकेशन बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल तो हमेशा ही उठते रहे हैं, लेकिन अक्टूबर, 2008 से इसकी जो स्थिति है, उससे यही अंदाज़ा होता है कि राज्य की एनडीए सरकार मदरसा शिक्षा को ध्वस्त करने की रणनीति के अनुसार काम कर रही है.

मदरसा एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन एक ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है, जो प्राथमिक स्तर के मदरसे का शिक्षक है. प्रशासनिक अनुभव में शून्य. मदरसा बोर्ड का दफ्तर कुछ लोगों के लिए कमाई का केंद्र बनकर रह गया है. स्थिति का अंदाज़ा सिर्फ़ इसी से लगाया जा सकता है कि 14 मई, 2010 को विजीलेंस ने छापा मार कर चेयरमैन के प्राइवेट सेक्रेट्री एस. सादिक़ को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था और फिर जेल में भी ठूंसा था. सादिक़ के घर से 60 भर सोना, 8 लाख नक़द रुपये, 5 लाख की एफडी, दो एम्बेस्डर कार और करोड़ों की अवैध अचल संपत्ति के काग़ज़ात बरामद किए थे. प्राइवेट सेक्रेट्री चार महीने जेल में रहकर जबसे बाहर आए हैं तबसे चैयरमैन साहब उनपर और ज़्यादा मेहरबान हो गए हैं. सादिक़ को प्राइवेट सेक्रेट्री से मदरसा बोर्ड के कैडर में लाकर उन्हें असिस्टेंट सेक्रेट्री में प्रोन्नति दे दी गई है. केवल इतना ही नहीं उन्हें पूरे राज्य के मदरसों की स्थापना संबंधी कार्यों का प्रभारी बना दिया गया है.

बिहार के मुस्लिम समुदाय की एक बड़ी संख्या मूलभूत सुविधाओं से वंचित है. मुसलमानों की शैक्षणिक स्थिति को कमज़ोर करने में उनकी ग़रीबी का बहुत बड़ा हाथ है. एक तरफ़ सरकार द्वारा स्वीकृत या राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को छठा वेतन पुनरीक्षण का लाभ मिल रहा है, वहीं स्वीकृत मदरसों के शिक्षकों और कर्मचारियों को वित्तीय सहायता के नाम पर तीसरा वेतन पुनरीक्षण के आलोक में वेतन भुगतान किया जा रहा है. सेवानिवृति के बाद मदरसा शिक्षकों को एक पैसे का भी सहारा नहीं है. नीतीश सरकार में मदरसा, मदरसा शिक्षा और मदरसा शिक्षकों की बेहतरी के लिए बातें तो ख़ूब होती रहीं हैं, लेकिन इन बातों के अनुसार काम करने से हमेशा परहेज़ किया जाता रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

जूट उद्योग दम तोड़ रहा है

मनोज ठाकुर

बिहार के अन्य उद्योगों की तरह ही जूट उद्योग भी असामयिक मौत से जूझ रहा है. अब कोसी के कछार पर जूट की खेती नहीं की जाती. कटिहार शहर में अवस्थित एक सरकारी व दूसरी निजी जूट मिल सरकारी अनदेखी और आर्थिक विपन्नता के कारण बंद हो चुकी है. बाज़ार में अब प्लास्टिक के बोरे व रस्सियां उपलब्ध है. वह भी मंहगे बिक रहे हैं, लेकिन इस विषम परिस्थिति में भी लोगों में जूट के प्रति अथाह प्रेम है. कोसी क्षेत्र के लोग मौजूदा दौर में भी जूट के बोरे का व्यापार करते हैं.

सहरसा शहर के बीच स्थित गंगजला मोहल्ला. यहां रहते हैं इंद्रदेव भगत! वह फटे बोरे का व्यापार करते हैं. इसे संयोग कहिए या कुसंयोग. बोरा जूट से बनता है. हालांकि वह बोरा बनाने का काम नहीं करते. वह तो सिर्फ़ बोरे का रफ़ू करते हैं. बाज़ार से 5 से 10 रुपये फटा बोरा ख़रीद कर इन बोरों की मरम्मत करते हैं फिर 11 से 12 रुपये के बीच बेच देते हैं. इस व्यापार में उनके ही अनुसार 50,000 से 1,00,000 तक की पूंजी लगी हुई है. इसके लिए उन्होंने 2 स्थाई नौकरों को रखा, अगर बोरे की मांग बाज़ार में बढ़ जाती है तो उन्हें नौकरों की संख्या बढ़ानी पड़ती है. लाभ के नाम पर उनका यही कहना है कि उनका 5 सदस्यों का यापन इसी व्यापार से चलता है. व्यापार में फ़ायदा है, यही कारण है कि उन्होंने खेतीबाड़ी छोड़ दी.

इस व्यापार में इंद्रदेव भगत इकलौते नहीं है. सहरसा के कचहरी चौक पर कई लोग इस व्यापार में लगे हुए हैं. 500 से 1000 लोगों का यापन इसी व्यापार से चलता है. भगत के मुताबिक़ व्यापार का भविष्य अच्छा नहीं है. जूट मिल बंद पड़ी हैं, उत्पादन नहीं हो रहा है. उस पर से प्लास्टिक की मार भी इस व्यापार को खाए जा रही है, क्योंकि प्लास्टिक के बोरे बाज़ार में सिर्फ़ 2 रुपये में उपलब्ध हो जाते हैं. अगर पर्यावरण को ध्यान में रखा जाए तो जूट का बोरा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है. सरकारी ध्यान भी इस ओर जा रहा है. अब गुटखे प्लास्टिक निर्मित पैकेट में नहीं भरे जाएंगे. प्लास्टिक निर्मित पैकटों के रोक के लिए क़ानून बनाया गया है. हो सकता है कि जूट उद्योग का कायाकल्प हो जाए. हो सकता है इंद्रदेव भगत ख़ुश हो जाए, लेकिन भगत के लिए ज़िला उद्योग केंद्र के प्रबंधक एन.एन. राम के पास कुछ नहीं है. उनका कहना है कि वह या विभाग उत्पादन के लिए पूंजी मुहैया करवाती है, लेकिन बोरा मरम्मती का कारोबार उत्पादन की श्रेणी में नहीं आता. जब उनसे यह कहा गया कि इस तरह का प्रस्ताव तो वह सरकार के पास भेज सकते हैं, लेकिन उनका साफ़ कहना था कि वह इसके लिए असमर्थ हैं. ये बातें नीति से संबंधित हैं. कोसी क्षेत्र पूर्व में जूट उद्योग का केंद्र माना जाता था. थाईलैंड, मलेशिया आदि देशों को भेजे जाने वाले पदार्थ जूट के बोरे में भरकर भेजे जाते थे. कोसी के कटिहार, किशनगंज, पूर्णियां, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा ज़िलों में जूट (पटुआ) की सघन खेती की जाती थी. आज इस पटुए की खेती यहां नहीं की जाती है.

जूट उत्पादक बोरे में पैबंद लगा रहे हैं

जब इस बाबत राज्य की उद्योग मंत्री रेणु कुमारी से संपर्क साधने की कोशिश की गई तो उनके पी.ए. ने बताया मैडम एक सप्ताह दिल्ली से रहकर आई हैं. इसलिए मैडम अभी कोई बात नहीं कर सकती हैं. यह हाल है नीतीश के सुशासन के नुमांइदों का.

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

जेईई क्लासेज सरकारी स्कूल के बच्चों को छात्रवृत्ति देगा

जेईई क्लासेज अब सरकारी स्कूल के प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृति देगा. साथ ही साथ अन्य बच्चों को सस्ते दर पर मेडिकल व इंजीनियरिंग की शिक्षा उपलब्ध कराएगा. इसके लिए परीक्षा का अयोजन किया जाएगा. यह निर्णय सेमिनार में जेईई क्लासेज के प्रबंध निदेशक ए.एन. सिंह डीओ किरण कुमारी सहित लगभग एक सौ विद्यालयों के प्राधानाचार्य की बैठक में लिया गया. इसके लिए सरकार ने जेईई क्लासेज को आमंत्रित किया है. उधर, पटना की ज़िला शिक्षा अधिकारी किरण कुमारी ने कोचिंग संस्थान जेईई क्लासेज के सहयोग से मेधावी विद्यार्थियों को फ्री कोचिंग और स्कॉलरशिप दिलाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है.

क्षेत्र की समस्याओं से मेरा संघर्ष : अफ़रोज़

ज़िले के वारिस नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ज़िला परिषद् क्षेत्र सं.-32 में मथुरापुर, सारी, शेखोपुर, कुसैया, रामपुर बिशुन एवं धुरलख पंचायत के मतदाता इस बार ऐसे प्रतिनिधि की तलाश कर रहे हैं जो क्षेत्र को बाढ़-सुखाड़ की समस्याओं के साथ ही सड़क, चापाकल, नलकूप, इंदिरा आवास आदि समस्याओं से आम लोगों को राहत पहुंचाए. पिछले दो चुनाव जीत चुके निवर्तमान ज़िला पार्षद नंद किशोर चौधरी सहित कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें पिछली बार की तरह इस बार भी रामनरेश राय, गुफ़रान, एस. ए. इमाम भाग्य आज़मा रहे हैं, लेकिन अन्य नए मो. अफ़रोज़ आलम, तरूण सिंह, विनोद सिंह, राजू सिंह, सुनील राय, दीनबंधु राय एवं जयप्रकाश शर्मा ज़्यादा जोर आज़माइश कर रहे हैं. चुनाव में खड़े मो. अफ़रोज़ आलम का कहना है कि क्षेत्र के विकास के लिए दस वर्षों का मौक़ा कम नहीं है, बशर्तें जनप्रतिनिधि में विकास की इच्छाशक्ति हो, जिसमें मौजूदा ज़िला पार्षद पूर्णत: असफल रहे हैं.

-चौथी दुनिया ब्यूरो

B.M.T. LAW COLLEGE (AUTONOMOUS)

KAMLA BHAWAN, PURNIA, BIHAR

Website: www.bmtlawcollege.org Email: bmtlcautonomous@gmail.com, info@bmtlawcollege.org, admin@ bmtlawcollege.org

[Autonomous Status Granted by U.G.C , New Delhi Vide F. No. 221/June 2009(AC), Permanently Recognized by the Bar Council of India, New Delhi, A Permanent affiliated unit of B.N. Mandal University , Madhepura]

THE ONLY AUTONOMOUS COLLEGE IN BIHAR

B.M.T. Law College Purnia has been granted Autonomous Status from Academic Session-2009-10 by University Grant Commission, New Delhi. College develops its own Curriculum,Syllabi,Examination process and all-around Academic activities with the help of different committees like Board of studies,Finance committee,Academic council and Board of management as per the rules of U.G.C.Examination,Publication of result and Issuance of certificate has been made by college.The Final Degree will be awarded by University. This college is having well equipped infrastructure, like Administrative Block, Examination cell, Auditorium, Class Rooms, Yoga and Health Centre, Canteen, Women's Hostel, Examination Hall,huge Computer center,Audio-visual facility,modern E-resources and learning materials, Internet facilty, rich Computerized Library, surrounded by Pucca Wall. And having well adequate experienced faculty members.

Limited Seats ,Admission Process is going on...

Admission form is available for Academic Session- 2011-12

- LL.M- 2 Year Semester Course
- LL.B- 3 Year Semester Course
- B.B.A- 3 Year Semester Course
- B.A. LL.B 5 Year Double Degree Integrated Course

Cont. No:- 09135002159, 09431665242, 09608751601, 06454-244487